खण्ड-351, अंक-1
शनिवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1903
(28 मार्च, 1981 ई0)

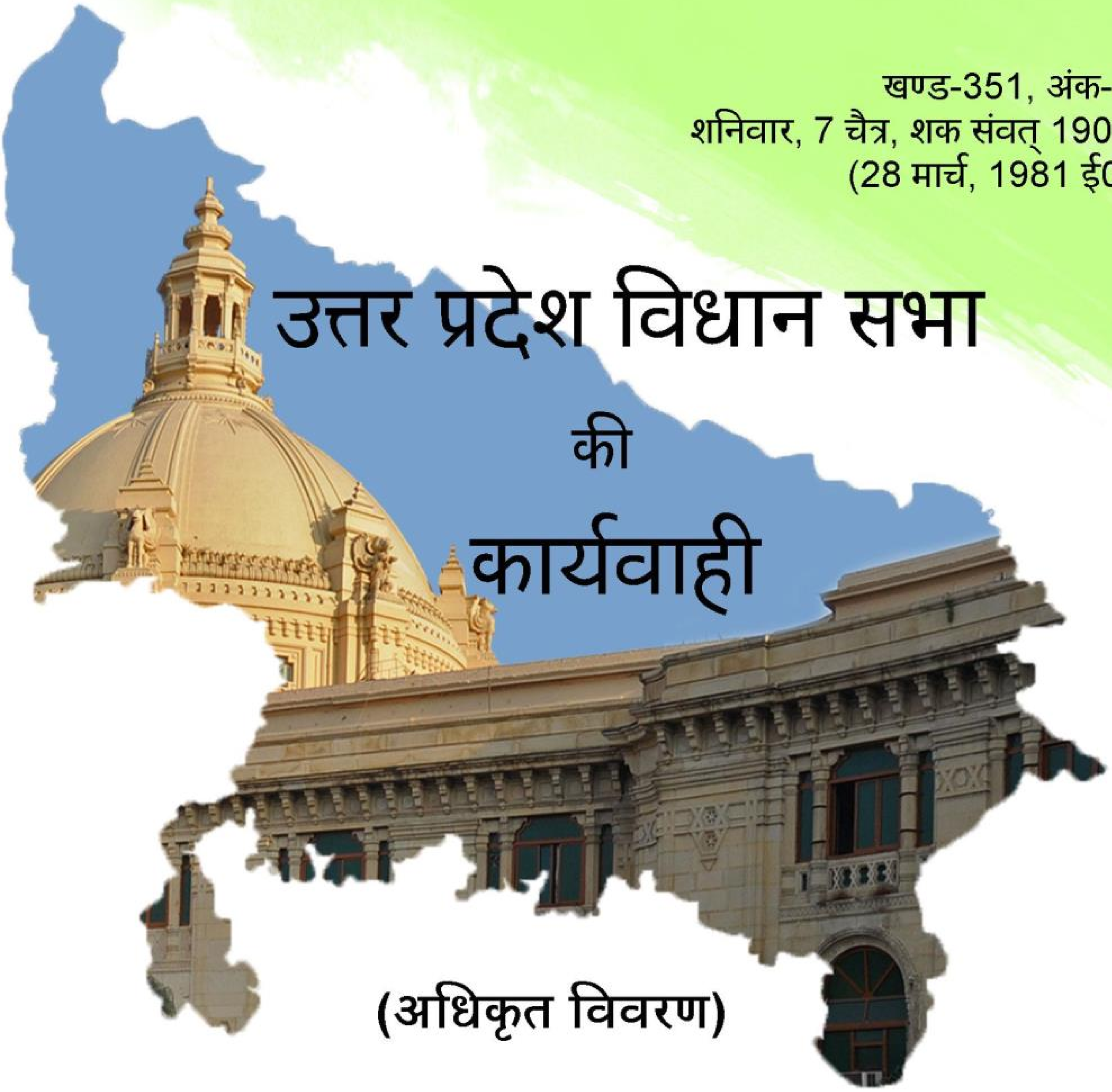

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 351 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–4
बरेली कालेज के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं उनकी गिरफ्तारी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	5
हमीरपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियंता, श्री दयाराम व अस्थायी खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, श्री हमीर सिंह के मध्य सरकारी आवास के मामले में विवाद के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	5–6
ग्राम मांहलिया, जिला बाराबंकी, निवासी श्री सादिक की सीतापुर के दरोगा, श्री दुर्गा प्रसाद अग्निहोत्री व सिपाही श्री ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	6–7
गाजीपुर जिला अस्पताल से श्री रामसरन लोहार की पत्नी का नवजात शिशु गायब कर दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	7
उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980 . . (वापस लिया गया)	8
श्री केदारनाथ सिंह द्वारा दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	8
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	8-9
लखनऊ में एक ही दिन में तीन हत्याएं व जालौन के चुर्खी थाने के एक दरोगा व कांसटेबिल की डाकुओं द्वारा हत्या के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	9–15
उत्तर प्रदेश जिला परिषद्, मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 .. (पुनः पारित)	16–17
1981–82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 50–पर्वतीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 87–पर्वतीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 117–पर्वतीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	17–68
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	68
मिर्जापुर के रिहन्द बांध में नाव डूब जाने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	68
आगरा में सेना के खतरनाक एवं दुर्लभ शस्त्रों का जखीरा पकड़े जाने के संबंध में 13 मार्च, 1981 को दिये गये वक्तव्य पर चर्चा	68–80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 301

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए. सी. ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपूर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)

जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' श्री (फैजाबाद)
जौराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जौराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
त्रिवनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (रामपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ मसरूर) (गोंडा)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)

माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वरनाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विदया सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद, तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)

विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ, उपाध्याय श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

संसदीय प्रदेश पीठ

[समय 11 बज कर 1 मिनट]

बरेली कालेज के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं उनकी गिरफ्तारी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 की 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि दिनांक 26 मार्च, 1981 को बरेली में बरेली कालेज के छात्रों पर पुलिस द्वारा निर्मम लाठीचार्ज किया गया। परिणामस्वरूप लगभग 50 छात्र घायल हुए। गम्भीर रूप से घायल छात्र नेता श्री वीरेन्द्र अटल तथा कुछ अन्य व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हैं। मान्यवर, यह भी सूचना मिली है कि घटना के बाद 200 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने भागते छात्रों को दौड़ा कर पकड़ा तथा पीटा होटल के भीतर बैठे निर्दोष छात्र भी पीटने से बख्शे नहीं गये।

मान्यवर, मामला यह है कि बरेली कालेज, बरेली छात्र संघ का चुनाव 31 मार्च को होना विज्ञापित हो चुका था। नामांकन पत्र दाखिल हो चुके थे, परन्तु इस दिन प्रातः समाचार-पत्रों में प्राचार्य की यह अधिसूचना प्रकाशित हुई कि चुनाव स्थगित कर दिये गए हैं। छात्रों को शिकायत थी, चुनाव स्थगन के लिये बहाना कोई भी हो परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि कालेज में प्रवेश के लिये काली सूची के एक छात्र को कालेज में एडमीशन देने के लिए सत्तारूढ़ दल के लोग प्राचार्य पर दबाव डाल रहे थे। प्रदेश सरकार के मंत्रियों तक ने रुचि ली थी। इस छात्र का प्रवेश मात्र इसलिए कराया जा रहा था कि यह चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो सके। मान्यवर, अन्त में प्राचार्य महोदय झुक गये और चुनाव मात्र इसलिए स्थगित हो रहा था कि काली सूची के छात्र का नाम लिखकर दुबारा चुनाव लड़ाया जा सके। इस घटना से कुपित होकर छात्र प्राचार्य कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।

लाठी चार्ज के लिए दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही न करने से छात्र अभी उत्तेजित हैं। कालेज 3 अप्रैल तक के लिये बंद कर दिया गया है।

अविलम्बनीय लोकमहत्व की इस सुनिश्चित घटना शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि सम्पूर्ण मामले की उच्चस्तरीय जांच हो, विद्यालय खोला जाय, घोषित समय पर छात्रसंघ के चुनाव हों, दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाय।

हमीरपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियन्ता, श्री दया राम व अस्थाई खंड के अधिशासी अभियन्ता श्री हमीर सिंह के मध्य सरकारी आवास के मामले में विवाद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन की संज्ञान में लाना अत्यन्त आवश्यक है।

हमीरपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियन्ता, श्री दया राम और अस्थाई खंड के अधिशासी अभियन्ता, श्री हमीर सिंह के बीच सरकारी आवास के लिए शुरू हुआ संघर्ष आज इस कदर बढ़ गया है कि न सिर्फ अधिकारियों के प्रति लोगों में सम्मान की भावना समाप्त होती जा रही है बल्कि सरकारी कामकाज पर उल्टा असर पड़ रहा है। बताया जाता है कि विवादित निवास प्रांतीय खंड सा0 वि0 वि0 का है और उसमें दया राम वैधानिक रूप से रह रहे थे। इसी बीच उन्होंने श्री हमीर सिंह को जिनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री यदुनाथ सिंह---]

कार्यक्षेत्र राठ में है परन्तु जिन्होंने अपना मुख्यालय यहीं बनाया हुआ है, उसी निवास के एक हिस्से में रहने की जगह दे दी। क्योंकि श्री दया राम का परिवार कानपुर में रहता है। इसलिए उस निवास का एक बड़ा हिस्सा श्री हमीर सिंह और उनके परिवार के कब्जे में आ गया है। उसी निवास में श्री हमीर सिंह ने जानवरों को बांधने के लिये एक अवैधानिक निर्माण भी कराया परन्तु श्री दयाराम की आपत्ति पर उसे गिरवा दिया गया। पुलिस में दर्ज रिपोर्टों के अनुसार श्री दया राम का कहना है कि उन्होंने श्री हमीर सिंह को अवैधानिक कार्यों के लिए मना किया इसलिए वह उनसे ईर्ष्या रखने लगे साथ ही वे पूरे निवास पर भी कब्जा करना चाहते थे और जब वे तीन दिनों के लिये एक आवश्यक बैठक में भाग लेने झांसी गये थे, तो अवसर पाकर हमीर सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ घर का ताला तोड़ दिया और वहां तैनात नौकरों को भी धमका कर भगा दिया। श्री दया राम ने एक सोने की अंगूठी, ट्रांजिस्टर और कुछ नकद रुपयों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। श्री दया राम के अनुसार हरिजन होने के कारण श्री हमीर सिंह नहीं चाहते कि वे उनके साथ रहें। ऐसी चर्चा उन्होंने कई बार अपने परिचितों में भी की श्री दयाराम के अनुसार जिला प्रशासन ने भी उनके रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की जिससे उत्साहित होकर श्री हमीर सिंह और उनके एक सहयोगी सहायक अभियंता, श्री जे0पी0 पांडेय तथा कुछ ठेकेदारों ने उन्हें नैतिक बल और सहयोग देने वाले एक जूनियर इन्जीनियर, श्री राम निवास को बुरी तरह मारा जिसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज करा दी गयी। श्री हमीर सिंह और उनके सहयोगियों के बराबर आक्रमण जारी रखने के बाद भी जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौन रही जिस से साबित होता है कि इनका समर्थन श्री हमीर सिंह को प्राप्त था। श्री दया राम ने विभागीय उच्चाधिकारियों को भी इस घटना की सूचना दी परंतु उन्होंने भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की उनके अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, श्री जे. सी. तायल ने अपने हमीरपुर आगमन पर श्री हमीर सिंह का मनोबल बढ़ाते हुये कहा कि तुमने कुछ नहीं किया मैं होता तो उसे (दया राम) दो-चार थप्पड़ मारता। सा0 नि0 वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, के हमीरपुर आगमन पर जूनियर इन्जीनियर्स महासंघ ने उनके समक्ष सहायक अभियन्ता, श्री जे0 पी0 पांडेय द्वारा जूनियर इन्जीनियर, श्री राम निवास को पीटे जाने के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किया। परिणाम स्वरूप श्री पांडेय को लिखित क्षमा याचना करनी पड़ी। श्री दया राम का आरोप है कि जब श्री हमीर सिंह का कार्य क्षेत्र राठ है फिर भी उन्होंने अपना मुख्यालय राठ से 60 कि0 मी0 दूर हमीरपुर में क्यों बनाया है इससे कार्यों का सही संचालन व देखरेख नहीं हो पाता है, इसके अतिरिक्त सरकारी साधनों का भी दुरुपयोग होता है।

इस लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाना अत्यंत आवश्यक है जिससे उक्त विवाद में उचित कार्यवाही की जा सके तथा श्री दया राम की रक्षा की जा सके।

ग्राम मोहलिया जिला बाराबंकी निवासी, श्री सादिक को सीतापुर के दरोगा श्री दुर्गा प्रसाद अग्निहोत्री व सिपाही श्री ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, दिनांक 13-3-81 की शाम 8 बजे सादिक निवासी ग्राम मोहलिया, थाना कुर्सी, जिला बाराबंकी को थाना सिधौली, जिला सीतापुर की पुलिस के दरोगा, श्री दुर्गा प्रसाद अग्निहोत्री व ठाकुर प्रसाद सिंह सिपाही घर पर शाहपुर निवासी राम चरण के द्वारा बुलाकर पकड़ ले गये और ससोना के पूरक एकवाग उन्हें केवल चार पांच पेड़ लगे हैं वहां पर ले जाकर पेड़ में रस्से से बांध कर निर्मम हत्या कर दी।

ग्राम मोहलिया, जिला बाराबंकी, निवासी, श्री सादिक की सीतापुर के दरोगा श्री दुर्गा प्रसाद अग्निहोत्री व सिपाही श्री ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मान्यवर, जिस बन्दूक से फायर किया गया बताते हैं वह बन्दूक सिधौली के मालखाने की बंदूक है उससे एक फायर नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अब ग्राम मोहलिया के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी फसल का काट रहे हैं और जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। मान्यवर, उक्त मृतक के एक बीवी तथा तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं।

मान्यवर, इस घटना से उक्त इलाके में भय व आतंक का वातावरण व्याप्त है। मैं आपके माध्यम से श्री सादिक की हत्या की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच तथा मृतक के परिवार की फसल की रक्षा तथा मृतक की बीबी बच्चे के लिये पांच हजार रुपया आर्थिक सहायता का माननीय मुख्य मंत्री जी के कोष से दिलाने की मांग करता हूं।

गाजीपुर जिला अस्पताल से श्री राम सरन लोहार की पत्नी का नवजात शिशु गायब कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नरायन--

मान्यवर, मैं सदन और सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। यह सरकार एवं मा0 मुख्य मंत्री जी रोजाना कानून एवं जन जीवन की सुरक्षा की प्रशस्ति करने में फूले नहीं समाते हैं। वर्तमान शासन में मासूम बच्चों की रक्षा एवं सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं के बराबर है। इसका ज्वलंत प्रमाण मैं अपने क्षेत्र के ग्राम लावा परगना व जनपद गाजीपुर के एक गरीब लोहार राम सरन, पुत्र श्री गोबर्धन की स्त्री को गाजीपुर महिला चिकित्सालय में 20-2-81 को पुत्र पेट के आपरेशन के बाद पैदा हुआ और चिकित्सालय के अधिकारीगण की खराब व्यवस्था एवं लेडी डाक्टरों एवं नर्सों एवं दाइयों के साजिश एवं लापरवाही के परिणाम-स्वरूप उक्त नव जात शिशु 23-2-81 को प्रातःकाल 7 बजे चिकित्सालय से गायब कर दिया गया और उक्त नवजात शिशु की मां आज भी उक्त चिकित्सालय में अपने शरीर की कमजोरी एवं आपरेशन एवं पुत्र के वियोग में विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई है। इसके पहले उसने कई बच्चों को जन्म दिया था परन्तु वे काल के गाल में जा चुके हैं और इस अपने ढलती उम्र में एक जीवन का सहारा उसे प्राप्त हुआ उसे भी आज की शर्मनाक सुरक्षा व्यवस्था ने उसे अपने एकमात्र पुत्र से सदैव के लिये वंचित कर दिया गया तथा उसका कुलदीप सदैव के लिये बुझ गया। उक्त दम्पति का आरोप है कि उसके पुत्र के सात हजार रुपये के बदले में महिला चिकित्सालय के कर्मचारीगण ने बेच दिया है। इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में भी खबर छपी है तथा संबंधित जिला प्रशासन को भी प्रार्थना-पत्र राम सरन लोहार दे चुका है। मुझे भी सारी घटना से अवगत कराया। मैंने भी जिला मुख्य चिकित्सालय अधिकारी एवं जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक; गाजीपुर से इस दर्दनाक घटना के बारे में बात की परन्तु आज तक कोई ठोस एवं प्रभावी कदम नहीं उठाया गया जिसकी वजह से क्षेत्रीय जनता में काफी असंतोष का वातावरण व्याप्त है कि स्त्रियों को प्रसव काल की भयंकर परेशानियों में कहां राहत प्राप्त होगी। जनपद में बच्चों के चुराने एवं भगाने का एक सक्रिय गिरोह कार्य कर रहा है घटना के पूर्व भी मोहम्मदाबाद कस्बा से एक पांच वर्ष का राजेश नाम का लड़का उक्त गिरोह का शिकार हुआ था जो दूसरे दिन वाराणसी शहर में बरामद हुआ।

अतः आप के माध्यम से मैं सरकार से इस दर्दनाक एवं शर्मनाक घटना की अविलम्ब जांच सी0 आई0 डी0 से कराने तथा संबंधित अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के विरुद्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980, जो उ0 प्र0 विधान सभा में दिनांक 16 सितम्बर, 1980 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 16 सितम्बर, 1980 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री केदार नाथ सिंह द्वारा दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में जानकारी की मांग

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, उसमें बता दें।

श्री अध्यक्ष---

आपने नियम 218 में दिया है, वह मंत्री जी को जाता है, इसलिये वह वहां गया है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इसमें से पहली सूचना श्री शंकर सिंह की दिनांक 27-3-81 को जालौन जनपद में थाना चुर्खी के अन्तर्गत ग्राम शिपरा शेखपुर के निकट दस्यु दल द्वारा पुर्वी थाना के थानाध्यक्ष, एक सब इन्सपेक्टर तथा एक सिपाही को मार डालने तथा उनके शस्त्र लेकर फरार हो जाने से उक्त जनपद की जनता में व्याप्त भय तथा आतंक के संबंध में यही सूचना श्री हरिबंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह की है। इसी विषय पर यह सूचना नियम 51 में भी प्राप्त हुई है। नियम 51 के समय इस पर विचार किया जायेगा जहां तक कार्य स्थगन की नियम 56 की सूचना का प्रश्न है यह अस्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की दिनांक 27-3-81 को अमीनाबाद, लखनऊ में गल्ला व्यापारी संघ के प्रचार मंत्री, श्री रमेश कुमार अग्रवाल की छुरा भोंक कर हत्या कर दिये जाने तथा घटना की रिपोर्ट अमीनाबाद थाने में दर्ज किये जाने से पुलिस द्वारा इन्कार करने तथा रिपोर्ट दर्ज करने हेतु गये व्यक्तियों के प्रति दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री हुकम सिंह की दिनांक 27 मार्च, 1981 को लखनऊ नगर के थाना अमीनाबाद, थाना कैसरबाग तथा नाका हिंडोला में तीन व्यक्तियों की निर्मम हत्या के फलस्वरूप समस्त नगर में असुरक्षा, भय तथा शोक की लहर उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है। यही सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री मोती लाल देहलवी, श्री कुबेर भण्डारी, श्री रियासत हुसैन तथा श्री राम गोबिन्द चौधरी की है।

आठवीं सूचना श्री सूबेदार सिंह एवं श्री यदुनाथ सिंह की दिनांक 27-3-81 को लखनऊ विधान सभा के समक्ष पिछड़ा वर्ग, हरिजन एवं अल्पसंख्यक युवा संघर्ष समिति के सदस्यों पर अपनी मांगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के फलस्वरूप पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने एवं तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के संबंध में है।

नवीं सूचना श्री फखरे आलम की दिनांक 26-3-81 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है। यह सारी सूचनायें नियम 56 में अस्वीकार की गईं और पहली सूचना जो श्री शंकर सिंह की है जिस पर वह कुछ कहना चाहते हैं नियम 51 के समय विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--
अभी कल ही हमने 130 करोड़ रुपया दिया है।

श्री अध्यक्ष--
आप बैठ जायं।

श्री शंकर सिंह--
मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर . . .

श्री अध्यक्ष--
नियम 51 में जब आयेगा तो . . .

श्री हुकम सिंह--
मान्यवर, सुन लें।

श्री अध्यक्ष--
आप बैठ जायं।

लखनऊ में एक ही दिन में तीन हत्याएं व जालौन के चुर्खी थाने के एक दरोगा व कांस्टेबिल की डाकुओं द्वारा हत्या के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आज मैंने और अन्य साथियों ने जो कार्य-स्थगन की सूचना दी है उस पर इस आदरणीय सदन में कार्यस्थगन के रूप में चर्चा होनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि कल उस समय जब सदन में शान्ति और व्यवस्था पर बहस चल रही थी उसी समय नृशंस और निन्दनीय काण्ड उत्तर प्रदेश की राजधानी में होता है। यह शान्ति व्यवस्था को चुनौती है और उसका फर्दाफाश होता है इससे मान्यवर, मर्डर हो जाता है यह घटना इसलिये महत्वपूर्ण हो गई है कि ठीक 8 बजे दिन दहाड़े सड़क पर बीच रास्ते में जहां सैकड़ों लोग रहते हैं, 24 साल का नवयुवक पान की दुकान पर खड़ा था, उसको छुरा मार दिया गया और उसके घर वाले जब उसको रिक्शे से अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। यह गम्भीर इसलिये और हो जाता है कि जब उसके घर के लोग शुभ चिन्तक लोग 8-45 पर थाने में एफ0 आई0 आर0 लिखाने गये तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिसकी आप बड़ी प्रशंसा करते हैं, वहां डियूटी पर जो मुन्शी था उसने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और जो लोग गये थे, उनको डाटना शुरू कर दिया कि आप लोग बवाला बनाते हैं। थोड़ी देर में 2-3 हजार नागरिकों ने थाने को घेर लिया। वहां पर एस.एस.पी. और डी.एस.पी सिटी वहां पहुंचे, मुख्य मंत्री को भी इसकी जानकारी मिली और उन्होंने डी.एम. को फोन किया। एस0 एस0 पी0 वगैरह वहां पहुंचे और 10 बजे एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

सवा घंटे तक उन लोगों ने एफ. आई. आर. नहीं लिखी। मान्यवर, एक साल पहले उसी थाने की पुलिस ने, एक आदमी को मार डाला था, और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी। मान्यवर, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, वहां की शान्ति व्यवस्था का प्रभाव सारे प्रदेश पर पड़ता है। पूरा जनजीवन असुरक्षित हो गया है। कल कैसरबाग के थाने के पास एक मकान में जिसमें दरोगा किराये पर रहते थे उनके लड़के ने अपने मकान मालिक को छुरा भोंक कर मार दिया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। राजधानी में इस घटना से रोष व्याप्त है। हम चाहते हैं कि कार्य-स्थगन के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराइये।

*श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, कल शांति और व्यवस्था की जिस तरह से चर्चा हो रही थी उसका जीता जागता उदाहरण है कि उसी दिन एक आदमी को मारा जाता है और जब शहर के नागरिक रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जब तक थाने का घेराव नहीं किया जाता है तब तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स हम सुनते थे, लेकिन अब गुंडा टैक्स वसूल किया जा रहा है। मान्यवर, रमेश से गुंडा टैक्स वसूल करने लोग गये थे जब उसने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी जाती है और जब शहर ने नागरिक थाने जाते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और गुंडा टैक्स की वसूली की जा रही है, जो देने से मना करता है उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब शहर के नागरिक थाने जाते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। क्या प्रदेश की यही हालत रहेगी कि जब तक थाने का घेराव नहीं किया जायेगा रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी? मान्यवर, आखिर किस तरह से शासन चलेगा? मेरा आग्रह है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय और नहीं हो सकता। कत्ल होने के बाद, थाना 200 मीटर दूर है, इतना बड़ा काण्ड हो जाये और रिपोर्ट न लिखी जाय तो मेरा आग्रह है कि इस पर चर्चा करायें।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 घंटे के अन्दर उत्तर प्रदेश की राजधानी में 3 हत्यायें हो जाना यह बहुत गम्भीर चिन्ता का विषय है। मान्यवर, कल कानून और व्यवस्था पर माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो उससे लग रहा था कि आज से ही कानून और व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हो जायगा। इनकी पुलिस सतर्क हो जायगी बदमाशों को पकड़ने में और शांति व्यवस्था कायम करने में। ऐसा लगता था कि इनकी सरकार काफी सतर्क हो गयी है और यह घटनायें नहीं होंगी। लेकिन एक तरफ भाषण हो रहा था और दूसरी तरफ वारदातें हो रहीं थीं इसी लखनऊ में। मान्यवर, लखनऊ के नागरिक का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है उनको यह विश्वास नहीं रह गया है कि हम लखनऊ में सुरक्षित हैं। मान्यवर, थोड़े दिन पहले एक नौजवान जिसने पुलिस के पास जाकर तीन बार सुरक्षा की फरियाद की उसको, एस0 पी0 साहब के निवास के बगल में उसकी हत्या हो गयी और यहां की पुलिस उसे बचा नहीं सकी। एक दरोगा का लड़का मारा गया। तो इससे ज्यादा लज्जा और शर्म की बात नहीं हो सकती। यहां के नागरिक आतंकित और भयाक्रांत हो गये हैं। इसलिये जरूरी हो जाता है कि इस पर चर्चा हो। माननीय सदन के चलते रहते लखनऊ में 24 घंटे में 3, 3 लोग मारे जायं और पुलिस पकड़ न सके और रिपोर्ट लिखाने के लिये थाने का घेराव करना पड़े तो मान्यवर, आज दुकानें भी बन्द होंगी, यह बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय है। दुकानदार क्षुब्ध होकर हड़ताल करने जा रहे हैं। तमाम लखनऊ के लोग कम से कम आशा करते हैं कि हमारी सुरक्षा होगी लेकिन लखनऊ के अंदर सदन चलते रहते इस तरह की वारदातें हो रही हैं। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि लोगों में आस्था और विश्वास पैदा करने के लिये,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आपसे मेरा आग्रह है कि पुनर्विचार करें और आज इस पर विचार कर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, आज जो पुलिस द्वारा हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में आपकी पूरी सहायता की आवश्यकता है, जब मान्यवर, शहर में यह हाल है, जहां पर चौकी है, थाने हैं, कोतवालियां और तमाम पुलिस फौज है, तब खुलेआम इस तरह कत्ल हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोलें, उसी बात को दोहराइये नहीं।

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं कि यह हाल जब शहर का है, जहां सब कुछ मौजूद है, तो फिर गांवों का क्या हाल होगा, जहां कोई सुविधा समय से उपलब्ध नहीं होती। मान्यवर, जब शहर में इस तरह का आतंक फैला हुआ है और कोई सुनवाई नहीं है। (शोर)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इस घटना के संबंध में इसकी ग्राह्यता पर मुझे यह कहना है कि यह जो लखनऊ शहर में एक के ऊपर एक घटनाएं लगातार इधर कई दिनों से हो रही हैं, तो इससे साफतौर पर यही पता चलता है कि लखनऊ की पुलिस आपके कब्जे में नहीं है और दूसरी तरफ जैसा कि पेपर से मालूम हुआ कि पुलिस जवानों ने अपनी जानें कुरबान कर अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं, जिसमें एक इन्सपेक्टर, एक एस. आई. और एक सिपाही डाकुओं के मुकाबले में मारे गये। तो इस तरह यह जो राजधानी से दूर हैं, वह तो आपके आदेशों और अपने फर्ज को निभा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस लखनऊ में है, आपके सामने है, वह न तो आपके आदेशों का पालन कर रही है और न ही अपना फर्ज निभा रही है, बल्कि आपके आदेशों की अवहेलना कर रही है।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि यहां पर लखनऊ शहर में 3 वारदातें हो गयीं और सदन चल रहा है, सदन मान्यवर, किस बात के लिए चल रहा है, जबकि नागरिकों की हत्या इस तरीके से हो रही जहां पर आई. जी., मुख्य सचिव, गृह सचिव और माननीय मुख्य मंत्री जी आदि मौजूद हों, वहां पर इस तरह से दिन दहाड़े 3-3 हत्याएं हो जाएं, और उस पर यह कि सदन चलता रहे, किस लिए सदन चलता रहे? सिर्फ इसलिये कि बजट पास करते रहें। मान्यवर, जब नागरिक ही इस प्रदेश का सुरक्षित नहीं है, तो यह बजट किसके लिए पास किया जाए और पास करके करेंगे भी क्या, जब नागरिक ही नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि तमाम कार्यवाही स्थगित करते हुए, पहले इन घटनाओं पर चर्चा करायें, उसके बाद सदन की कार्यवाही चलाएं।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, हमारे यहां एक बड़ी जबर्दस्त घटना घटी, लेकिन उसके लिए अभी कुछ नहीं किया गया। इस घटना में 2 दरोगा मारे गये और एक सिपाही मारा गया। इसकी स्थिति मान्यवर, मैं आपको समझा दूं बेहमई ग्राम, जिला कानपुर में जमुना के उस पार पड़ता है और इस पार हमारा कालपी क्षेत्र, जनपद जालौन पड़ता है और तुर्की थाना ठीक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शंकर सिंह--]

बहमई के इस पार पड़ता है। जिसमें यह गांव शिमरा शेखपुर जमुना के किनारे पड़ता है। थानाध्यक्ष, सब-इन्सपेक्टर और सिपाही इसी ग्राम में किसी तफतीश के लिए जा रहे थे, डाकुओं ने इन लोगों पर घात लगाकर मार दिया, न कोई उनसे मुकाबिला हुआ और न कोई मुठभेड़। और मान्यवर, जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी 8 तारीख को वहां जा रहे थे, तो समाचार-पत्रों में बड़ा प्रचार किया गया कि मलखान सिंह का गैंग जनपद जालौन के ब्लौड़े गांव में 7 तरफ से घेर लिया है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के वापस आते ही यह समाचार डी.आई.जी. के लेबिल से निकला कि मलखान सिंह घेरा ही नहीं गया और जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी वहां से वापस हुए उसी दिन वहीं के पास के थाने आटा से एक आदमी का अपहरण हो गया। इसलिये मेरा निश्चित मत है कि पुलिस अध्यक्ष, जालौन का स्थानान्तरण तत्काल किया जाये, तभी दस्यु उन्मूलन में कामयाबी मिल सकती है, वरना इसी तरह आप नागरिकों को मरवाते रहिये। कल मान्यवर, जब यहां शांति और व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी, तब माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी फूलन देवी के नाम को लेकर सदन में दिल्लगी कर रहे थे, और जिस वक्त यहां फूलन देवी को लेकर दिल्लगी हो रही थी, उस वक्त पुलिस के तीन नव-जवान आखिरी सांसें गिन रहे थे।

आपने अपनी बात कह दी और मैंने सुन ली, कोई जरूरी है कि मैं आश्वासन दूं

"नसीमें शुभ गुलशन में गुलों से खेलती होंगी,
किसी की आखिरी सिसकी और किसी की दिल्लगी होगी।"

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, इस पर आप चर्चा का आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष--

आपने अपनी बात कह दी और मैंने सुन ली, कोई जरूरी है कि मैं आश्वासन दूं तभी आप बैठें?

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, स्थिति यह है- - - -

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, बिना नाम बुलाये आप बोलने के लिये खड़े हो गये हैं।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। मान्यवर, स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे विस्फोटक स्थिति जिला जालौन की है। जालौन में डकैत पनप रहे हैं, उन्हें पुलिस की ओर से प्रोटेक्शन मिल रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमको सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर बुन्देलखंड को बोलने का अवसर नहीं मिल सका है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस पर सदन में कम से कम दो घण्टे की चर्चा अवश्य हो ताकि सदन के सामने प्रदेश का मामला स्पष्ट किया जा सके कि जनपद जालौन में क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जाइये, यह आवश्यक नहीं है कि हर बार जब मैं बैठने को कहूं आप उसका उल्लंघन करें और बैठें नहीं।

*संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्यों ने पहले एक घटना पर ध्यान आकर्षित किया और कर रहे हैं, आज समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा। मैं कहता हूं कि जिस तरह से भी यह घटना हुई है जाने में या अनजाने में, इस बात की पूरी जांच कर लूंगा और इसकी पूरी जांच तत्परता के साथ करायी जायेगी, इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं दी जायेगी।

दूसरी बात चुर्खी के लिये जिला जालौन की बात कही गयी। इसमें जो सूचना प्राप्त हुई है मेरा कर्तव्य है कि आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को अवगत करा दूं कि 27 तारीख को ग्राम सुगबाग, सिमरा सैदपुर, जिला जालौन में पुलिस के लाल और श्री राम डकैतों के बीच मुठभेड़ में श्री काली राम और थानाध्यक्ष तथा श्री इन्द्रपाल, कांस्टेबिल चुर्खी वीरगति को प्राप्त हुए। पूरी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। यह बड़ी खेद की बात है कि हमारे तीन अफसर शहीद हो गये। सरकार की निगाहें पूरे प्रदेश में सजग हैं कि इस प्रकार के अराजक तत्व समाप्त हों और वे अपना सर न उठायें, इसका पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार इसमें पूरी तरह से तत्पर है। उनकी निगाहों में जो घटनायें हो रही हैं इसमें सबका सहयोग मिलना चाहिये क्योंकि यह कोई राजनैतिक या दलगत वाली बात नहीं है। मैं समझता हूं कि तीन व्यक्ति जो शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रध्दांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं माननीय सदस्यों से जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, कि वे भी मेरी इस बात से सहमत होंगे ।

(शोर)

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने और जोर-जोर से बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय केदार नाथ सिंह जी, आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया इस पर एक दो स्पष्टीकरण की आप अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष—

जो सूचना लखनऊ के तीन हत्या कांड से संबंधित है जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हुकम सिंह, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री कुबेर भण्डारी, श्री मोती लाल देहलवी, श्री रियासत हुसैन तथा श्री राम गोविन्द द्वारा दी गयी है, वह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी है । माननीय शंकर सिंह की जो सूचना है उसी विषय पर नियम 51 में प्राप्त सूचना को स्वीकार किया गया है ।

श्री रियासत हुसैन—

जो वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी है, इसको आप सदन के उठने के पहले ले लें।

(शोर तथा व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय, सदस्य ने प्रश्न उठाया है, कल जब सामान्य प्रशासन पर उस दल के लोग, माननीय मुख्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री ने तत्परता से कहा कि सब कुछ नियंत्रण में है, कण्ट्रोल में है, कुछ ग्राम्य विकास मंत्री ने भी कहीं और कुछ भाषा ऐसी बोलते हैं जिस को अधिक लोग, मंत्रि परिषद् के लोग बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि उन शब्दों को टेप करा लें और जब चाहें सुना दिया करें। जैसे तत्परता,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र सिंह---]
शीघ्रता आदि-आदि चार पांच शब्द बोलते हैं। कल जब तीन पुलिस अधिकारी मारे गये तो यह उन्मूलन तो पुलिस का हो रहा है, डकैती का कहां हो रहा है? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बजट में कुछ रखा नहीं है, एक सेकेण्ड में पास कर देंगे, आपका बहुमत है, पास हो ही जायेगा, आप कहियेगा 5 बजने से 5 मिनट पहले पास कर देंगे लेकिन इस विषय में बहस करा लें। इतनी सजगता होने के बाद भी लखनऊ में 3 हत्यायें हो गयी जहां पुलिस फोर्स, बड़े-बड़े अधिकारी, मंत्रि परिषद् बैठा है। जालौन के अंदर क्या हुआ? हम चाहते हैं बहस कीजिये, दो घंटे के अन्दर जवाब दीजिये, दो घंटे का समय हम दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---
जो प्रश्न माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया है उसके संबंध में मंत्री जी से जवाब दिलवा दें।

श्री अम्मार रिजवी---
मान्यवर, अभी मैंने निवेदन किया था कि जो सूचना उपलब्ध थी बगैर कहे मंगा कर आप के समक्ष रख दी, सूचनायें आ रही हैं। स्थिति क्या है इस संबंध में इस समय . . .

(व्यवधान)

पुलिस महानिरीक्षक, एन्टीडकैवायटी के डी0 आई0 जी0, जितने पुलिस अधिकारी थे सब उस स्थल पर जा चुके हैं। कोई ऐसी चीज बता देंगे बगैर सूचना के तो उचित नहीं होगा, तब माननीय सदस्य कहेंगे कि. . . .

(व्यवधान)

जैसे ही सूचना आ जायेगी मैं तुरन्त सदन में रख दूंगा। जिस समय सूचना आयेगी आपके सामने वह रख दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा---
मान्यवर, कम से कम चर्चा के बारे में मंत्री जी आश्वासन तो दे दें कि चर्चा स्वीकार है उन्हें।

श्री अध्यक्ष---
मैंने जैसा पहले आप से कहा कि लखनऊ के संबंध में वक्तव्य देने के लिए निर्देश दिया है। केवल वक्तव्य। जैसा कि लखनऊ का मामला है मंत्री जी इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र आप वक्तव्य कब दे सकते हैं, बता दें?

श्री अम्मार रिजवी---
30 को रख लिया जाय, मान्यवर।

श्री रियासत हुसैन---
हम आज जा रहे हैं। लोग हम से पूछेंगे कि क्या हुआ और वक्तव्य आ रहा है 30 को, तो आज इस को कर दें।

श्री अम्मार रिजवी---
सारी सूचना उपलब्ध कराना है। अगर कोई सूचना गलत कही जायेगी तो यह कहेंगे कि सूचना दबायी जा रही है . . .

श्री रियासत हुसैन---
हम यह नहीं कहेंगे। जितनी भी जानकारी हो वह आज 4 बजे तक जरूर दे दें कि मामला क्या है।

श्री अध्यक्ष--

आज 28 तारीख है कल आपका सदन बन्द है । दो ही तारीख जल्दी से जल्दी हो सकती है, या तो आज दें या तो अगले दिन दें । आज देने के सम्बन्ध में यदि 12 बजे निर्देशित करता हूं तो यह पूरी सूचना दे पायेंगे या नहीं आप यह देख लें, लेकिन जो भी वह सूचना आपको दे सकेंगे देंगे, इस पर केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है, दुबारा फिर दूसरी सूचना पहले आप दें और उसको स्वीकार करें तो उचित यह होगा कि निश्चित रूप से 30 तारीख को वक्तव्य दे देंगे।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इसके ऊपर यह है कि या तो उनके ऊपर चर्चा होने की बात स्वीकार करें और जिस वक्त यह कहें, जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा, आप जब कहिए पास करा लीजिए, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के सम्बन्ध में यह जो आपकी सूचना है, इस पर जैसा मैंने कहा नियम 51 में यह स्वीकार की गई है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

आप लोग बैठ जाइये । कृपया सुन लें । नियम 51 में यह सूचना जालौन जनपद में वहां के दरोगा व कांस्टेबिल के मारे जाने के संबंध में है, इस संबंध में आप कब वक्तव्य दे सकेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी--

आज यह भी संभव नहीं है । माननीय नेता विरोधी दल तो मंत्री रह चुके हैं, वह समझते हैं कि क्या कठिनाई हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

कुछ तो आप कार्यवाही चलने में सहयोग दें । 30 तारीख तक आप दे सकेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अगर यह सम्भव नहीं है तो सदन का चलना भी सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह दोनों वक्तव्य जालौन वाली घटना के सम्बन्ध में नियम 51 में वक्तव्य और दूसरा लखनऊ की घटनाओं के संबंध में वक्तव्य 30 तारीख को आप दे दें और उस वक्त अगर आप . . .

(व्यवधान)

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

बार-बार मैं खड़ा होता हूं और आप खड़े हो जाते हैं। दूसरा कोई खड़ा हो तब भी कोई बात है। आप बैठ जायं।

इस पर यह 30 तारीख को वक्तव्य होगा और उस दिन अगर आवश्यक समझा गया तो इस पर चर्चा करा दी जायेगी।

(शोर तथा कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

अब आप अगर यह नहीं मानते हैं तो मेरे मुंह में अपना उत्तर दे दीजिए उसको बता दूं। मैंने स्वीकार कर लिया है, सारी बात स्वीकार कर लिया है। इस तरह से आप मुझसे उत्तर नहीं दिला सकते।

(श्री फखरे आलम के खड़े होने पर)

आप बैठ जायें। आप थे नहीं। इससे पहले यह आया था मैंने इसको अस्वीकार किया है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981

*पंचायती राजमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981, जो इस सदन द्वारा दिनांक 14 मार्च, 1981 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दिनांक 25 मार्च, 1981 की बैठक में अस्वीकृत हो गया है, को जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो यह अभी विधेयक फिर से प्रस्तुत किया गया विधान परिषद ने हमें मौका दिया है कि हम इस पर फिर से विचार कर लें, पुनर्विचार कर लें।

इसका विरोध नहीं किया जाता अगर इसमें कार्यकाल बढ़ाने तक की बात होती, शायद इस पर विचार कर लिया होता। यह एक बहुत ही खतरनाक, जनतंत्रीय परम्पराओं के खिलाफ शासन द्वारा अपनी संख्या के बल पर, जनतंत्र के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों को न चुन कर अपने नामांकित प्रतिनिधियों के द्वारा काम करने की नियत का यह परिचायक है। दूसरी गंभीर बात यह है कि यह विधेयक इस बात को सिद्ध करता है कि इस सरकार के मंत्रियों के अन्दर समय पर निर्णय की अपात्रता, सूझबूझ का नितान्त अभाव है, समय पर कोई फैसला कर सकें, इसकी अपात्रता है, नौकरशाही पर नियंत्रण करने में असमर्थ है। इस संबंध में इस विधेयक के उद्देश्य और कारण देखने की कृपा करें। उद्देश्य और कारण में लिखा है कि मण्डी समिति अधिनियम का कार्यकाल 5 मार्च, 1981 को समाप्त हो गया। 5 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो गया और आज 28 मार्च को हम इस पर विचार कर रहे हैं। इतने दिनों तक ऐसी परिस्थिति रही जब जिलाधिकारियों ने प्रशासन किया होगा। उनको इस विधान मंडल ने किसी अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं दिया इस तरह का प्रशासनिक काम करने का। इस अधिनियम में लिख दिया गया है कि इस बीच उनके द्वारा किया गया सभी कार्य वैध मान्य हो जायेंगे। संख्या के बल पर यह हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर 5 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो 5 मार्च के पहले अध्यादेश क्यों नहीं निकाल दिया गया था विधान मंडल सत्र के आहूत होने के पहले।

राज्यपाल को अधिकार दिया गया है संविधान के तहत कि अध्यादेश निकालें। ऐसा अध्यादेश निकालना नहीं था तो विधान मंडल का सत्र समय से पहले आहूत किया जाता, 5 मार्च से पहले राय लेकर इस विधेयक में संशोधन कर दिया होता। यह अपात्रता है। मैं कहता हूं इस अपात्रता के लिए दोषी, जिम्मेदार, मंत्री हैं। उन मंत्रियों को यह जो गलती रह गयी है, अपात्रता रह गई है, सूझ बूझ की कमी रह गई है, समय पर निर्णय न लेने की कमी है, इस गलती के लिए क्या मंत्रियों को हम अपने पद पर रहने देंगे? ऐसे मंत्रियों को बरखास्त कर देना चाहिए। उन्हें खुद त्याग पत्र दे देना चाहिए। एक गंभीर मामला है। एक कल्पना कीजिए। इस बीच जिलाधिकारियों ने कोई ऐसा काम कर दिया होगा जिससे वाद कोर्ट में प्रस्तुत हो क्या सरकार और विधान मंडल इसमें पार्टी नहीं बनेगा? हम भी पार्टी बन जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और आदरणीय सदन से इस बात के लिए अपील करता हूं कि परिस्थिति को समझते हुए कि क्या कभी सरकार को ऐसा फैसला करने का मौका दिया जाय इस विधेयक को जरूर-जरूर अस्वीकृत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दें और अस्वीकृत कर के इस सरकार पर बल दें, चेतावनी दें, कि अगर यह समय पर निर्णय न ले, नौकरशाही के हाथ में कठपुतली बनी रहे, समय पर निर्णय लेने की अपात्रता रहेगी, तो सदन आपके द्वारा किये गये काम का समर्थन नहीं करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बात का विरोध करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी--

यह विधेयक पहले भी इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है और पारित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त की है जहां तक कि विलम्ब का संबंध है, विलम्ब इसमें हुआ, वाकई कोई इन्कार करने की बात नहीं है। लेकिन जहां तक जिला परिषद् और तमाम चीजों के चुनाव के संबंध में बात है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि अतिशीघ्र, जितनी जल्दी हो सकेगा, चुनाव कराये जायेंगे ताकि हमारा जो पूरा सिस्टम है, चौखम्भा राज्य बनाने का, प्रजातंत्र को मजबूत करने का, उसमें हम कामयाब हो सकें। इस में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है कि इसका कार्यकाल बढ़ाने की वजह से जिलाधिकारियों को मुस्तकिल अधिकार दे दिये जायेंगे।

उस दिन माननीय मोहन सिंह जी नेसुझाव दिया था कि उनको किसी न किसी रूप में समयानुकूल कराना चाहिए। मैंने उस समय भी यह कहा था कि इनको समयानुकूल अवश्य किया जायेगा। मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो विधेयक आपके सामने आया है उस पर काफी चर्चा हो चुकी है और काफी सम्मानित सदस्यों ने उस पर विचार व्यक्त किये। इस पर अब अधिक चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसे पारित किया जाय।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आज इस बिल के पारित हो जाने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो शासन के मिनिस्टर थे, वे अफसरान का संरक्षण किया करते थे लेकिन आज से यह माननीय सदन भी उनका संरक्षक हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981, जो इस सदन द्वारा दिनांक 14 मार्च, 1981 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 25 मार्च, 1981 की बैठक में अस्वीकृत हो गया है, को, जैसा कि वह सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[समय 11 बजकर 53 मिनट]

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 50--पर्वतीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 87--पर्वतीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 117--पर्वतीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50--पर्वतीय विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,99,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—]

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87—पर्वतीय विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अतंर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,69,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 117—पर्वतीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,24,01,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, विशेष प्रसन्नता की बात हमारे लिये यह है कि छठी पंच वर्षीय योजना में जहां पूर्व में हम हिमाचल प्रदेश के समकक्ष धनराशि की बात करते थे, इस बार 10 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी है। 560 करोड़ उनका है और 570 करोड़ रुपया छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये स्वीकृत हुए हैं। इस समय विशेष केन्द्रीय सहायता का अंश बढ़ा है। 350 करोड़ रुपया विशेष सहायता का अंश है। पर्वतीय क्षेत्र का परिव्यय इस वर्ष 1 अरब रुपया रखा गया है। मान्यवर, 1978–83 के बीच में जो प्लान परिव्यय था जो पंचवर्षीय योजना बनने वाली थी, उसमें प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट 995 रुपया आ रहा था लेकिन जो हमारी योजना बनी है उसमें प्रति व्यक्ति प्लान परिव्यय 1491 रुपया प्रति इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि 496 रुपया प्रति व्यक्ति उसमें बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 1980-81 में प्रति व्यक्ति प्लान परिव्यय जहां 225 रुपया रखा गया था, वहीं वर्ष 1981-82 में 262 रुपया प्रति व्यक्ति प्रस्तावित है। विशेष केन्द्रीय सहायता का अंश जो 5वीं योजना अवधि में लगभग 50 प्रतिशत था वह बढ़कर 61.4 हो गया है और इसमें राज्य के अंश में कमी नहीं हुई है। शासन के उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए सामाजिक क्षेत्र की सभी सुविधायें हर क्षेत्र में यथा संभव उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्र विकास योजनाओं का लक्ष्य थोड़ा बदल दिया गया पिछले जो विकास परिषद् की मीटिंग हुई थी उसमें पर्वतीय विकास परिषद् के सदस्यों की आम सहमति थी और विचार था जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी सराहा था, एक तरह से निर्णय था कि आय परक श्रोतों, इनकम जेनेरेटिंग सेक्टर पर अधिक धन व्यय करें। पर्वतीय विकास पर अंशदान को ध्यान में रखते हुए, पर्वतीय लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए, वहां के विधायकों और परिषद् के सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमने छठी पंचवर्षीय योजना की आय परक योजनाओं में 44 प्रतिशत तक व्यय की व्यवस्था की है जो कि पहले 36 प्रतिशत था। इस प्रकार से 8 प्रतिशत अधिक खर्च आय परक योजनाओं में बढ़ा है।

इस बात की भी चेष्टा की जा रही है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों से नौकरी की तलाश में लोग पलायन करते हैं उनको किस तरह से आत्मनिर्भर बनायें उस लक्ष्य को लेकर विकास योजनायें बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में शासन ने नीति बनाई है कि स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध स्थानीय टैलेंट का समुचित प्रयोग करके कंज्यूमर ओरियेंटेड अर्थ व्यवस्था के बजाय इनवेस्टमेन्ट अर्थ व्यवस्था तैयार की जाय ताकि वहीं पर लोग कुछ लगा सकें और अपने आय के स्रोत बढ़ा सकें इसके लिये विभिन्न तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र के टैम्परेट जलवायु के अनुरूप फलोद्यान, गैर मौसमी फलों एवं सब्जियों की खेती करना जिस समय मैदानी क्षेत्र में जो सब्जी नहीं होती है उस समय वहां पैदा की जाय, जो फल यहां नहीं होते हैं वह वहां पैदा किये

जायं। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर भी कार्य करने की चेष्टा की जा रही है। आज की जो वर्तमान आवश्यकता है जिसकी ओर सारे देश की नजर लगी है भूमि संरक्षण और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोकल डेवलपमेन्ट करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए विशेष व्यवस्थायें की जा रही हैं जिसकी चर्चा मैं आगे जाकर करूंगा। वहां की परिस्थिति को देखते हुए माइक्रो वाटर शेड, छोटी छोटी रैवूलेट्स जो हैं जिनकी वजह से कटान होता जा रहा है उसके लिए माइक्रो वाटर शेड को विकास योजनाओं की इकाई मानकर परियोजनायें तैयार करने पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ताकि भू-कटाव की मात्रा को रोका जा सके। इसी संदर्भ में मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछली बार वन विभाग के बजट पर बोलते हुए मैंने कहा था कि 2750 मीटर के ऊपर 45 डिग्री अंश से ऊपर पेड़ों का कटान नहीं होगा। और मुझे सदन को बताते हुए हर्ष है, यद्यपि इस पर एक कमेटी गठित की जा रही है, किन्तु माननीय मुख्यमंत्री ने अंतरिम रूप से आदेश दे दिये हैं कि एक हजार मीटर से ऊपर और 35 डिग्री से ऊपर के जो ढलान हैं, उनके ऊपर कटान न किया जाए। इस तरह से पर्यावरण को बनाये रखने के लिए एक अच्छा प्रयास किया गया है, जिसकी ओर सारे देश का ध्यान गया है। इससे मैदानी क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं, ऊपर की सिलटिंग नीचे आती है और उससे खेती की जमीनें कट जाती हैं, जिससे मैदानों में अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती है। अन्तोगत्वा इससे पर्वतीय क्षेत्रों को ही नहीं बल्कि पूरे मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना के बेसिन और कलकत्ता तक उसका प्रभाव जाता है। तो इसका फायदा कृषि में और अन्य क्षेत्रों में भी पूरा-पूरा मिलेगा। इसका प्रदेश को ही नहीं, देश को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है।

स्थानीय उद्यमियों को समुचित रूप से प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किये जाने की बात है। वहां पर इक्विपमेंट की काफी कमी थी और कुछ संस्थाओं को केवल प्राविजनल मान्यता मिली हुई थी। तो अब इनमें गुणात्मक सुधार करके इक्विपमेंट प्रोवाईड कर दें और उन संस्थाओं को पूरी मान्यता दे दें, यह हमारी योजना है। हम वहां पर सारे इक्विपमेंट्स दे दें, ताकि इनके पढ़े हुए लड़के जो निकलें वे कहीं अच्छी तरह से काम कर सकें। उद्योगों को बिजली देने के लिए, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रदेश सरकार स्वयं ही इस नीति पर विचार कर रही है और उसी सन्दर्भ में पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष रूप से छूट दी जाएगी, उस पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ-साथ हम माइक्रो हाइडिल स्कीम पर भी ध्यान देना चाहते हैं और हम यह चेष्टा कर रहे हैं कि सिंचाई विभाग वाले जो गुले बनाते हैं, स्रोत ढूंढ लेते हैं, उनके द्वारा माइक्रो हाइडिल स्कीम कहां-कहां लगायी जा सकती है, पता लग जाएगा। क्योंकि विद्युत विभाग के पास कोई इस हेतु स्टाफ नहीं है और सिंचाई विभाग को वहां जाना पड़ता है, तो एक लिंक बनाकर माइक्रो हाइडिल स्कीम को बढ़ाने की चेष्टा की जाएगी।

एक और प्रशंसा की बात है, हमेशा यह कहा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकारी इसलिए भी नहीं रुकते हैं कि वहां पर गृह निर्माण नहीं है, अधिकारियों को रहने के लिए आवास नहीं मिलता है। अतः उनके हेतु आवास बनाने के लिए जो धनराशि है वह अपने स्थान पर तो है ही, लेकिन अपने बजट से पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में अपना मकान बनाने के लिए अग्रिम धनराशि का प्राविधान विभागीय बजट में अतिरिक्त रूप से भी किया जा रहा है यह इस बजट में किया गया है ताकि उनको यदि अपने विभाग से उतनी मात्रा में धनराशि नहीं

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—]

मिल सकती है, तो अपने विभाग से वह यह धनराशि प्राप्त कर पायेंगे ताकि उनके रहने संबंधी कोई दिक्कत या असुविधा नहीं हो। मान्यवर, मैं अनुगृहित हूं मुख्य मंत्री जी का कि प्लान परिव्यय के लिए उन्होंने निर्णय लिया है कि इन प्लान परिव्यय के अंतर्गत जो योजनायें हैं, उनके निरूपण और कार्यान्वियन के लिये संबंधित विभागीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे पर्वतीय विकास के लिये अब तक इसमें कोआर्डिनेशन में थोड़ी दिक्कत होती थी। अब ऐसा है कि इसके द्वारा इसके कार्यान्वियन में काफी मात्रा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने हेतु समुचित और काफी धनराशि का इसमें प्राविधान है, साथ ही बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासन के लिये भी धन का प्राविधान किया गया है। पहाड़ों पर कृषि योग्य भूमि की अपनी सीमा होने के कारण दो फसली क्षेत्रों में वृद्धि तथा फसलों के डाइवर्सीफिकेशन की हमारी नीति है और हम यह करने जा रहे हैं, ताकि उत्पादन में हमारे वृद्धि हो। पर्यावरण, भू-संरक्षण के लिये तथा स्थानीय निवासियों के लाभ हेतु कृषि योग्य भूमि में फलोद्यानों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जायेगा। उन्नत किस्म वाली वर्तमान फसलों, दलहन, तिलहन, सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसी कैश क्रापों को भी बढ़ावा देने की हमारी नीति रहेगी। हम इस पर पूरा ध्यान देंगे और इनके लिये उर्वरक के मूल्यों तथा उसके परिवहन पर अनुदान देने का भी प्राविधान है। अभी हाल ही में मैंने फलोपयोग विभाग से कहा है कि वह खोजबीन करके बताएं, जिससे हम उन कार्यक्रमों को लेने की चेष्टा करें जिससे उनका अधिकाधिक विकास हो। हमने यह भी उनसे कहा है कि वह साल भर जो फसल पैदा करते हैं, उसके पूरे आंकड़े हमें दे दें, तो उनके लिए प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने पर विचार किया जा सके, जिसके बारे में माननीय सदस्य समय-समय पर सुझाव देते हैं और देंगे भी। तो उस आधार पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर भी विचार किया जाएगा।

पंतनगर यूनिवर्सिटी तथा रानीचौरा हिल कैम्पस में शोध कार्य की सुविधा देने की बात प्रस्तावित है, लेकिन इसमें प्रगति अभी तक नहीं हुई है। अभी वहां पर जो उपकुलपति गये हैं वे हमारे प्लानिंग सेक्रेटरी थे। वे उसको त्वरित गति से चलाने के लिये लगातार हमसे सम्पर्क बनाये हुए हैं और यह चेष्टा की जा रही है कि मैदानों के अलावा जो स्थल हैं उनमें स्वायल एनेलिसिस के लिये किस तरीके से काम हो सकता है। उस दिशा में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। कृषकों के लिए भी विपणन और भंडारण की सुविधा देने के लिए जो पहले 43 हजार मीट्रिक टन की क्षमता थी 1981-82 में 4 हजार मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का और सृजन करेंगे।

हमारे यहां पर जो सामुदायिक बेनाप भूमि है उस पर हम शत प्रतिशत खर्च करके विभाग के द्वारा एफोरेस्टेशन करवा रहे हैं। फलदार पौधों तथा सब्जी के बीज के लिए शत प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। चूंकि मुझे सारे विभाग देखने पड़ते हैं इसलिए संक्षेप में, मैं अपनी बात बता रहा हूं और बहुत कम समय भी लूंगा ताकि विधायक गण अपने-अपने विचार प्रकट कर सकें। यह भी चेष्टा की जा रही है कि मार्केटिंग इन्टेलिजेन्स यूनिट्स-कम-पैकिंग एवं ग्रेडिंग और जो फल उनके ट्रांसिपमेंट के लिये भी सेन्टर्स बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है। जो पैदा करने पर भी काश्तकारों को अनुदान दिया जा रहा है। मशरूम का उत्पादन जो काफी होता है देहरादून से चला जाता है। उसके उत्पादन के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपया ऋण की सीमा कर दी गयी है और ब्याज की दर 5.5 प्रतिशत कर दी गयी है।

जहां तक होटल प्रबन्ध पाठ्यक्रम का संबंध है इसमें प्रवेश हेतु, जो लखनऊ में स्थित है, 6 प्रशिक्षार्थियों के लिये स्थान आरक्षित किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की

आवश्यकता को देखते हुए अगर ये सब वहां पर खपाये जा सकें तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसी तरह का कोर्स चलाने हेतु एक केन्द्र खोलने पर विचार किया जायेगा।

हवा के बाद पेय जल की प्रमुख आवश्यकता होती है। इसका वहां पर काफी कष्ट है। इस कष्ट को इसलिए भी महसूस करते हैं क्योंकि मुख्य रूप से महिलाओं को ही इस कष्ट को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस वर्ष भी इसके लिए प्राविधान किया गया है। 1981-82 वर्ष में ग्रामीण पेय जल योजना के लिए 17.25 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा ग्रेविटी वाटर सोर्सेज, इकोलौजिकल इम्बैलेन्सेज के कारण पुराने सोर्सेज सूख गये हैं और इस बार फेज पम्पिंग की योजना बन रही है। टेक्नीकल दिक्कत भी आ रही है और काफी रुपया भी लग रहा है। फिर भी काफी संख्या में इसको हमने रखा है। इस वर्ष 120 ट्राइबल विलेजेज और 680 दूसरे गांवों में पेय जल की योजना का लक्ष्य है। वर्ष 1981-82 में इसके लिये 17.25 करोड़ रुपये की लागत से पानी देने का प्रबन्ध किया जायेगा। जल निगम और जल संस्थान की एक इकाई खुले, इसके लिये औपचारिकताएं चल रही हैं और बात चीत भी चल रही है। इसके मैरिट्स और डिमैरिट्स, दोनों पर विचार किया जा रहा है और यथा समय निर्णय ले लिया जायेगा।

इस वर्ष में डीप फ्रिज सीमैन तकनीक कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये 125 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत नस्ल सुधार हो सकेगा। इन केन्द्रों की देहरादून और अल्मोड़े में स्थापना की गयी है।

इसके अलावा श्रीनगर में एक लिक्विड नाइट्रोजन प्लान्ट के भवन का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। 15 नये पशु चिकित्सालय, 30 स्टाफ मैन सेन्टर भी खोले जायेंगे। 18 कार्यरत आई0 टी0 आई0 (एक महिला आई0 टी0 आई0) तथा उनमें 7 व्यवसाय हेतु 560 सीटों का निर्माण तथा साज-सज्जा आदि के लिये प्राविधान किया गया है। इन संस्थानों की साज सज्जा व भवन के लिए वर्ष 81-82 में 60 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। यह प्रयास है कि भारत सरकार एवं एन.सी.टी.बी.टी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार साज-सज्जा उपलब्ध करायी जाएं।

बहुधन्धी संस्थायें 9 हैं। हर जिले के एक-एक हैं। एक जिले में दो हैं। इनको चालू रखने तथा भवनों और साज सज्जा हेतु भी इस वर्ष 64 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 200 उप-केन्द्र, 40 ग्रामीण एलोपैथिक, 8 आयुर्वेदिक, 5 होम्योपैथिक, 5 महिला चिकित्सालय, 2 हृदय रोग पर्यवेक्षा इकाइयां, एक ई0 एन0 टी0 इकाई, 5 शल्य, 2 बाल ऊर्जालय, 4 शरीर विकृत विज्ञान तथा 4 दन्त ऊर्जालय और 2 नर्सिंग होम की स्थापना का लक्ष्य है। गैर सरकारी 3 चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण, 2 चिकित्सालयों में पूर्ण उपचारिक सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। अल्मोड़ा तथा श्रीनगर गढ़वाल में 200 शैय्या युक्त बेस अस्पतालों के भवनों के निर्माण के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। 2 यौगिक केन्द्रों की स्थापना का प्रश्न भी विचाराधीन है क्योंकि जिस क्षेत्र लक्षमन झूला से मैं आता हूं वहां लोगों की इस ओर काफी रुचि है।

जन जाति क्षेत्रों में वर्ष 1981-82 में 25 उपकेन्द्रों की स्थापना तथा सचल इकाइयों की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

शिक्षा क्षेत्र में भी गुणात्मक सुधार पर अधिक बल दिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र में 1500 फुट से अधिक ऊंचे स्थान पर

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—]

स्थित ग्रामीण प्राइमरी स्कूल में कम से कम दो अध्यापक की नियुक्ति प्रस्तावित है। जीर्ण स्कूल भवनों की विशेष मरम्मत के लिए भी प्राविधान किया गया है। पर्वतीय विकास परिषद् की मीटिंग में यह कहा गया था कि भवन नहीं हैं। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं हैं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी कमी है। इसलिए विद्यालयों में साज-सज्जा और उपकरणों आदि के लिए भी प्राविधान किया गया है। नयी बिल्डिंग्स बनाने तथा उनके विद्युतीकरण का भी प्राविधान किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया है। निर्बल वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिये निःशुल्क पुस्तकों के वितरण की भी व्यवस्था की जायेगी। उनको पोशाक देने की भी व्यवस्था की जायेगी। जीर्ण स्कूलों की मरम्मत भी सीमित साधनों को देखते हुए की जायेगी। जो छात्र काफी दूर से हमारे यहां पढ़ने के लिए आयेंगे उनको छात्रवृत्ति पूर्ववत् जारी रहेगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता के लिए पात्र बनाने के लिए 30 लाख रुपये विकास अनुदान प्रस्तावित है। इससे विश्वविद्यालय सहायता का पात्र होने में अग्रसर होगा। हमने काफी मात्रा में उस विश्वविद्यालय को रुपया दिया है ताकि वह विश्वविद्यालय एक अच्छे मानक को प्राप्त कर लें। हमने कोशिश की है इस क्षेत्र में इन्कम जनरेटिंग सेक्टर आदि पर खर्च करें। मैं माननीय राम स्वरूप वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव को देख रहा था। उन्होंने यही कहा कि कमी करने का उद्देश्य- जन उपयोगी कार्यों को रोक कर कम महत्व की चीजों पर खर्च करने की आलोचना करना, और ऋण को राजस्व व्यय की तरह खर्च करने की आलोचना करना, रोपवे का विकास करना, फलों की बागवानी का विकास करना, रम्य व स्वास्थ्यकर पर्यटन स्थलों का विकास करना। तो आपका मन्तव्य भी जो है, उसी मन्तव्य की पूर्ति हेतु हम इस कार्य को करते जा रहे हैं।

मान्यवर, गोपेश्वर, जिला चमोली में 31.82 लाख रुपये की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम के बनने की स्वीकृति दी जा चुकी है। माननीय मुख्य मंत्री जी का सम्भवतः कार्यक्रम है कि वह इसका शिलान्यास भी करने वाले हैं। पिथौरागढ़ में सुरिनगाड़, चमोली में तपोवन तथा थराली और सीतापुर चट्टी में लघु जल विद्युत योजनाओं हेतु वर्ष 1981-82 में 8 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है और माईक्रोहाइडिल इकाई स्थापित करने के लिये एप्रोप्रिएट टेक्नालाजी डेवलपमेन्ट एसोसियेशन, लखनऊ द्वारा स्थलों का चयन मिनी माइक्रोहाइडिल स्कीम चलाने हेतु जानकारी प्राप्त की जा रही है। यह विचार है कि आरम्भ में उक्त एसोसिएशन द्वारा इकाइयां लगाई जायं और बाद में उन्हें स्थानीय संगठनों को सौंप दिया जाय। लगभग 12 हजार में छोटी-छोटी माइक्रोहाइडिल इकाई बनवाने के लिए हम देखवा रहे हैं कि अगर वह अच्छी पड़ती हैं, तो उन पर विचार किया जा सकता है कि छोटे-छोटे गांवों के लिए उस लाइन पर विचार किया जा सकता है। विद्युतीकरण के जो हमारे लक्ष्य हैं, उसमें 718 ग्रामों तथा हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण तथा 320 नलकूपों, पम्पिंग सेटों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य है। माइनर इरीगेशन की योजनायें काफी मात्रा में जनरेटिंग सेक्टर में आती हैं। निजी सिंचाई कार्यों के लिए 125 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है तथा राज्य लघु सिंचाई कार्यों के लिए 540 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ताकि इसको बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से उक्त साधनों से 20,580 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हो जायेगी। इसके अतिरिक्त 60 हाइड्रम योजनायें प्रस्तावित हैं। इस वर्ष पक्के कुओं, नलकूप सेटों और पम्प सेटों आदि से 12,500 हेक्टेयर की सिंचन क्षमता होगी। इनकी देख-रेख के लिये शासन अभी विचार कर रहा है, अंतिम फैसला नहीं किया है। सेना के जो हमारे अवकाश प्राप्त लोग हैं, अगर वह तकनीकी ज्ञान रखते हैं तो इनको उसमें लगा लिया जाय, यह शासन के विचाराधीन है। यह भी शासन के विचाराधीन है कि इनको अंशकालिक रूप से रखने से काम चलेगा कि नहीं,

क्योंकि सेना के लोग बहुत काफी कम उम्र में रिटायर होकर घर चले आते हैं। उनमें डिसीप्लिन और काम करने की सामर्थ्य होती है और अगर उनकी सेवाओं का लाभ हमें मिल सकता है और उसमें कार्य भी अच्छा होगा। तो इस पर विचार किया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग है। हमने पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में यह चेष्टा की है कि पहले 3 हजार किलोमीटर सड़कों का सर्वे कराया जाय। इसके अतिरिक्त 4 लाख 75 हजार की लागत से नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड एण्ड इकोनामिक रिसर्च, नई दिल्ली को ट्रान्सपोर्टेशन प्लान बनाक देना है। इसको इस लिये दिया गया कि सड़कें इस तरह से बनें जिनमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, हार्टिकल्चर सेंटर्स तथा टूरिस्ट काम्पलेक्सेज को दृष्टि में रखा जा सके। इन सारी चीजों को देखते हुए इस सर्वे के कार्य को अलग से ले रहे हैं और कान्स्ट्रक्शन कास्ट में सर्वे की कास्ट नहीं जोड़ी जायगी। कई जगह माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया कि कहीं-कहीं सड़क बन जाती है लेकिन दो सड़कों के बीच में पुल नहीं बन पाते हैं जिससे सड़क चलती नहीं है। इसके लिए लगभग यह विचार निर्णय की स्थिति में है कि पोर्टेबिल ब्रिज संयंत्र खरीद लिए जांय और जैसे ही कोई सड़क बने उस पर पोर्टेबिल ब्रिज बना दिया जाय ताकि वह सड़क चालू हो जाय। फिर ब्रिज बनना शुरू हो जाय और पुल जब पक्का बन जाय तो पोर्टेबिल ब्रिज दूसरी जगह ले जाया जाय ताकि सड़क पर पुल बन सके तथा समयबद्ध रूप से सड़कों का भी निर्माण हो सके।

81-82 में 750 कि. मीटर नई सड़कें, 20 पुल तथा 250 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण तथा सुधार का लक्ष्य है। उद्योगों के लिए बराबर हम चेष्टा कर रहे हैं, भारत सरकार से हमारे नियोजन मंत्री भी कर रहे हैं, मुख्य मंत्री ने भी किया है कि इंडस्ट्रियल बैकवर्ड जोन घोषित किया जाय। चूंकि सभी की सहानुभूति इस ओर है इस पर बहुत जल्दी कोई न कोई निर्णय लेने में वह सक्षम होंगे। जहां तक निगमों का सम्बन्ध है इस वक्त गढ़वाल निगम तथा कुमायूं मंडल विकास निगम की गतिविधियों को तेज करने के लिये पूंजी में वृद्धि की जा रही है तथा एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाने के लिये कहा गया है। हेफहेजर्ड वे में न चला बल्कि एक पर्सपेक्टिव प्लान पर चला जाय।

अभी कोटद्वार की फ्लशडोर इकाई का उद्घाटन हुआ था। सीमेंट का बड़ा अभाव था। टेंडर मांग लिये गये। बने तो कैसे बने। उद्योग विभाग ने कोशिश करके 100 मीटरिक टन सीमेंट दे दिया। अब शीघ्र ही इस पर निर्माण होने वाला है। इसके साथ ही मैं भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पहली बार पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिये टूरिज्म के कार्य के लिये तथा लोगों की आवश्यकता के लिये 38 हजार मीटरिक टन के लिये सीमेंट का प्राविधान किया गया है जिससे हमारे निर्माण कार्यों में जो सुस्ती थी उसमें आटोमेटिक चुस्ती आ जायगी और कार्य तीव्र गति से चलने लगेंगे।

यही नहीं, हम यह भी चेष्टा कर रहे हैं कि टेलीट्रानिक्स लिमिटेड, भीमताल का विस्तार किया जाय। डायरेक्टर, पुलिस टेलीकाम तथा अध्यक्ष, यू. पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन 26-27 को गढ़वाल मण्डल के दौरे पर थे और जैसा कि उनका रेडियोग्राम भी मौजूद है, वे यह देखने गये हैं कि इलेक्ट्रानिक्स इक्विपमेण्ट्स के कितने कारखाने वहां लगाये जा सकते हैं और कितनी फिजिबिलिटी वहां की है। वहां पर नरेन्द्र नगर, श्रीनगर, लैंसडाउन आदि स्थानों में देखने जा रहे हैं। हमारी यही चेष्टा है कि पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह की चीजों को, जैसे स्विट्जरलैंड में है, और न केवल उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बल्कि सारे हिन्दुस्तान के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये, जहां

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—]

पर इस चीज के उद्योग लग सकें, वहां पर इलेक्ट्रानिक्स और टेलीट्रानिक्स के आसपास के क्षेत्र में चुने हुए उद्यमियों को प्रशिक्षित कर छोटे-छोटे उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन को गति देने के लिये प्रयत्न किया जायेगा।

हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए 90 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। पर्यटन को हमने इण्डस्ट्री के रूप में मान लिया है, कुटीर उद्योग के स्तर का। 50 हजार तक जो लोग ऋण लेंगे होटल की फिनिशिंग के लिये, उसकी कैटरिंग के लिये, कैटलरी के लिये या उसको अच्छा स्वरूप देने के लिये, उनको 20 प्रतिशत सबसिडी हम देंगे। साथ ही स्थान-स्थान पर पर्यटक निवास बनाये जा रहे हैं। यही नहीं, इसको व्यावसायिक रूप देने के लिये शीतकालीन क्रीड़ा के माध्यम से पर्यटकों के लिये इसे आकर्षक बनाने हेतु, हमारे सचिव जो टूरिज्म के सचिव भी हैं, भारत सरकार के जो पर्यटन से सम्बन्धित अधिकारी हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस वार्ता में काफी सफलता मिलेगी और जो हमारे पर्यटन के काम हैं, उसको भी बढ़ाने के लिये चेष्टा की जा रही है। कार्बेट पार्क और चिला के जो पशु विहार हैं, उसको भी पर्यटन के क्षेत्र के सर्किल में शामिल करने की चेष्टा भारत सरकार से की जा रही है। वर्ष 1981-82 में सिर्फ पर्यटन के लिये हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपया रखा है। छठी पंचवर्षीय योजना में 7 करोड़ 50 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

इस वर्ष 1981-82 में 250 शैय्याओं और हो जायंगी। अब तक 1878 शैय्यायें मौजूद थीं। अब 250 की वृद्धि के बाद 2128 शैय्यायें हो जायेंगी और जो सबसिडी की बात मैंने की थी तो रूल्स फ्रेम कर दिये गये हैं और वह भेज भी दिये गये हैं। उसके आधार पर भी काम जल्द शुरू हो जायगा।

अन्त में मैं पुनः इस बात को फिर कहना चाहता हूं कि वानिकी की महत्ता को देखते हुए इस वर्ष विभिन्न माध्यमों से लगभग 21,000 हैक्टेयर जमीन पर 2 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाने का प्राविधान है। इसमें सिविल एवं सायम बन, रिजर्व फारेस्ट तथा तमाम और भी स्थान सम्मिलित होंगे।

वनीकरण में यह चेष्टा की है कि शीघ्र बढ़ने वाली प्रजाति, चारा देने वाली प्रजातियों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, अलग से मैं बताना चाहता हूं कि पेड़ों की कटान को काफी मात्रा में बंद करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न सामने आयेगा कि स्थानीय लोगों को इससे कठिनाई होगी तो इसके लिये वन विभाग अलग से विचार कर रहा है कि किस माध्यम से हम उनको फ्यूल वुड दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भारत सरकार ने गैस एजेन्सियां हमारे लिए स्वीकृत की थी तो अब एजेन्टों से कहा जा रहा है कि त्वरित गति से इस कार्य को करें। भारत सरकार से पिछले वर्ष ही अनुमति मिल गयी थी लेकिन उसके भंडारण और वितरण की व्यवस्था चूंकि निगम के माध्यम से की जानी थी इस लिये अब कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इन स्थानों जैसे कोटद्वार, श्रीनगर, काशीपुर, रुद्रपुर और लोहाघाट आदि पर्वतीय क्षेत्र में जहां-जहां स्वीकृति मिली है गैस एजेन्सी चालू करें।

मान्यवर, आई० आर० डी० योजना में बहुत से लोगों को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय सदन के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमने उन्हीं की भावनाओं और विचारों का समावेश और आयपरक बनाने की चेष्टा की है। इसके साथ ही व्यक्तियों के पलायन और वन न कटने की चेष्टा की जा रही है। पहाड़ अच्छे रहें, वहां सुधार हो, वहां लोग रहें और उनकी क्रय शक्ति बढ़े इसका

हमने प्रयास किया है। कुल मिलाकर हमारा यह दृष्टिकोण है और इस आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह अपने उपयोगी सुझाव जो देना चाहें वह दें और उन पर हम विचार करेंगे।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87—पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 117-पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, लगभग एक घंटे के भाषण के अन्तर्गत, यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो मंत्री जी ने किया, किया, किया, किया और करने वाले हैं कहा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा। यदि इन्होंने कुछ तुक्के की बात किया तो एक ही किया कि योगिक केन्द्र यह बनाने वाले हैं क्योंकि इनके क्षेत्र ऋषिकेष में ऐसे योगी सिद्ध पुरुष हैं जिनका सीधा संबंध महेश योगी, विदेशी एजेंट, से है। तो मान्यवर, यह ऐसा कार्य करने वाले हैं। यह विशेष बात भारत के लिये, इस माननीय सदन के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को चौकन्ना कर देने वाली है और उनको चौकन्ना भी होना चाहिए चूंकि इन्होंने स्वीकार किया है कि वहां पर रहने वाले योगियों से इनका सीधा सम्पर्क है। मान्यवर, रोज "माया" में छप रहा है कि महेश योगी बिदेशी एजेन्ट हैं और वह विदेशों में क्या करते हैं इसको मंत्री स्वयं जानते हैं। इसलिये उनको चिन्ता है कि महेश योगी और कैलाश योगी की जो कमी रह गयी है उसके लिये मैं तो कहूंगा कि एक दो और केन्द्र खोल दें। इसके अलावा मंत्री जी ने और कोई नई बात नहीं कही है।

मान्यवर, इनको हिमांचल का बुखार बहुत चढ़ गया है। भाषण में कहा कि हिमांचल प्रदेश के बराबर कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हिमांचल की जन-संख्या कितनी है और पर्वतीय 8 जिलों की जनसंख्या कितनी है? हमारा एरिया कितना है और उनका कितना है? मैं यह भी पूछता हूं कि केन्द्र से उनको 80 प्रतिशत मिलता है और 20 प्रतिशत केवल हिमांचल का रहता है तो आप हमारे लिये क्या उतना रुपया लाये हैं? हिमांचल की जो राग आप अलापते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं और इल्जाम लगाना चाहता हूं कि 20—25 जून के मध्य जो आपकी प्लानिंग कमीशन की मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था कि हम पर्वतीय अंचल को पीछे नहीं रहने देंगे और इसी सरकार की प्लानिंग कमीशन ने वहां तय किया था कि हम 15 प्रतिशत का वेटेज देंगे तो वह कहां चला गया है। यदि वह हमको मिलता तो उसके हिसाब से हमारा बजट इस समय 1869 करोड़ रुपये का होता। लेकिन मंत्री जी प्रसन्नता से कह रहे हैं कि हम तो 570 करोड़ रुपये का बजट ले आये हैं। तो मैं इल्जाम लगाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–]

चाहता हूं कि आपने पहाड़ की जनता को धोखा दिया है। मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि केन्द्र से हमें 350 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। मैंने इस सदन में राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्य मंत्री जी को रोक कर कहा था कि आप बतायें कि पर्वतीय अंचल को क्या हिस्सा दे रहे हैं, उनके भाषण को देखें तो उन्होंने कहा था कि 50 प्रतिशत केन्द्र का 50 प्रतिशत हमारा। तो इसको देखने से बनता है 350 करोड़ केन्द्र का और जो हमारा योगदान है उसको देखें तो कुल मिलाकर 629 करोड़ रुपये बनता है। तो आप चोरी कर गये हैं उस रुपये की और कह रहे हैं कि हमने बड़ा भारी काम कर दिया है। हमारे हिस्से का जो रुपया बनता है उसमें आपने चोरी किया है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि इसको आप अपने जवाब में स्पष्ट करेंगे कि क्या बात है और नहीं तो मुख्य मंत्री का वक्तव्य झूठा है या आपका वक्तव्य।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार, पर्वतीय अंचल को अपने प्रदेश के अंश का कितना हिस्सा देती है। यदि हमारा हिस्सा 50 प्रतिशत नहीं है तो मैं भी उसके आंकड़े देने के लिये तैयार हूं। मान्यवर, हमारे यहां कुछ भी नहीं है और माननीय सदस्य भी कहते हैं कि पहाड़ में कुछ नहीं होता है। इसके बावजूद मान्यवर, हमारे यहां के वनों से सरकार को 65 करोड़ रुपये मिलता है और फिर भी वनों को कटवा रहे हैं और भाषण करते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं और किया है। मान्यवर, हमारे सारे वनों को कटाने के बाद 65 करोड़ प्रतिवर्ष खो रहे हैं। मान्यवर, यह इनके हिसाब से लेकिन मैंने हिसाब लगाया है तो 125 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष, पहाड़ नंगे होने के बावजूद, दे रहे हैं और इस प्रकार 5 वर्षों में 725 करोड़ रुपये इस प्रदेश को हम देंगे।

हम विदेशों से भी रुपया लाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं पिछले साल देहरादून के चावल से साढ़े दस करोड़ रुपया विदेशी मिला था। जो देहरादून का चावल बाहर गया था। पहाड़ पर जो पत्थर होता है उससे डेढ़ करोड़ रुपया मिला था। पहाड़ 5 साल में आपको 715 करोड़ दे रहा है और आप हमें 5 साल में 570 करोड़ दे रहे हैं। बड़ा एहसान कर रहे हैं। आप कह रहे थे यह कर दिया, वह कर दिया, बड़ा कल्याण कर दिया। मैं इल्जाम लगाना चाहता हूं इस बात का आपने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है कि मंत्री जी आप पहाड़ के लोगों को मुंह नहीं दिखा सकते। पहाड़ की जनता आपको माफ नहीं कर सकती है। आपने ऐसा बजट पेश करके पहाड़ के रास्ते को रोका है, पहाड़ की जनता को रोका है। आपने कहा यह कर दिया, वह कर दिया बड़ा तीर मार दिया आपने। छठीं पंचवर्षीय योजना में आपने पहाड़ के लोगों को जो दिया है, पहाड़ का हर व्यक्ति पूरी तरह से अपने आपको बुरी तरह कमजोर पा रहा है। मंत्री जी ने प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव बात की। मैं तो बधाई देना चाहता हूं मंत्री को यह दो शब्द याद रहे और तो नहीं कहा, कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं इसके सिवा कुछ आया नहीं।

मैं बताना चाहता हूं प्लानिंग कमीशन की किताब उठाकर देख लें, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है जो बजट आपने बनाया है 65 प्रतिशत अनप्रोडक्टिव है और 35 प्रतिशत प्रोडक्टिव है। आप मान्यवर, उस पर भी दफ्तर खोलते जा रहे हैं। कहां से आपने गणित पढ़ी है, कौन से विद्यालय में मंत्री जी ने पढ़ा है। मंत्री जी दफ्तर खोल रहे हैं कैसे प्रोडक्टिव हो गया। बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे मंत्री जी मकान बनाने का इन्तजाम कर रहे हैं। गढ़वाल, कुमायूं में जो सारे मकान ढेर हो गये हैं क्या उनकी चिन्ता है? अधिकारियों के लिये तो देहरादून और हल्द्वानी में हास्टल बनाने का बजट में रखा है।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा हमने सारे स्कूल और अस्पताल के भवनों के लिये वह किया। मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने भवन हैं गढ़वाल और कुमायूं के

अन्दर और उन पर कुल कितना खर्च आयेगा और कितना आपने रखा है । आपको मालूम होना चाहिए जो आपने रखा है वह एक प्रतिशत रुपया नहीं है, इनको बनवाने के लिये। आप कह रहे हैं हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया। मंत्री जी प्रोडक्शन की बात करते हैं। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। यह आकड़े आपके ही हैं। एग्रीकल्चर पर आप 5 साल में 2 करोड़ 50 लाख खर्च करते हैं यानी साल में 46 लाख, हार्टिकल्चर पर 13 करोड़ 50 लाख 5 साल में, एक साल में एक करोड़ रुपया एक जिले पर। मारकेटिंग का बड़ा नाम मंत्री ले रहे हैं। बड़े फूल कर मंत्री जी कह रहे हैं। एक अंग्रेजी का सेन्टेन्स, वह तो मैं भूल गया लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्री जी रात भर उसका घुट्टा लगाते रहे। मंत्री जी 5 लाख कुल मारकेटिंग पर है।

मैं आपको एक दर्दनाक कहानी बताने जा रहा हूं। हमारे जोशीमठ के इलाके में 5 रुपये क्विंटल आलू आज कोई नहीं उठा रहा है। 8 रुपये सेब हमारे इलाके में किसी ने नहीं उठाया। हमारे इलाके में लोगों ने आलू की खेती करना बंद कर दिया है। इसलिये बन्द कर दिया है कि उसको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है और मंत्री जी कह रहे हैं कि कृषि के लिये एक अलग से विभाग खोल दिया है जो कृषि पर अनुसंधान करेगा और यह अनुसंधान लखनऊ में होगा। कह रहे हैं कि पर्वतीय विकास परिषद् के जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी-अपनी राय दी, तो हमने कब ऐसी राय दी, किस विधायक ने ऐसी राय दी ?

हमारे यहां आलू सड़ रहा है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इनका आज इस प्रकार का रवैय्या हो गया है कि पहाड़ का आदमी आज जिन्दा रहने के लिये सोच रहा है कि हम क्या करें। मैं एक दुखभरी कहानी और बता रहा हूं, हरमल की चोटी पर पांच रुपये किलो नमक मिल रहा है और यह सरकार कहती है कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। आपको कुछ करना है तो करिये, हम कब कहते हैं कि नहीं करना चाहिये लेकिन अगर आप सचमुच कोई काम करना चाहते हैं तो हम प्रशंसा करेंगे। अगर आप मार्केटिंग के लिये 20 करोड़ रुपये का प्राविधान रखते और जिन अधिकारियों को खुश करने के लिये इस प्रकार का आपने कार्य किया है उसको काट देते तो सचमुच आप बधाई के पात्र होते। आप गांवों की बहुत बातें करते हैं लेकिन असल में आप गांवों से चिढ़ते हैं। आप गढ़वाल और कुमायूं के जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यह आप समझ लीजिये ये लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे।

एक सदस्य––

यह गांव के हैं नहीं। टाटा और बिड़ला के लोग बैठे हुए हैं।

एक अन्य सदस्य––

क्या आपकी मंत्री जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल––

मेरी आपसे मित्रता है। मैं जो बहिन जी हैं उनसे कहूंगा कि यहां छैला बनने से कुछ नहीं होगा। जरा वहां के लोगों की छलबलाहट को देखें, वहां की महिलाओं के दुख को देखें जिनकी कमर काम करते करते टूट गयी है। उनकी पीड़ा को समझें। मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं उनकी दर्द की बात कर रहा हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गांवों के लिये कितना रखा है मैं उसको भी बताना चाहता हूं। आपने गांवों के लिए 15 लाख कुल रखा है । अगर हम श्रीकण्ठ खरीद लें 15 लाख रुपये का और किसी पंडित जी से कहें कि इसको घोटो और पहाड़ के आठों जिले के गांवों में जाकर चंदन लगाकर आ जायं तो 15 लाख रुपये का श्रीकंठ भी

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---]

पूरा नहीं पड़ेगा चंदन लगाने के लिये आजकल के जमाने में। और मंत्री जी गांवों के विकास करने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मैं इनके आंकड़े पर कह रहा हूं अगर गलत हों तो यह बता देंगे कि गलत कह रहा हूं। 86 ब्लाकों के लिये 18 लाख रुपया रखा है। गांव में छोटी-छोटी सड़कें बनाते, छोटी-छोटी पुलिया बनाते, लेकिन इन कामों के लिए, गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिये आपके पास पैसा नहीं है। मान्यवर, बी0डी0ओ0 का टी0ए0 भी 12 हजार बनता है। हमारे यहां इस तरह किया जाता है कि रोज ट्रांसफर किए जाते हैं जो पसंद नहीं आया उसको पिथौरागढ़ भेज दिया, जो पसंद नहीं आया देवरिया भेज दिया, यही काम इन्होंने साल भर किया है। इसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। यही एक्टिविटी के काम इन्होंने किये हैं, इसीलिए आप यह कह रहे हैं और मान्यवर, जिला परिषदों को क्या दिया? इन्हें केवल 16 लाख रु0 दिया गया। जो दो लाख पर जिले में पड़ा। मैं आपके ही विवेक पर छोड़ता हूं। माननीय मंत्री जी और सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब आप अपने-अपने जिलों में जायेंगे तो वहां के लोग आपसे पूछेंगे कि आपके क्षेत्र के विकास की क्या रिपोर्ट है, तो आप क्या कहेंगे और इससे आप संतुष्ट हो रहे हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा। हम जानते हैं कि माननीय मंत्री जी से कौन से सुझाव मंत्री परिषद् की मीटिंग में दिये ।

आपको मान्यवर, याद होगा मेरी पिछली रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें भी हमने इस बात को उठाया था। और मान्यवर, 50 लाख रु. शिक्षा विभाग ने सरेंडर कर दिया, तो जहां रु0 खर्च नहीं हो रहा है, वहीं रु0 अधिक दिया जाता है और जहां पर इसकी आवश्यकता है, वहां माननीय मंत्री जी कोई ध्यान नहीं देते। और न ही इन्होंने कोई इतने समय में सड़कें बनवाई, और न ही कोई पुल, जितने भी इस समय सड़कें और पुल वहां हैं, वह सब पुराने हैं और जब चुनाव आता है तो कहते हैं उन्हीं पुरानी सड़कों और पुराने पुलियों और पुलों के बारे में कि हमने बनवाया, वहां पर अपने नाम का तख्ता जड़वा देते हैं, ठीक है, ऐसा करें लेकिन कम से कम गढ़वाल जायें तो सही। और दूसरी बात मान्यवर, यह कह रहा था कि जितनी भी सड़कें पिछले बजट में पास हुयी थीं, इसके संबंध में आपसे पूछना चाहता हूं कि उन सड़कों का जो जी0 ओ0 हुआ था, उसकी एक कापी हमको दे दें। मान्यवर इस संबंध में मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि वह जी0 ओ0 हुए ही नहीं और जब पिछला बजट सेशन था तो 25 तारीख को मैंने जानबूझ कर एक सवाल किया था कि माननीय मंत्री जी एक बात बतायें कि आपके यहां एक छोटी सी पुलिया कितने दिनों में बनती है, तब उन्होंने कहा कि 3-4 साल में बनेगी। तो मान्यवर, जब एक छोटी से पुलिया के बनने में तीन-चार साल लगेंगे तो गंगा का पुल का इसके मंत्री के जमाने में 20-25 साल जरूर बनने में लगेंगे।

श्री बिहारी लाल---

मान्यवर, माननीय सदस्य से कह दीजिये कि यह सदन की भाषा का इस्तेमाल करें। अभी इन्होंने कहा कि इस मंत्री के जमाने में शब्द 'इस मंत्री का' इस्तेमाल किया गया है, जो संसदीय भाषा नहीं है।

श्री कुबेर भण्डारी---

यह पहाड़ी भाषा है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

माननीय बिहारी लाल जी, आप मुझे भाषा न सिखाइये, आपको भाषा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सदन का 1969 से सदस्य हूं। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इस बजट में पूर्वी अंचलों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है,

कोई दिशा-बोध नहीं और कोई सही दिशा बताने की बात नहीं, बल्कि केवल इतनी चर्चा और शोर-शराबा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी ने पिछले बजट में कहा था कि हम स्कूल इसलिये नहीं खोल रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से देख और परख कर काम करेंगे और स्कूल जब खुले तो मान्यवर, उसका असन्तुलन दिखाया, आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। अस्पताल खोलने की बात कही तो वह अस्पताल भी केवल अपने क्षेत्र में खोला, क्षेत्र भी छोड़िये केवल अपने घर के निकट खोला। केवल दहेज के रूप में किया। यह है आपका चरित्र। आपने कहा था कि डिग्री कालेज खोलेंगे, लेकिन इस बजट में कोई डिग्री कालेज का नाम नहीं है। पौड़ी गढ़वाल, रुद्र-प्रयाग, भृगुखाल इत्यादि यह तो पौड़ी गढ़वाल के हैं जिन्हें अनुदान की आवश्यकता है। पंच मढ़ी, खोली रुद्रप्रयाग में मान्यवर, जिनके लिये कहा कि आप बना रहे हैं लेकिन फिर भी इसे नहीं बना पाये। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है और न बढ़ा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में हरिजनों का बहुत रोना रोया है। हरिजनों की बड़ी बात करते हैं, हरिजनों का रुपया भी घसीट कर खा लिया। मान्यवर, वित्त मंत्री जी के भाषण के पृष्ठ 28 पर आप देखें—लिखा है कि सप्लाई आफ दि कम्पोनेन्ट प्लान्ट, उन्होंने बताया कि इसमें केन्द्र की सरकार से 100 करोड़ रुपया सारे प्रान्त के लिये आया है, उसका पांचवां हिस्सा पिछड़े एरिया के लिये, पहाड़ के आठों जिलों के लिये है। इसका पांचवा हिस्सा 20 करोड़ रुपये होता है। पहाड़ों के लिये पांच सालों के लिये मिलना चाहिये था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने बहुत ज्यादा प्रशंसा की कि हमने ये किया और हमने वो किया, इसमें मान्यवर, उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपये रखे हैं केवल बजट में, बाकी रुपया कहां गया? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ हमदर्दी रखने वाली सरकार, हरिजनों के लिये आंसू बहाने वाली यह सरकार, हरिजनों का उत्थान करने वाली यह सरकार, मंत्री जी साफ-साफ बतायें कि जो रुपया केन्द्र से आ रहा है उसको भी आप डकार गये हैं। उसका क्या कारण है? इस पर भी आप कहते हैं कि हरिजनों के लिये हम बहुत कार्य कर रहे हैं।

मान्यवर, इस बजट में महामान्य राज्यपाल महोदय ने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने, हमारे पर्वतीय विकास के राज्य मंत्री जी ने बार-बार इस बात की बात की है कि हम तो इस समय असंतुलन को दूर करेंगे और बजट जो पेश किया गया है मान्यवर, वह देखने के काबिल है। मैं पहले राज्यपाल के अभिभाषण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, उनके अभिभाषण पर पेज 8 पर, 15 और 16 पर देख लीजिये, मैं इसका पक्षधर रहा हूं कि पहाड़ के आठों जिलों में और उसमें भी जो सचमुच पहाड़ के आंचल हैं वहां के लोगों का विकास होना चाहिए।

आजकल मंत्री जी गढ़वाल और चमोली का बहुत दौरा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं।

श्री चारु चन्द्र आझा—

आप भी इस समय जो ऐसा बोल रहे हैं यह भी चुनाव आ रहा है इसलिये।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

जी हां, मैं मानता हूं, मैं कब इन्कार कर रहा हूं। तो मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं कि चुनाव आ गये हैं और चुनाव के आने के कारण से इसमें लिखा हुआ है कि हल्दवानी में 6 करोड़ की सोयाबीन की एक फैक्टरी लगेगी और वह है राज्य-

[समय 1 बजे]

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, यह बकवास शब्द क्या संसदीय है? इसको आप बता दें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, बकवास मैंने नहीं कहा। मैंने जो शब्द प्रयोग किया है उसकी कान्टीन्यूटी को भी देखा जाये।

श्री अध्यक्ष--

इसके पहले इस शब्द का प्रयोग हुआ था और मैंने उसको असंसदीय कहा था और आज अपने भाषण के दरमियान में किसी संदर्भ में अगर उसे प्रयोग किया है तो उसका प्रयोग न करें और अगर होगा तो निकाल दिया जायेगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

इस तरह की जो बातें अलग-अलग कही जाती हैं उनको देखते हुए, उनके कहने के अनुसार बजट को देखते हुए मैं कह रहा हूं कि पेज 8 पर लिखा है कि हल्द्वानी में 6 करोड़ रुपये का एक सोयाबीन का प्लान्ट लगेगा और मान्यवर, नयी मदें जो छपी हैं उसमें खण्ड 3 के पृष्ठ 125(प) पर लिखा है कि जसपुर, विशेष उल्लेख के साथ लिखा है, वह अंचल जहां 5 रुपये का एक किलो नमक आ रहा है, वह पिछड़ा हुआ नहीं है। उनकी परिभाषा में मान्यवर, जसपुर जो बिल्कुल मैदानी क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ है और वहां पर मान्यवर, एक कताई मिल लगा रहे हैं 16 करोड़ रुपये की लागत में। 10 लाख का प्राविधान बड़े कृपालु होकर कर दिया गया है पर्वत के बजट से। सितारगंज में, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कहा था कि सितारगंज में चीनी की फैक्ट्री लगने वाली है 8 करोड़ रुपये की, यह भी जिला नैनीताल की तराई में है, बहुत पिछड़ा हुआ है जहां 5 रुपये का एक क्वींटल आलू सड़ रहा है। वह पिछड़ा इलाका नहीं है? सड़क नहीं जा रही जहां, सितारगंज जहां चारों तरफ से सड़कें जुड़ी हुई हैं, पिछड़ा है और एक चीनी मिल बाजपुर में बन रही है। वहां पर डिस्टिलरी लगाने के लिए रुपया दिया जा रहा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि चुनाव आ गये हैं, नैनीताल जिले में इतना रुपया केवल यही दिखलाने को दिये जा रहे हैं।

मैं साफ पूछना चाहता हूं ऐसी ही कोई योजना गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तर काशी और टिहरी के लिये है? प्रमाण सहित दें। मैं नहीं कहता कि सितारगंज में क्यों किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पहले उन लोगों की चिन्ता कीजिये जिनकी हालत खराब हो रही है। नैनीताल के मैदानी क्षेत्र को इस तरह से आगे बढ़ायें और जहां लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, अपना जीवन किसी तरह से काट रहे हैं, उनके लिये आप चिन्ता न करें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। वहां जाकर के अनेक प्रकार की बातें की जाती हैं। उनसे कहा जाता है और इसकी बार-बार चेष्टा की जाती है कि ऐसा किया जाये लेकिन मैं मान्यवर, आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि आपने जो अपने बजट में सीधे-सीधे हमारे पर्वत के बजट का 59 करोड़ रुपया दबाया है, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं माफी चाहता हूं आपके सामने यह शब्द प्रयोग करने के लिये क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने पूछ लिया था कि हमको आप अपना हिस्सा क्या दे रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय बजट से जो सहायता मिलेगी वही दी जायेगी। 350 करोड़ की सहायता हमको केन्द्र से मिली है तो 350 करोड़ की सहायता जो कहा था, मिलनी चाहिए थी। उन अंचलों को मिलनी चाहिए जहां के लोगों का जीवन बहुत बुरी तरह से वीरान हो चुका है, उनका रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। मैं इसके साथ ही साथ मान्यवर, एक बात और कह देना चाहता हूं कि (किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) यह तो एक किस्म से इनफरमेटिव ही है। आपको जसवन्त सिंह नेगी की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, इसी संबंध

में एक झलकी और देना चाहता हूं। छठी पंचवर्षीय योजना में माइनर इरीगेशन के लिए 37 करोड़ था-अब 6 करोड़ 65 हजार है। स्वायत्त शासन के लिए 6 करोड़, 8 लाख है। इसी तरह से जल निगम के लिए 90 करोड़ था-अब 6 करोड़, 75 लाख है। इस प्रकार कुल जो 352 करोड़ था-वह 63 करोड़ 68 लाख है। इस तरह से सारे बजट का 64 प्रतिशत 5 विभागों को मंत्री जी ने बांट दिया है।

बिजली विभाग का यह हाल है कि पता नहीं यह रुपया देते हैं और खत्म हो जाता है। आज तक कोई भी माननीय सदस्य इस बात को कह दे कि बिजली वहां ठीक हुई है? इसी तरह से जल निगम की बात है। जल निगम में जो पैसा दिया जाता है सारा का सारा पर्वतीय क्षेत्र का पैसा उसके लिए जाता है। पानी की योजना भी सफल नहीं हुई है। इरीगेशन के रोड्स के बारे में इन्होंने पी0 डब्लू0 डी0 से इंजीनियर्स सारे भगा दिए हैं तो रोड कैसे काटें और जैसा कि मैंने अभी बताया पिछले साल की रोड्स का अभी तक जी0 ओ0 ही नहीं हुआ कि रोड कब तक बनेगी। एक सबसे अच्छा व्यक्ति इन्जीनियर जरूर है लेकिन उसको काम नहीं करने दिया जाता है। उसको मंत्री जी अपने साथ गाड़ी में लेकर घूमते हैं। मेरी जानकारी है कि वह पी0 डब्लू0 डी0 की गाड़ी में पौड़ी तक गया और जब गाड़ी खराब हो गयी तो फारेस्ट की गाड़ी में गया उसके बाद फिर पी0 डब्लू0 डी0 की गाड़ी में गया। इस प्रकार जो मंत्री जी के लग्गे भग्गे हैं सारे वहां मंत्री बने हुए हैं। मान्यवर, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं इन्होंने कहा कि हिल डेवलपमेन्ट की एक योजना बना रहे हैं। मान्यवर, दो मिनट और लूंगा। मान्यवर, इन्होंने आखिर में कहा हुआ है। बड़ा भारी करिश्मा दिखाया है। कहा है हम हिल के लिए प्लानिंग इन्सटीट्यूट फार हिल्स बनायेंगे। अहा, बड़ी भारी खोज निकाल ली। मान्यवर, जो दिल्ली में बैठा हुआ है हिल्स सैल उसने कौन सा तीर मार दिया। आप यहां फिर सैल बनायेंगे हमारा रुपया लगा करके यह कर रहे हैं। मान्यवर, आपकी जानकारी में होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विभाग भी है जो इवेल्यूएशन करता है मूल्यांकन करता है। 36 रिपोर्ट्स उसकी अब तक छप गयी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितनी रिपोर्टें उनमें से आपने पहाड़ के बारे में पढ़ी हैं। यह निर्णय करने से पहले क्या माननीय मंत्री जी ने उन रिपोर्टों को पढ़ा? जितनी रिपोर्टें हैं उन पर काम नहीं हो रहा है। निर्णय कैसे होगा। एक आदमी ने कह दिया कि पुल चार साल में बनेगा और माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि पांच साल में बहुत जल्दी बन रहा है। इस तरह के करिश्मे, मान्यवर, अगर इस प्रदेश में होते रहेंगे तो लखनऊ में बैठने वाले लोग पहाड़ का विकास नहीं कर सकते। हम लोग जो पर्वतीय विकास परिषद के लोग हैं, हमने पहले भी अपनी सेवाओं के लिए कहा था कि माननीय मंत्री जी के जितने निर्णय होते हैं आप तमाम एम0 एल0 एज0 को बुला कर उनकी टीम बनायें, उनसे राय लें लेकिन आपने कभी इसकी आवश्यकता नहीं समझी। इसकी कोई आवश्यकता आपने नहीं समझी। आपको तो प्यारा अधिकारी है। चाहे वह अधिकारी कह दे कि इस समय दिन है तो आप कहते हैं दिन है, अगर वह कह दे कि रात है तो आप कहते हैं रात है। इस तरह से कभी पहाड़ पर रात हम होने नहीं देंगे। इस तरह की अंधेरगर्दी हम पहाड़ के लिए होने नहीं देंगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बजट उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया है, वह उन्हीं की नीतियों के खिलाफ है। मान्यवर, जो प्लानिंग कमीशन ने 15 प्रतिशत का वेटेज दिया था, हमको मिलना चाहिए। 18 करोड़ रुपये का हमारा बजट होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी अगर चाहते हैं कि सचमुच

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---]
पहाड़ में कुछ काम हो, मेरा आपसे नम्र निवेदन है इस बजट को आप वापस ले लें, दूसरे दिन, दूसरा बजट ठीक ढंग से, उतने रुपये और लेकर, प्रस्तुत करें ताकि हम उसमें सहयोग दे सकें।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सब अपने विचार व्यक्त करें और इस चर्चा को आगे बढ़ायें।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पर्वतीय विकास के बजट पर मुझको बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट के समर्थन में बोलना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय को कई चीजों में तो मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं ताकि उन चीजों की ओर हम अपना ध्यान दें।

सुझावों में सबसे पहले यह है जिसके लिये मैं उनको मुबारकबाद दूंगा वह तो है धनराशि का इजाफा होना। इस साल काफी धनराशि में बढ़ोत्तरी हुई। जैसी कि हिमांचल प्रदेश को मिल रही है उससे भी हमारे यहां बजट ज्यादा मंजूर हुआ। मगर इसके साथ ही साथ मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि बजट तो बढ़ रहा है मगर कार्य रूप में पर्वतीय प्रदेश में प्रगति कुछ नहीं दिखलायी दे रही है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जैसे केन्द्रीय सरकार ने, प्लानिंग कमीशन ने, तय किया है कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के मुताबिक सब जगह की प्रगति की जाय उसी आधार पर जो पर्वतीय प्रदेश हैं, उसके लिये भी योजनायें बनी थीं, मगर देखने में यह आया है कि अब तक इस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के (इस समय 1 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।) अन्तर्गत कुछ दिखायी नहीं दे रहा है। यह समझ में नहीं आता है कि इस इलाके को क्यों अब तक तिरस्कृत समझा जा रहा है।

हिल कैडर जो शिक्षा विभाग में बनाया गया है उसकी भी मैं तहेदिल से तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि होता यह आया है कि पर्वतीय प्रदेश के लोगों को जो भी वहां से क्वालिफाइड हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, प्लेन्स से लोग नौकरी हासिल करने के लिये वहां जाते थे और जाने के बाद हमेशा वहां से ट्रांसफर की कोशिश करते थे। इस तरह से बहुत से स्थान रिक्त रह जाने से बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता था और वहां के लोगों को कोई रोजगार भी नहीं मिलता था।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जियोलौजिकल सर्वे की नितान्त आवश्यकता है। मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे जितनी जल्दी हो सके सारे पर्वतीय क्षेत्र के मिनरल रिसोर्सेज का सर्वे कराने की कृपा करें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी कई बातें इस तरह की सामने आई हैं। गंगोली-हाट में एक सीमेन्ट फैक्टरी बनाने का विचार हो रहा था लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पिछले बजट में काफी बड़ी धनराशि इस हेतु मंजूर की गई थी। इसलिये मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें। दैवलथल में भी एक मैग्नीसाइट माइन बनाने की बात चली आ रही है। उस दिशा में भी प्रगति बहुत कम है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। सबसे बड़ी चीज जो मैंने इस बजट के दौरान सुनी वह यह है कि इरीगेशन के लिये पंचेश्वर डैम की मंजूरी कर ली गई है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसकी ओर विशेष ध्यान देंगे। यह इस इलाके के लिये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा।

डाक्टर धर्मपाल---

मान्यवर, माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता––

यह कोई आपत्ति की बात नहीं है। भाषण पढ़ा नहीं जा सकता है। उसकी सहायता ली जा सकती है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट––

मान्यवर, चम्पावत तहसील के बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, चम्पावत तहसील ऐसी है कि जब यह अल्मोड़ा जिले के साथ थी उस समय इसमें साधारण प्रगति हो रही थी लेकिन जब उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले बने और यह चम्पावत तहसील पिथौरागढ़ जिले के अन्तर्गत आयी तो उस वक्त से इसकी प्रगति का पैटर्न धीमा हो गया। तब से इसको कोई लाभ उसका नहीं मिल सका। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे ताकि यह जो पिछड़ी हुई तहसील है, उसके लिये कुछ कार्य किये जा सकें। मान्यवर, इसके अलावा 2/4 अन्य बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले हिल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिला करती थी वह अब नहीं मिल रही है। चीजों की महंगाई बढ़ गई है जिसके कारण वहां पर दुकानों में सामान नहीं मिलता है। चावल, सीमेन्ट, किरोसिन आयल, डीजल आयल की भारी कमी है जिससे वहां लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज फुट आर्चाल्ड स्कीम आदि में कोई प्रगति नजर में नहीं दिखाई दे रही है। इसी तरह से वहां रोड्स एन्ड ब्रिजेज की हालत है। वह भी स्टैंड स्टिल दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी का काम भी धीमी प्रगति से हो रहा है। डिंकिंग वाटर की भी कोई ठोस योजना नहीं है। इसी तरह से स्कूल और हास्पिटल का काम भी धीमी रफ्तार से चल रहा है। स्वायल इरोजन और दरख्तों के कटान का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है और कहा जाता है कि एफारेस्टेशन का काम भी तेजी से हो रहा है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कहीं एफारेस्टेशन का काम हो रहा हो।

ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर रात दिन एक्सिडेन्ट हो रहे हैं और उसमें काफी लोग मर चुके हैं। मेरा सुझाव है कि ब्रेक खराब होने पर वहां गाड़ियां नहीं चलायी जानी चाहिये। काफी जानें खतरे में आ चुकी हैं। फाइव इयर प्लान के लिए पहले कहा जाता था कि वहीं पर उसे बनाने के लिए सेमीनार होंगे और उसमें वहां चर्चा होगी जिसके आधार पर विकास योजनायें बनेंगी। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले एक साल के अंदर कोई भी सेमीनार अभी तक वहां नहीं हुआ।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपने एक चर्चा की थी वहां कहा जाता है कि एक घड़ी का कारखाना लगेगा तो आशा करता हूं कि कुमायूं में कहीं पर घड़ी बनाने का कारखाना लगाने की ओर भी ध्यान देंगे ताकि वहां काफी लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय बिष्ट जी, आपका दो मिनट का समय रह गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट––

एक सबसे जरूरी बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा तेजी से बढ़ रही है, मेरे जिलों में दो डिग्री कालेज बन गये और काफी लोग डिग्री प्राप्त कर चुके हैं मगर वहां पर इम्प्लायमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है, गरीबी रातदिन बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि समाजवादी समाज के

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---]

ढांचे में बेकारी और गरीबी का नाम नहीं रहेगा, मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह चीज वहां बढ़ती जा रही है। लोग जितना उनके पास धन होता है उसको पढ़ाई में खर्च करने के बाद बेकार होकर इधर-उधर धक्के खाते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी और कोई ठोस योजना पर्वतीय क्षेत्र के लिये वहां की उन्नति के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए बनायेगी अन्यथा इन थोड़े से कामों से पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं का कोई हल होने वाला नहीं है। इतना कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, आज पर्वतीय विकास का जो मसला है वह इस माननीय सदन के बीच आज पेश है। मुझे यह देख कर तकलीफ हुई कि इस माननीय सदन में बहुत थोड़े माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल वह क्षेत्र है जिसके बारे में पं0 नेहरू ने जब कांस्टिटुएंट एसेम्बली में डिबेट हो रही थी तो कहा था फस्ट थिंग कम्स फस्ट एण्ड इज डिफेंस आफ दि कंट्री यानी सबसे पहले वह चीज आये जिसमें देश की सुरक्षा हो। तो देश की सुरक्षा के संबंध में अगर बात आये तो उत्तर प्रदेश सीमा सबसे पहले सामने आती है। हमारे इस अंचल में 20 अक्तूबर, 1962 को चीन ने आक्रमण किया था उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने ध्यान दिया। वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है वहां रास्ते नहीं हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे मिलिट्री डिपार्टमेंट को देकर वहां के लिए रास्तों तथा दूसरी चीजों के लिए विचार किया और उसी आधार पर कुछ विकास प्रदेश सरकार की ओर से शुरू हुआ। श्रीमन्, यह जो किताब मिली है, उसकी ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो एवरेज इनकी पैदावार है 1976 की चावल की, वहां पर हेक्टेयर 14.13 क्विंटल है और आपने 5 साल में जो बढ़ोतरी की है न मालूम उसमें कितनी लागत आपने लगा दी और वह बढ़ कर केवल 15.90 पर पहुंची है यानी डेढ़ क्विंटल पर हैक्टेयर की वृद्धि हुई। तो यह कोई अच्छी प्रगति नहीं है।

गेहूं की पैदावार 1977 में 13.01 क्विंटल पर हैक्टेयर थी, वह 1980 में घट कर 13 क्विंटल ही पर हैक्टेयर रह गयी। इसमें मैं इस चीज को भी जोड़ता हूं कि जो नैनीताल जिला आपने शामिल किया है, जिसमें आपका जसपुर से लेकर पीछे तक जो तराई का इलाका है, वह भी इसमें आता है। यह इलाका ऐसा है जो अमेरिका और रूस के मैदानी इलाकों का मुकाबला कर रहा है जहां गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। तो वह रकबा भी इसमें शामिल है। तो नैनीताल जिले के गन्ने और सीरियल्स को उसमें शामिल कर रहे हैं तब यह एवरेज आपका आ रहा है। यदि आपने कहीं उस एरिया की पैदावार को माइनस कर दिया होता तो सही स्थिति सामने आती कि पर्वतीय क्षेत्र में आपकी क्या पैदावार है तो आप ईमानदारी के साथ यदि पहाड़ी क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो जिसके अन्दर बद्रीनाथ, केदारनाथ, बागेश्वर, गंगोत्री, जमुनोत्री है और जिस क्षेत्र में कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नन्द प्रयाग और विष्णु प्रयाग हैं, कौशानी और बेरीनाग हैं--वे स्थान असली पहाड़ी क्षेत्र हैं और आप उनके विकास की बात सोचें। बाजपुर, खटीमा, रुद्रपुर, किच्छा और हल्द्वानी यह पहाड़ी क्षेत्र नहीं हैं और देहरादून पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। तो या तो आप इस मैदानी इलाके को पहाड़ी क्षेत्र से निकाल दें या फिर ऐसी बात न कहें। और मैं तो यह भी कहूंगा कि आप यह नैनीताल और देहरादून दोनों जिले निकाल दीजिए। इनमें दोनों में अट्रेक्शन की चीजें हैं, उन पर कुछ रुपया खर्च किया जाय या न किया जाय, यह तो अपने से ही अपना पूरा विकास कर लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब आप उस एरिया को देखें, जिसके अन्दर बिजनेस प्वाइन्ट आफ व्यु से बागेश्वर-मेला, गोचर मेला और जालजीवी तीन मेले लगते हैं। यह सारे उस एरिया के बिजनेस केन्द्र हैं, आपने इन तीनों मेलों को अपने सारे निगमों द्वारा कितनी तरक्की दी है, इस पर भी आप देख लें। अब इस वक्त जो आपका तमाम खर्च है वह कुमायूं, गढ़वाल और जनजाति निगमों पर है। यहां यह तमाम निगम भी काम कर रहे हैं और आपकी सरकार भी काम कर रही है। इन सारी चीजों के बावजूद चले जाइये आप कर्ण गंगा के किनारे-किनारे, अलखनन्दा और भागीरथी नदियों के किनारे-किनारे, सारी सड़कें, नदियों के किनारे-किनारे बनी हैं और यदि कहीं आदमी नदी पार जाना चाहे तो पुल न होने की वजह से 50-50 मील का चक्कर काटकर एक मील का उसका रास्ता पूरा होगा। तो इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि नदियों पर यथासम्भव पुलों का निर्माण कराया जाए। अब आप देखिये, सबसे बड़ी चीज यह है आदमी कैटिल पालता है, सफा 15 पर पशुधन के बारे में आप देखिये। सन् 1952 में कुल 21.9 लाख यह था, 77 में घटकर 20.28 लाख रह गये। जो वहां की मूल चीज है वह कैटिल वेल्थ, वहां आपका घट गयी है। इस चीज की ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब वहां पर दो चीजों की तरक्की की बड़ी जरूरत है। जो वहां लोकल प्रोडक्शन है, उसके आधार पर लोकल इंडस्ट्रीज जो उन से संबंधित हैं, एक तरफ भोटिया लोग उन की तिजारत करते हैं। आज भी उनके घरों में जाकर देखें और आपने मुझसे ज्यादा देखा होगा, तो उनके घरों की औरतें आज भी उनी पट्टी को उसी तरह से बुनती हैं, जैसे पचास साल पहले बुनती थीं। आज तक उसमें कोई विकास नहीं हुआ है, आधुनिक औद्योगिक उन्नति का उन पर कोई असर नहीं हुआ है।

मैदानी क्षेत्र के जो हमारे अंसारी बुनकर भाई हैं अब इस वक्त अगर कोई गिरे से गिरा भी खड्डी चलाता है तो उसमें भी तेजी आयी है और अगर वह पावरलूम लगा लेता है तो वह काफी तरक्की कर गया लेकिन पहाड़ के जो भोटिया लोग काम करते हैं वहीं के वहीं हैं। एक तो मुकामी तौर से आप उनके उन को प्रोड्यूस करने के लिये कोई सहायता नहीं दे रहे हैं जिससे वे भेड़ें वगैरह पाल सकें और न उनके लिए आपने कोई इन्टैग्रेटेड स्कीम ही चालू कर रही है। अगर उन्होंने भेंड़ें पाल भी रखी हैं तो आपके वन विभाग ने प्रति हेड टैक्स ही बढ़ा दिया है। तो आपको वहां पर एक इन्टीग्रेटेड प्लान को चलाना होगा ताकि देख सकें कि जितने लोग भी वहांपर रहने वाले हैं चाहे बोक्सा हों या भोटिया हों, उन सबका विकास कैसे हो? देहरादून के माइग्रेटिरी लोग हैं, वे अपने मवेशियों को लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। उनको भी वन विभाग के लोगों को फेस करना पड़ता है। यह भी देखने में आया है कि माना और नीति के लोग 6 महीने ऊपर और 6 महीने नीचे रहते हैं। जब वे अपने रहने के स्थान पर वापस जाते हैं तो जहां पर वे अपने मकान छोड़कर आये थे, वे उन्हें टूटे हुए मिलते हैं। उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। वे लोग अपनी भेड़ बकरियों पर कुछ गल्ला और एक-एक या दो-दो किलो नमक लाद कर ले जाते हैं लेकिन उन्हें अपने घर टूटे हुए मिलते हैं।

पहाड़ी क्षेत्र में जो आपने 6 ब्लाक बढ़ाये हैं, यह अच्छा काम है लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं कि वे किस हद तक काम कर रहे हैं। जो माइग्रेटरी लोग हैं जब वे अपने अपने स्थानों पर जायें तो इन ब्लाकों के बी0 डी0 ओज0 की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके लौटने पर उनके सामने रहने का मसला न खड़ा हो। खाने की तो कुछ चीजें वे अपने साथ ले ही जाते हैं।

[श्री रियासत हुसैन---]

आपने यह भी कहा कि आप उस एरिया में 29 पर्यटक स्थान बना रहे हैं लेकिन पता नहीं कि वर्ष 1981-82 में कितने स्थान बन पायेंगे, अगर आप ये सब बना दें तो आपकी बहुत तरक्की हो जानी चाहिए।

जिस एरिया को आप डील कर रहे हैं उसमें 4.3 प्रतिशत प्रदेश की पापुलेशन है लेकिन एरिया 17.4 प्रतिशत है। कितनी-कितनी दूर पर आबादी है कितनी दूर पर छोटे छोटे गांव हैं, उनका विकास कैसे होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह देखें कि वहां पर जो जनजाति निगम है उसका हैड आफिस देहरादून में है। चमोली के पास का रहने वाला जो भोटिया है आप सोचें कि उसे निगम से कुछ सहायता लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा देहरादून जाने और वहां से वापस आने में। यह भी जरूरी नहीं है कि एक दफा में ही उसका काम हो जाय। इसलिए उसे आपको डिसैन्ट्रलाइज करना चाहिए और उसे ऐसे स्थान पर रखिये जिससे किसी भी गांव के आदमी को 25-30 किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े जिससे वह एक दिन में जाकर अपना काम करा आये और रात अगर उसे बितानी पड़े तो अगले दिन सुबह को घर आ सके। लेकिन देहरादून वाले को 4 दिन चाहिए फिर भी यह गारन्टी नहीं है कि उसको पैसा मिल सकेगा या नहीं। आप कोई ऐसा इन्तजाम करिये कि जिससे उन लोगों को पैसा आसानी से मिल जाया करे। उस चीज की जिम्मेदारी आपकी है।

आजकल मान्यवर, साइन्टिफिक युग का जमाना है और हर आदमी खूबसूरती और अच्छाई को देखता है। जो आपके यहां यह लोग ऊनी माल बनाते हैं उसमें वह चमक दमक नहीं आती जैसी कि मिल के कपड़े में आती है। इसलिये वे बाजार में कम्पीट नहीं कर पाते। गांधी आश्रम वालों ने तो कुछ क्वालिटी इम्प्रूव की है, पर आपके यहां के लोग उसे नहीं कर पाये हैं। इस चीज की भी आप की जिम्मेदारी है, आप इसे देखें कि उनके माल की क्वालिटी इम्प्रूव हो।

बेरीनाग को भी आप डेवलप कर सकते हैं। वहां की चाय बहुत अच्छी होती है। मगर उसका यहां पर मार्केट नहीं है। आज अगर लखनऊ और मुरादाबाद में कोई बेरीनाग की चाय चाहे तो उसे नहीं मिलेगी, उसे तो वहां आसाम की चाय मिलेगी, इसलिये कि आपने बेरीनाग की चाय का यहां पर मार्केट नहीं बनाया है। आप उसे डेवलप कीजिए और उसको यहां के मार्केट में लाइये। अगर वहां की चाय आसाम की चाय से उन्नीस भी हो तब भी हमें उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से कि हम गांधी आश्रम के कपड़े को पहनते हैं। अगर आप गांधी आश्रम के कपड़े को तरजीह दे सकते हैं तो बेरीनाग की चाय को भी दे सकते हैं। वह देना चाहिये।

हमारे पहाड़ों पर कुछ एट्रेक्टिव प्लेसेज हैं जिनको और आकर्षक बनाने की जरूरत है। आज पर्यटक नैनीताल, मसूरी या बहुत हुआ तो देहरादून आदि स्थानों पर ही जाकर लौट आता है। अगर आप पंचाचोटी, त्रिशूल, पिन्डारी ग्लेशियर और कोसानी आदि स्थानों को आकर्षक बना दें, तो भारी संख्या में पर्यटक वहां जायेंगे। बम्बे और कलकत्ता का पर्यटक आज वहां पर कोई आकर्षण न होने के कारण नहीं जाना चाहता। इसलिये आप इस तरफ ध्यान दें।

एक बात मैं और कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। ताकलाकोट या बारा-होती आदि जो स्थान हैं, जहां पर कि विदेशी हमले का खतरा बना रहता है, यहां के विकास की ओर भी आपको देखना होगा। उस एरिया की गरीबी को दूर करने के लिये भी आपको प्रयास करना होगा, अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो उनको यह मौका देंगे कि वे लोग अलग प्रदेश की मांग करें। हम यह चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप उनको यह मौका न दें कि वे यह कहें कि हमारी स्टेट अलग बनायी जाये। आप ऐसी हवा पैदा कीजिये जिससे कि उनमें ऐसी फीलिंग न आये। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री द्वारिका नाथ धवन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने के लिए मुझे अनुमति दी। सबसे पहले तो पर्वतीय विकास का कोई विभाग है या नहीं, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। इसलिए कि हम बजट तो लम्बा-चौड़ा रखते हैं, हम बात तो हिमांचल के बराबर की करते हैं लेकिन इसका कोई सेल बनाया है योजना का, पर्वतीय विकास के लिए एक सेपरेट कि उस पर्वतीय वातावरण में वह प्लानिंग बन सके, योजना बन सके, वह है ही नहीं। तो हम प्रगति क्या करेंगे? सिर्फ रोड बनाने से या बगैर छत के स्कूल खोल देने से प्रगति नहीं होगी। वहां के लोग जो हैं, वह आज तक फौज में भर्ती हुए या सर्विस करते रहे। हिमांचल की हम कम्पेयर करते हैं। हिमांचल की रुचि दूसरी है। वहां फौज में दूसरे लोग जाते हैं। वहां के लोग हार्टिकल्चर में ज्यादा रुचि लेते हैं। हमारे यहां हार्टिकल्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहां पर्वतीय विकास का कोई आफिस भी नहीं है। हमारे मंत्री को एक सचिव दिया गया है और एकाध अधिकारी और दे दिया गया होगा। पर्वतीय विकास में विभागों का कोई कोआर्डिनेशन नहीं है? अगर हम ईमानदारी से पर्वतीय क्षेत्र की प्रगति चाहते हैं, तो इसे हमें ध्यान रखना होगा कि वहां के लोगों की रुचि क्या है। उनकी रुचि पर ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त वहां की वायुमंडल में क्या पैदा होगा, उस पर भी ध्यान रखना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे साथी बोल रहे थे, बहुगुणा जी के साथी, तब उन्होंने बहुत कुछ किया। जब बहुगुणा जी यहां पर मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने वहां पर गढ़वाल मंडल में केवल पत्थर लगाया।

(व्यवधान)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

नारायण दत्त जी ने ज्यादा लगाया। पहले उनका हिसाब लगा लीजिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नौटियाल जी, आपको फिर समय मिलेगा, तब आप अपनी बात कहियेगा।

(व्यवधान)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, हमारे ऊपर इंगित किया जाता है। हमें बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपको अधिकार है। लेकिन आपको बोलने का अधिकार फिर भी मिलेगा।

(व्यवधान)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मेरी और माननीय सदस्य इंगित करें और मैं यहां पर उपस्थित हूं और मैं उत्तर न दूं, यही आपकी कुर्सी की तरफ से व्यवस्था होगी। इन्होंने इस प्रकार का प्रश्न उठाया जो कि इनको नहीं कहना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नौटियाल जी, आपको अपने भाषण में इसका उत्तर देने का पूरा अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री द्वारिका नाथ धवन—

आप भी यहां पर मंत्री रहे। बहुगुणा जी यहां पर मुख्य मंत्री रहे। केन्द्र में फाइनेन्स मिनिस्टर रहे। पहाड़ों के विकास के लिए केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा, लेकिन आपने न सोचा और न बहुगुणा जी ने सोचा।

(व्यवधान)

पर्वतीय क्षेत्र के लिए मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि वहां पर हार्टिकल्चर पर विशेष ध्यान दिया जाय। वहां पर उन उत्पादन के लिए अच्छी भेड़ें दी जायें ताकि वहां पर अच्छा ऊन पैदा हो और वहां के लोग काम कर सकें। मछली पालन और टूरिज्म के ऊपर बात कही जाती है। आज तक टूरिज्म के ऊपर कितना बजट आया। टूरिस्ट बंगले कितने हैं। बम्बई से चला आदमी का पता नहीं कितने गढ़वाल और कुमायूं मंडल में टूरिस्ट बंगले कहां हैं। प्रचार जब तक नहीं होगा उसे मालूम नहीं हो सकेगा। उसे मालूम होना चाहिये कि देहरादून के बाद मंसूरी और मंसूरी के बाद उसे कहां-कहां जाना है। हार्टिकल्चर के लिये कौन सी हाइट पर आलू, सेब, माल्टा, संतरा, नासपाती का दरख्त होगा, किसी ने इसका आज तक कहां सर्वे नहीं कराया। वहां जड़ी बूटियां होती हैं लेकिन वहां वाले नहीं जानते और लोग बंगलौर से आकर ले जाते हैं।

हिमांचल की बात की जाती है। हिमांचल में अगर किसी को पेड़ लगाने हैं तो हार्टिकल्चर वाले आयेंगे, स्वालय टेस्ट करेंगे और बतलायेंगे कि इस जगह क्या लगेगा और सबसिडी देंगे। देहरादून में लीची खत्म हो रही है लेकिन पंजाब में होशियारपुर में डेवलपमेंट होता जा रहा है। वहां सबसिडी मिलती है। हार्टिकल्चर वाले इन्स्पेक्टर की ड्यूटी है लेकिन यहां किसकी ड्यूटी है। इन्स्पेक्टर और डायरेक्टर यहां क्या कर रहे हैं? इसका कुछ पता नहीं चलता कि ब्यूरोक्रेसी पर्वतीय क्षेत्र के लिये विकास का क्या कार्य कर रही है? विकास केवल इस तरह से नहीं होगा कि हमने स्कूल खोल दिये। 5 लड़के बैठे हैं तथा चार टीचर हैं। हमने गढ़वाल यूनिवर्सिटी खोल दी। उसमें 12 हजार के लगभग स्टूडेन्ट हैं। जबकि 9 हजार स्टूडेन्ट देहरादून में हैं। श्रीनगर में उसका हेडक्वार्टर है जहां स्टूडेन्ट्स नहीं हैं। वहां का वाइस चांसलर जनता पार्टी की सरकार ने एक नायब तहसीलदार को बना दिया जिसका एजूकेशन से कोई ताल्लुक नहीं था। वह स्टूडेन्ट्स को क्या एजूकेट करेगा? यह सिफारिश की गयी कि यूनिवर्सिटी को 2 करोड़ रुपया दिया जाय लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन उसे रिकगनाइज नहीं कर रहा है। लड़के पास हो भी जायें तो दिल्ली में नौकरी नहीं मिल सकती।

यूनिवर्सिटी की हालत यह है कि देहरादून के लड़कों के अभिभावकों को पचासों चक्कर काटने के बाद भी बी. ए., एम. ए. की डिग्रियां उन्हें तीन साल से नहीं मिल रही हैं। कालेज देहरादून में 7 रोज से बन्द पड़े हैं। रोज झगड़े हो रहे हैं। जो लड़के लायक थे। पिछले तीन साल से जिनका रिकार्ड था फर्स्ट और सेकेन्ड डिवीजन में पास होने का था उनको फेल कर दिया गया और जो नालायक थे उनको पास कर दिया गया। इस तरह से वहां हंगामा हो रहा है। रजिस्ट्रार का कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार का कार्यालय तथा कालेज का कैम्पस देहरादून में न होकर श्रीनगर में है तो यूनिवर्सिटी केवल श्रीनगर के लिये तो नहीं है, गढ़वाल मंडल के लिये भी है इसलिये देहरादून में कार्यालय तथा कैम्पस खुलना चाहिए। देहरादून को गढ़वाल में लाने के लिये मेरठ से अलग किया गया बहुगुणा जी के जमाने में लेकिन आज उसकी क्या दुर्दशा हो रही है? वह आसमान से गिर कर खजूर में अटक गया। वह न गढ़वाल में है, न मेरठ में है। मैं पूछना चाहता हूं कि देहरादून जिले को क्या अनुदान दिया गया और अन्य 7 जिलों को क्या अनुदान दिया गया? उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मेरठ से निकाल कर देहरादून को मेरठ वाले भी नहीं पूछते

और अब गढ़वाल वाले भी नहीं पूछते। देहरादून को आज गढ़वाल मंडल का द्वार कहा जाता है। लाखों टूरिस्ट आते हैं। मसूरी जाते हैं, बदरीनाथ तथा केदारनाथ जाते हैं लेकिन देहरादून की दुर्दशा को सुधारने वाला कोई नहीं है। आज देहरादून में टूरिस्ट डर के मारे नहीं आता है। वहां पर गुण्डों का राज्य हो गया है।

(शेम. . . . शेम की आवाजें)

यह हालत है देहरादून शहर की। मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि क्या विकास करेंगे हम, जब टूरिस्ट का दम घुट जाय। अगर उसकी गाड़ी वहां चोरी हो जाय वह वहां लुट जाय तो वह टूरिस्ट क्यों आयगा।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री द्वारिका नाथ धवन––

मान्यवर, मैं दो मिनट और लूंगा।

श्री अधिष्ठाता––

दो मिनट नहीं, आप एक मिनट में अपनी बात कहिए।

श्री द्वारिका नाथ धवन––

देहरादून एक माननीय मंत्री जी गये थे, उन्होंने एक स्पोर्ट्स कालेज का एलान किया। मैं पर्वतीय विकास मंत्री से चाहूंगा कि इस ओर ध्यान देकर घोषणा करें। देहरादून में, जहां स्पोर्ट्स होते हैं, वहां स्टेडियम नहीं है। गोचर में 31 लाख का स्टेडियम बन रहा है तथा देहरादून में नहीं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके अलावा फारेस्ट आफ "वुड" पर क्यों नहीं ध्यान देते? आपने निगम बना दिये, कुमायूं निगम बनाया, गढ़वाल निगम बनाया, जनजाति निगम बनाया, इन निगमों ने क्या किया? ये केवल सफेद हाथी की तरह हैं मेरठ और जालन्धर में स्पोर्ट्स का सामान बन सकता है, आपके यहां से लकड़ी जाती है, तो हमारे यहां क्यों नहीं बन सकता? करोड़ों रुपये का स्पोर्ट्स का सामान बनता है तथा एक्सपोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त देहरादून में हास्पिटल है। देहरादून की आबादी बढ़ गयी है तथा यही हास्पिटल पूरे गढ़वाल मण्डल को देखता है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां आप इतने हास्पिटल्स खुलवा रहे हैं क्या 200 बेड वाला एक हास्पिटल देहरादून में भी खुलवा सकते हैं? इसके अतिरिक्त जोशीमठ में जो रोपवे लगनी थी, रोक दी गयी, जो स्विटजरलैण्ड का नजारा दिखाती। दूसरी तरफ जायें तो गढ़वाल मण्डल में 1 करोड़ रुपया उसका एडवान्स दिया हुआ है। इसकी तरफ मन्त्री जी ने क्या किया। बंधुआ मजदूर देहरादून में सबसे ज्यादा हैं जो कि मंत्री जी ने कहा कि उत्तर काशी में ज्यादा हैं इसका सर्वेक्षण करायें तथा देहरादून के बंधुवा मजदूरों की ओर ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री द्वारिका नाथ धवन––

इसके साथ ही मान्यवर, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। और आपका आभार प्रगट करता हूं।

श्री विद्या सागर नौटियाल––

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रगट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मेरे लिये आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और मैं अपने को धन्य

[श्री विद्या सागर नौटियाल–]

समझता हूं कि आज मैं सदन में माननीय चन्द्र मोहन सिंह नेगी जी को देख रहा हूं। एक मुद्दत हुई हम उनके दर्शन के लिये तरस रहे हैं–

मुद्दत हुई है यार को मेहमां किए हुए,
जोशे कदह से बज्म चरागां किये हुए।

चन्द्र मोहन हैं, चन्द्रमा को मोहित करने वाले और मैं हूं "सागर"। मंत्री जी ने कई बार कहा कि मैं खुश हूं, उनको हर्षित देखकर मेरा मन खिल जाता है और मेरे दिल में कविताओं का ज्वार-भाटा उठ रहा है–

कोई उम्मीद बर नहीं आती,
कोई सूरत नजर नहीं आती,

पौड़ी उप चुनाव का एक दिन मुअइन है,
आपको नींद क्यों रात भर नहीं आती।

मान्यवर, पिछले साल मंत्री जी ने बजट पेश किया था, मंत्री जी लगातार बोलते रहे कि 86 करोड़ रुपये का बजट है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल ने हिसाब लगाकर बताया कि 76 करोड़ का है और 86 करोड़ का नहीं है। आज मंत्री जी ने बजट पेश किया और 16 करोड़ रुपये गायब हो गये। मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है या मेरी गणित ठीक नहीं है कि मंत्री जी कह रहे हैं कि एक अरब रुपये का बजट है और जबकि मेरे हिसाब से अनुदानों में यह मांग रहे हैं 84 करोड़ 92 लाख और 68 हजार रुपये तो 16 करोड़ रुपये यह कहां जायेंगे, जो चुनाव होने वाले हैं उसमें या और कहीं? पिछले साल मंत्री जी ने जो बजट पेश किया 86 करोड़ रुपये का उसमें से कम से कम मेरे जिले में एक भी पैसा अभी तक नहीं खर्च हुआ है। मैंने इस संबंध में राज्यपाल के अभिभाषण में यही बात कही थी और आज भी कह रहा हूं कि पहले मंत्री जी ने मेरे जिले में बी.टी.सी. के केन्द्र बंद कर दिया जबकि आज भी मेरे जिले में 192 बेसिक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इसलिये मंत्री जी से निवेदन किया था कि उस ट्रेनिंग सेन्टर को बंद न करें।

मान्यवर, हमारे जिले में डिग्री, इन्टर, हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल सभी में पूरे अध्यापक नहीं हैं। मंत्री जी ने जून में कार्यभार संभाला और जून के दूसरे हफ्ते में पौड़ी निर्वाचन-क्षेत्र में रहने वाले अध्यापकों और राजकीय कर्मचारियों के ट्रान्सफर करने शुरू कर दिये थे चूंकि चुनाव होना था लेकिन जब हल्ला मचा तो अब फरवरी, मार्च में टेहरी में बड़े पैमाने पर अध्यापकों का ट्रान्सफर करके पौड़ी भेजा जा रहा है। वहां विद्यार्थियों को कोई पूछने वाला नहीं रहा। आजादी से आज तक, मैं मंत्री जी को चैलेन्ज देता हूं, कि कोई भी सरकारी स्कूल वहां खोला गया हो तो वह बतायें, बेसिक से लेकर डिग्री कालेज तक। क्या टेहरी गढ़वाल में पूरी तरह सरकारी पैसे से कोई स्कूल या कालेज बनाया गया है जिसके निर्माण में जनता का योगदान शून्य रहा हो। हमारे यहां जब डिग्री कालेज खुला तो हमने चंदा किया। बेसिक स्कूल भी सरकारी नहीं है। मान्यवर, हमने एक प्रश्न किया कि जो व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जिनके भवन क्षतिग्रस्त हो गये हैं उनके निर्माण के लिये सरकार ने पैसा क्यों नहीं दिया। इस पर जवाब मिला कि इस खाते का सरकार के पास पैसा नहीं है जिससे इनको मदद दी जा सके।

मान्यवर, नेगी का जो पर्वतीय विकास विभाग है, वह अपने ढंग का अनोखा पर्वतीय विकास विभाग है। जनतंत्र की हत्या करके, जिसको पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया था, ऊपर से नीचे तक जनतंत्र का गला घोटने के बाद पर्वतीय विकास मंत्री जी कहते हैं कि पहाड़ों का विकास कर रहे हैं जबकि इस विभाग के जितने अधिकारी

है, वह सब उन गांवों में नहीं जा सकते हैं जहां गढ़वाल और कुमायूं का गरीब रहता है। कौन विकास करेगा? मान्यवर, जनता शासन में श्री बनारसी दास को बार-बार आगाह करने वाला गृह सचिव आज पर्वतीय विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। उसने बनारसी दास जी को आगाह किया था कि यदि उत्तरकाशी में कमलाराम नौटियाल के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही को वापस लिया गया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस विद्रोह कर देगी। तो वह सचिव पहाड़ों का क्या विकास करेंगे?

मान्यवर, पर्वतीय विकास मंत्रालय वैरागियों का एक बगीचा है जिसमें अनेक जटाधारी साधू संत पद्मासन मारे ब्रह्म चिन्तन में लीन हैं। आज मंत्री जी ने योग्याभ्यास के लिये यौगिक केन्द्रों के खोले जाने की बात कही है जिसकी ओर डाक्टर शिवानन्द नौटियाल ने इशारा कर दिया।

[समय 2 बजे]

मैं उस पर अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह पहला मौका है मान्यवर, कि क्षेत्रीय विधायकों की संस्तुति के खिलाफ पर्वतीय विकास मंत्री जी ने अपने तानाशाही रवैये के अनुसार अपनी मर्जी से काम किया। यह पहला मौका है मैं इस सदन के अन्दर इल्जाम लगाता हूं और कांग्रेस के साथियों को आगाह करना चाहता हूं कि मंत्री जी पहाड़ों पर सिन्डीकेट को पनपा रहे हैं। क्योंकि जब कांग्रेस का बटवारा हुआ था तो मंत्री जी सिन्डीकेट में गये थे। यह पता नहीं क्यों ऐसा किसके लिये कर रहे हैं।

एक सदस्य---

आपके लिये।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मुझे मेरी जनता ने चुनकर भेजा है इसलिये नहीं कि मुझे बहुत बड़ी पार्टी का टिकट मिला था या मेरी पैतृक ख्याति रही हो। मैं पहाड़ों से वहां के अफसरशाही के विरोध में लड़ते हुए यहां आया हूं। मैं पैतृक आधार पर नहीं आया हूं। यह पहला मौका है जब गढ़वाल मण्डल निगम और कुमायूं निगम के अन्दर जितने गैर कांग्रेसी विधायक थे मंत्री जी ने उनको अलग कर दिया। गढ़वाल और कुमायूं मण्डल के अन्दर एक भी गैर कांग्रेसी विधायक नहीं है। आखिर यह बजट जो आपने पेश किया है यह किसी योजना का ही अंग है। मंत्री जी बतायें क्या यह बजट आपने बनाया है, जिला कांग्रेस ने बनाया है? क्या यह बजट पर्वतीय विकास का कांग्रेस पार्टी की शिरकत से बना है? इसमें कुछ अधिकारियों की शिरकत है जो पहाड़ के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। यह उनके सहयोग से बना है।

माननीय मंत्री जी आई0 टी0 आई0 की साज सज्जा की बात कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र नगर में जो पोलीटेक्निक है, उसमें पहाड़ के लड़कों को भरती करने में क्या आपत्ति है। मान्यवर, टेहरी के अंदर टेहरी बांध बन रहा है। पर्वतीय विकास की योजना पेश की उससे इस बांध का कोई संबंध नहीं। पहाड़ के लड़कों का पेशेवर गुण्डे टेहरी के अन्दर उनका कत्ल कर रहे हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पहाड़ के लड़कों को टेहरी बांध के अन्दर नौकरी नहीं मिलती है। मंत्री जी हमारी ओर देखते रहते हैं, हमको नौकरी थोड़ी देनी है, नौकरी आपको देनी है। आज पहाड़ के अन्दर टाटा, बिड़ला, डालमियां, बालचन्द, हीराचन्द और थापर का कब्जा है। चाहे वह पहाड़ का पानी हो, पहाड़ का पत्थर हो, पहाड़ के पेड़ हों, पहाड़ की पत्तियां हों. पहाड़ की लकड़ी हो, सब पर इनका कब्जा है। मंत्री जी केवल निगरानी रखते हैं और इन इजारेदारों को पर्वतीय-सम्पदा लुटा रहे हैं। मंत्री जी इजारेदार घरानों की खाने की मेज पर दस्तरखान बिछाने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा थापर यह टेहरी का बांध तुम्हारे लिये है,

[श्री विद्या सागर नौटियाल—]

वह उस पर काम करता है और बंधुआ मजदूरों की तरह से वहां काम लिया जाता है। बाल चन्द हीराचन्द के लिये मनेरी बांध निर्मित किया जा रहा है।

मान्यवर, 27 दिसम्बर को पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक हुई लखनऊ में। मैं उस बैठक की मिनिट्स मांगने के लिए खुद पर्वतीय विकास कार्यालय में गया, तब यह कहा गया कि मिनिट्स तैयार नहीं हुए हैं। आज मान्यवर, तीन महीने हो गये हैं अभी मिनिट्स तैयार नहीं हुए हैं। प्रोसीडिंग लिखी गयी या नहीं लिखी गयी, यह मैं नहीं कह सकता हूं। पर्वतीय विकास मंत्रालय में मंत्री जी ऐसी व्यवस्था है कि दूसरे व्यक्ति को कुछ पता न लगे।

मान्यवर, आत्मनिर्भरता की बात मंत्री जी ने कही है। आत्मनिर्भरता तब होगी जब पर्वतीय संसाधनों का उपयोग पर्वतीय धरती को सजाने में, मनुष्य के जीवन को सुन्दर बनाने के लिये, उच्चतम मूल्यों को वहां पनपाने के लिये किया जायगा। आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है वह बहुत गलत है और हम यह समझते हैं कि अगर विकास की यही दशा रही तो जो पहाड़ के अन्दर रहे सहे आदमी हैं, उनको धक्का मार कर वहां से भगा दिया जायगा।

5-6 नये बांध बनाने का प्रस्ताव है लेकिन जंगलों को आपने साफ कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने आज कहा है कि एक हजार मीटर के ऊपर कटाई नहीं होगी लेकिन क्या माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे कि जो एक हजार मीटर के ऊपर जंगलों की कटाई हो रही है उसको तुरन्त बंद करवा देंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 2750 मीटर के ऊपर जंगल नहीं होते हैं। लेकिन जंगल काटे जा रहे हैं, ठेका दे दिया गया है और तमाम हम लोगों को बहकाने की बात की जा रही है। अभी आपकी कटान जारी है, इस कटान को रोकने के लिये माननीय मंत्री जी यहां पर आश्वासन देंगे कि कल से पहाड़ों के अंदर जितने काम होंगे, सारे कामों के लिये मोनोपोलीज को पहाड़ों के अन्दर नहीं घुसने दिया जायगा? मैं मंत्री जी को आखिर में एक शेर सुनाता हूं :—

बूये गुल नालाये दिल, दूदे चरागे महफिल
जो तेरी बज्म से निकला सो परीशां निकला।

* श्री बल्देव सिंह आर्य—

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा विचार कुछ कहने का नहीं था पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ कह देने की ही आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र एक विशेष महत्व का क्षेत्र है। हमारे एक साथी ने उसका उल्लेख भी किया है कि वह सीमा से लगा हुआ है और इसीलिये आज आवश्यक है और पहले जो हमारे देश के नेता थे, हमारे प्रदेश का शासन चलाने वाले थे, उन्होंने सोच विचार कर वहां के विकास को विशेष तरजीह दी कि वहां का विकास होना चाहिये। जैसा अभी हमारे एक दोस्त ने कहा वहां के लोग फौज में भरती होते हैं, फौज में नौकरी करते हैं और दूसरी जगह जहां कहीं कभी कोई मौका मिलता है, वह वहां नौकरी में जाकर जीवन यापन करते हैं। जो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं वह बड़े-बड़े शहरों में जाकर पैसे वालों के यहां बरतन साफ करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है। यहां पर विकास के लिये जितना भी खर्च किया जाय वह कम ही है।

हमको भारत सरकार, खासतौर से श्रीमती इन्दिरा गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को धन्यवाद देना चाहिये कि पर्वतीय क्षेत्र के बजट में उन्होंने वृद्धि की है। लेकिन एक बात कहने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। कि बजट तो बहुत पास हो रहे हैं, पिछले साल भी बजट हमने पास किया और इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साल भी बजट पास हो रहे हैं। हमको चाहिये कि हम बात बहुत कम करें, और उस बात का असर, उस क्षेत्र में जाकर पड़े, जिस क्षेत्र के लिए हम कह रहे हैं, तब तो विकास होगा। लेकिन हम बातें तो बहुत लम्बी-लम्बी करते हैं, तो जिन लोगों के लिये बात लम्बी-लम्बी करें, तो उनको उसका लाभ पहुंचे, तब तो इन बातों का असर है, वरना वह सारी बातें बेकार हैं। तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह जितनी भी पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में बातें करें, तो उस बात का असर सही मायनों में उस क्षेत्र पर पड़ना चाहिए।

आज एक संतुलित विकास की आवश्यकता है, जिसकी वहां बहुत कमी दिख रही है। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि जो पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का विकास अधिक तेजी से होना चाहिए। आज कहा यह जाता है कि फलां-फलां जगह के कार्यों को लेंगे, ठीक है, वह भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र का ही हिस्सा है, उनका विकास होना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन जो क्षेत्र उपेक्षित हैं, उन क्षेत्रों में औद्योगिक धन्धे लगाये जाने चाहिए। ताकि इन उद्योग धंधों से वहां के लोगों की रोजी-रोटी चल सके और वहां ऐसी चीजें तैयार हों, जो अपने देश के बाजार में लग सकें, जिनसे अच्छा मूल्य मिल सके और हमसे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे। अगर हम इस तरह का संतुलित विकास नहीं करेंगे तो वहां प्रगति का आना सम्भव नहीं होगा।

आज पर्वतीय विकास विभाग के मंत्री नेगी जी हैं, कल कोई दूसरा मंत्री पहुंचेगा, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी इस जगह पर हो, वह पर्वतीय क्षेत्रों का विकास इस ढंग से करे कि वहां के लोग इस बात को महसूस करें कि हां कुछ कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। सन् 1936 में जब पंडित जवाहर लाल नेहरू पौड़ी और श्रीनगर गये तो उन्होंने उन क्षेत्रों को देखकर कहा कि यहां पर ब्रिटिश शासन की एक ही निशानी बाकी है, तार के खम्बे। बाकी यहां कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है न कोई सड़क बनी है, न कोई स्कूल, और कालेज आदि बने हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति वहां नहीं है। जहां पर उन्होंने यह कहा था, वहीं पर आज एक विश्वविद्यालय काम कर रहा है। यह बात और है कि उस विद्यालय में अनेकों कमियां और खामियां हैं, लेकिन पहले जैसी स्थिति आज वहां नहीं है। वहां पर विश्वविद्यालय जरूर है, लेकिन उससे लाभ जो नीति और माना घाटी के लोग रह रहे हैं, उनको नहीं पहुंच रहा है और जो लोग पिथौरागढ़ की घाटियों में रह रहे हैं, तो क्या उनको कुमायूं युनिवर्सिटी, नैनीताल से पूरा-पूरा लाभ पहुंच रहा है?ऐसा मैं नहीं मानता आज लोकतन्त्र के युग में, शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिये समान रूप से अवसर मिलना चाहिए और मुझे उम्मीद भी है कि सरकार इस ओर प्रयास जारी रखेगी।

इसके साथ ही मान्यवर, यह भी देखना है कि जो चीजें पहाड़ों पर पैदा होती हैं, अनाज, सेव और आलू। लेकिन इन चीजों की मार्केटिंग व्यवस्था ठीक नहीं है, जैसा कि अभी हमारे साथी नौटियाल साहब कह रहे थे। लेकिन कई सालों से इसके बारे में कहा जा रहा है, कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी। मैं भी अपने को शामिल करता हूं, काफी समय शासन में रहा हूं, उस समय भी कुछ नहीं हो सका और न ही आज तक कुछ हो पाया। मैं पिछले दिनों वहां गया था, तो वहां पर एक आलू का व्यापारी मिला, उसने कहा कि 15 हजार बोरे आलू मेरे पास रखे हैं, एक इंडीवीजुअल के पास 15 हजार बोरे आलू, जरा सोचिये और हमारे निगम ने कहा कि इस साल हमें ठीक लगा नहीं। हम समझते हैं कि उनके पास पूरी मशीनरी नहीं

[श्री बल्देव सिंह आर्य—]

है कि ठीक तरह से वे आलू का व्यापार कर सकें। एक मीटिंग में मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि एक सोसाइटी हो, एक मारकेटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी हो, वह सहकारिता के माध्यम से व्यापारी को सब सुविधायें उपलब्ध करायें। मान्यवर, जिन्होंने सेव पैदा किया था, उन्होंने वह सेव पेटियों में भर कर बराबर कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया, आप उनको नोटिस दे रहे हैं कि उसको कम मिले। न पेटियों का पैसा मिला, तो वहां की मारकेटिंग व्यवस्था कम से कम और कुछ नहीं तो, सही तो हो। तो इस तरह से जो चीजें वहां पैदा होती हैं, उन्हें बाजार में लाने के लिये हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि शासन इस पर जरूर विचार करेगा।

एक बात और मान्यवर, मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि वहां पर पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो पहाड़ के पर्यटक आते हैं विदेशों से यहां के पहाड़ देखने के लिये, वे यहां के पहाड़ देखना चाहते हैं, यहां के पहाड़ सबसे सुन्दर और रमणीक हैं। "वैली आफ फ्लावर्स" जो यहां की है, उस वैली में सारे हिन्दुस्तान के लोग और विदेश के लोग वहां जाते हैं वहां की खूबसूरती को देखने के लिये, वहां की आबहवा लेने के लिये। यह वैली आफ फ्लावर्स उत्तर काशी जनपद में है। हजारों यात्री, हमारे मुल्क के लोग तो कम जाते हैं, यहां विदेशी यात्री बहुत जाते हैं वहां की आबहवा को लेने, वहां की खूबसूरती को देखने, वहां की रमणीकता को देखने के लिये और आबहवा का लाभ उठाने के लिये। हमने पिछले दिनों कोशिश करके एक सड़क का निर्माण शुरू कराया था। वह सड़क आज तक पूरी नहीं बनी है, वह सड़क अधूरी पड़ी हुई है, वह बन नहीं पायी है, ऐसी स्थिति वहां की है। पहाड़ के पर्यटक उद्योग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ऐसा मेरा अनुरोध है। यह ठीक है कि सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील भी है परन्तु इसका पहले सर्वे हो जाना चाहिये। जो पर्यटक उद्योग में लगे हुए अधिकारी हैं, उन्हें पूरे क्षेत्र का सर्वे करना चाहिये कि कहां-कहां पर कौन-कौन से रमणीक स्थल हैं, कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं, उन स्थानों पर पर्यटन केन्द्र बनाने की आवश्यकता है।

हमारे प्रदेश के लोग पहाड़ के इन रमणीक स्थलों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। चूंकि बद्रीनाथ का हर व्यक्ति नाम जानता है, गंगोत्री का नाम कुछ लोग जानते हैं, इससे पर्यटन उद्योग को कुछ भी बढ़ावा नहीं मिलेगा।

मेरा एक अनुरोध और है कि हमारे क्षेत्र उत्तरकाशी में अधिक क्षेत्र जनजाति के निवासियों का है। जनजाति के निवासी और अनुसूचित जाति के निवासी सबसे अधिक संख्या में वहां पर रहते हैं। उनका जीवन–स्तर उठाने का प्रयास तो कुछ हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। इनका जीवन स्तर उठाने के लिये प्रयास करना बहुत जरूरी है। आफिस देहरादून में है। पिछले दिनों भी मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था तो उन्होंने और मुख्य मंत्री जी ने कृपा करके उस क्षेत्र के आफिस को उसी क्षेत्र के अन्दर ले जाने के वादे दिये थे लेकिन आज तक वह वहां नहीं जा सका है। आप समझिये कि 60-60 और 70-70 किलो मीटर से देहरादून जाना पड़ता है। जाहिर है कि काम से जाते हैं तो साथ में डेढ़-डेढ़ हजार और दो-दो हजार रुपये भी ले जाते हैं। देहरादून के होटलों में खर्च करते हैं।

अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि वहां शहरों की तरह चकाचौंध है। जी हां, वहां चकाचौंध है, वहां होटल हैं, वहां सिनेमाघर हैं। तो बेचारा जो पहाड़ से जाता है वह वहां अपने रहने-खाने में सारा पैसा खर्च कर देता है। उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है इसलिये मान्यवर, आज वहां की आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो वह जो कार्यालय है उसके आप का आदेश होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आदेशों को, हुकुम को अधिकारी मानने को तैयार नहीं हैं आदेशों का पालन ठीक तरह से होना चाहिए। यह

पूछना चाहिए कि सरकार की ओर से इस तरह के आदेश दिये गये थे यह क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 5वीं योजना में जो काम किये गये थे वही अभी अधूरे पड़े हैं। हमारे क्षेत्र से चिट्ठी आती है, दूसरे क्षेत्रों से चिट्ठी आती है। लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। 85-86 करोड़ पिछले साल और एक अरब रुपया इस साल मंजूर कर रहे हैं। मैं बराबर मंत्री जी को लिखता रहा कि यह होना चाहिए यह होना चाहिए। लेकिन जो काम अधूरे पड़े हैं वे वैसे ही पड़े हैं। उनको समाप्त होना चाहिए। पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर आप को ध्यान देना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के सामने जो बातें आप के माध्यम से कही गयी हैं, रखी गयी हैं, उन पर वे अवश्य विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं माननीय शिवानन्द नौटियाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने पिछले साल 86 करोड़ के बजट का इतना ढिंढोरा पीटा और जैसा कि सभी सदस्य, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कहा, आवाज तो बहुत हुई लेकिन एक बूंद बरसा नहीं। मेरे ख्याल से यह बजट 20वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक रहा और इस साल का जो बजट पेश किया वह पिछले साल की कापी है। सिर्फ 86 करोड़ के बजाय 100 करोड़ रख दिया बाकी आश्वासन, वही नारे, वही सब चीजें इसमें भी हैं। मेरा ही नहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी असंतोष है माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य, माननीय बलदेव सिंह आर्य ने भी इससे असंतोष व्यक्त किया और धवन साहब जो सत्ता पक्ष के हैं ने इतना ऐतिहासिक भाषण दिया जो मेरे ख्याल से जवाहर लाल नेहरू के ट्राइस्ट विद डेस्टनी के बाद पहला है। मंत्री जी, सब लोगों की शिकायत है, आप अपनी करें लेकिन जहां तक हम लोगों के सुझाव, सलाह लेने की बात है, सहयोग की बात है प्रत्येक विकास के कार्य में चाहे हम विरोध पक्ष के हों, आपके साथ हैं। यदि आप विकास कार्य करना चाहते हैं। परन्तु आप में एक कमी है वैसे सब आदमी अपनी अक्ल ज्यादा समझते हैं परन्तु आपको अपनी अकल के बारे में अधिक गलतफहमी है। किसी ने सुझाव दिया, राय दिया चाहे आपकी ही पार्टी के सदस्य ने, लेकिन आप उसे रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। कोई हम सुझाव देते हैं, उस की आप छानबीन करायें, अगर गलत हो तो हम से कहें कि आप का सुझाव गलत है सड़कों का चयन आप करवाते हैं अपने चन्द ठेकेदारों से। पी.डब्लू.डी. की विकास कमेटी बनायी है उस में सब के सब ठेकेदार भर दिये हैं और वे विधायकों से कहते हैं हमने आप की सब सड़कें पास कर दीं। यह है, हम विधायकों की भी कुछ गरिमा है, कुछ प्रतिष्ठा है, आप को रखना ही चाहिए। आज भी आप क्या कह रहे हैं, दिल्ली से सलाह लेंगे। कंसलटेन्ट कमेटी दिल्ली में है उत्तर प्रदेश में आप को कोई भरोसा नहीं है। अभी दिल्ली से लेंगे पता नहीं आगे कहां से लेंगे, स्विटजरलैण्ड से लेंगे। मैं तो खुद महसूस कर रहा हूं कि पर्वतीय विकास परिषद में मैंने अपने सुझाव दिये, कितने प्रस्ताव आपको दिये परन्तु कोई काम नहीं हुआ।

आज भी जो सुझाव हम दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं। आप हिमांचल की बात कहते हैं, कहते हैं पलायन रोकेंगे। आप पलायन कैसे रोकेंगे, आप तो खुद पलायन कर गये हैं। हिमांचल का विकास, वहां परमार जैसे मुख्य मंत्री रहे, जिन्हें प्यार था लगाव था हिमांचल से उन्होंने उसका विकास किया। आज भी बेहोशी की हालत में भी दिल्ली से शिमला जाने की ख्वाहिश पर शिमला भिजवाये गये। मंत्री जी पहाड़ की आबहवा भी तो आपको माफिक नहीं आती है, विकास की उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं है परन्तु पहाड़ों का वातावरण जो बड़ा सौहार्द्र और शान्तिपूर्ण था,

[श्री कुंवर सिंह नेगी---]

उसको आपने विषाक्त बना दिया। माननीय मंत्री जी आप गुड़ न दें पर गुड़ जैसी बात तो करें। जो यह धवन साहब ने कहा है और माननीय बिष्ट ने कहा है कि आपका 86 करोड़ का बजट कहां गया, सही कहा है। श्री शिवानन्द नौटियाल जब मंत्री थे तब 325 प्राइमरी स्कूल खुले, आपके समय में 116 स्कूल खुले और अब 110 प्राइमरी स्कूल खुले। श्री शिवानन्द नौटियाल के समय में 110 जूनियर हाईस्कूल खुले और आपके समय में 38 जूनियर हाईस्कूल खुले और 38 प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार श्री शिवानन्द नौटियाल के समय में 46 हाईस्कूल खुले, आपके समय में 24 खुले और अब 3 प्रस्तावित हैं।

मान्यवर, मेरे जिले में एक असेड़ सिमली तथा लदोली के हाईस्कूल प्रस्तावित थे उन पर वित्त ने, शिक्षा ने अनुमोदन दे दिया था केवल राजाज्ञा पर मंत्री जी के दस्तखत होने थे परन्तु आपने रोक दिए। आप प्रत्येक चीज को विद्वेष की भावना से कर रहे हैं और किसी के यहां स्कूल खोलने हैं, अस्पताल खोलने हैं तो आप कह रहे हैं कि पहले शपथ-पत्र भरो, अनुबंध करो कि वोट देंगे तो मंत्री जी यह बात ठीक नहीं है। इसी प्रकार इण्टर कालेज माननीय शिवानन्द के समय में 29 खुले, आपने 19 खोले और इस वर्ष अब 5 प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार डिग्री कालेज 6 खुले, आपके जमाने में एक भी नहीं और अब भी कोई प्रस्तावित नहीं है। इसी प्रकार आप उद्योग धन्धे जो आर्थिक विकास के लिए लगाना चाहते हैं। नौटियाल जी ने ठीक कहा कि तीन करोड़ 73 लाख के आपके बजट में से ढाई करोड़ जसपुर, बाजपुर और सितारगंज हल्द्वानी पर खर्च हो रहा है। आपने व नारायण दत्त तिवारी जी ने तो पहाड़ की किस्मत का ही सौदा कर दिया है। इसी प्रकार से अस्पतालों के बारे में कह रहा हूं, नौटियाल जी के समय में 60 एलोपैथिक खुले थे आपने 50 खोले और इस वर्ष 40 प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार महिला चिकित्सालयों के संबंध में नौटियाल जी के समय 7 खुले थे, आपके समय में 5 खुले और अब भी 5 प्रस्तावित हैं। जो आप बातें कर रहे हैं असन्तुलन समाप्त करने की, विकास का सन्तुलन बनाये रखने की तो डुगड्डा ब्लाक में तीन किलोमीटर पर अस्पताल खोला गया है और चमोली जिले में 20 कि. मी. पर भी अस्पताल नहीं है। आप प्रत्येक को वोट के परसेन्टेज के अनुसार हांक रहे हैं। लेकिन 185 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 40 पर आपकी जीत हुई है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इस चीज को विभाग के कर्मचारी, डाइरेक्टर और सेक्रेटरी को तो देखना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय न हो। कहीं पर 3 किलोमीटर पर अस्पताल खुले, और कहीं 20 कि. मी. पर भी अस्पताल न हों। विकास के लिए जरूरी है कि वहां के कर्मचारियों का जनता से नजदीक का संबंध हो, तालमेल हो, सामन्जस्य हो। हमारे यहां कोई भी कर्मचारी पैदल रास्ते पर गांवों में नहीं जाता। मंत्री जी एक नियम बना है, एक विधान बना है कि प्रत्येक कर्मचारी महीने में निश्चित दिन गांव में जायेगा, गांव वासियों के साथ गांव में रह कर उन की समस्याओं को सुनेगा, उन के निराकरण की व्यवस्था करेगा, लेकिन कोई भी कर्मचारी गांव में नहीं जाता। जहां तक मोटर सड़क है वहां से आगे नहीं जाता।

आप ने मेरे जिले के साथ बहुत अन्याय किया है। इस साल सिर्फ 54 किलोमीटर सड़क सिर्फ मेरे जिले को मिली है। उस में भी एक सड़क पर भी कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पिछले बजट में आप ने कितने पैदल सड़क और कितने पैदल पुल बनाये। शायद उन के लिए कोई प्राविधान नहीं था और इस साल भी नहीं है। मंत्री जी जोड़ना सीखिये। दो हिस्सों को आपस में पुल की तरह जोड़ना सीखिये। आप तो तोड़ने में विश्वास रखते हैं। इस चीज की ओर ध्यान दीजिए।

आपने पर्यटन के बारे में काफी बातें कहीं। तीन चीजों के बारे में मेरा विशेष अनुरोध है। हमारे यहां जड़ी बूटियों की बहुत उपलब्धता है। जड़ी बूटियों पर आधारित

वहां पर उद्योग लग सकता है। जड़ी बूटियों के लिए मैं पिछले साल से चिल्ला रहा हूं। हमारे यहां हरबल इन्सटीट्यूट पहले से सरकार ने प्रस्तावित किया है। आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लिए आप से निवेदन किया था कि जो जड़ी बूटी फार्म प्रस्तावित है उन्हें अवश्य खुलवायें। हमारे यहां जोशीमठ से ओलीगुरसों तक रोप वे लगना था जोकि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कार्य अभी तक नहीं हुआ है। शायद आप उस कार्य को समाप्त करने वाले हैं। गढ़वाल विकास निगम का मैनेजिंग डाइरेक्टर आपने डी. एम. पौढ़ी को बनाया है, जिला परिषद् का चार्ज भी उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास नगरपालिका भी है, डी. डी. सी. भी वही हैं, एक आदमी उतना काम कैसे कर पायेगा? वह कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इसको देखें। हमारी रोप वे न रोकें। माननीय मंत्री जी आपकी समदृष्टि होनी चाहिए। आपका विभाग बहुत सम्वेदनशील विभाग है। जो भी पर्वतीय विभाग का मंत्री रहा है डाक्टर शिवानन्द नौटियाल के अलावा कोई दुबारा नहीं आया। आपभी दुबारा आयें मेरी कामना है। इसलिए सबका काम करें, सबको समदृष्टि से देखें। धन्यवाद।

*श्री बिहारी लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पर्वतीय क्षेत्र के बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र की बात हमारे पक्ष और विपक्ष की तरफ से आई और कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आये। दुर्भाग्य इस बात का है कि बजट में मैंने कहीं भी यह नहीं देखा कि पर्वतीय क्षेत्र के हरिजनों के लिये, अल्पसंख्यकों के लिये और कमजोर वर्ग के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था हो जिस से उन के हितों की रक्षा हो सके और उन का उद्धार हो। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। हम आठ जिलों के पर्वतीय क्षेत्र से चुन कर तीन विधायक आये हैं, गोपाल राम दास जी, जो मंत्री हैं, हमारे बुजुर्गवार आर्या जी और स्वयं बिहारी लाल आप के सामने हूं। जब हम पर्वतीय क्षेत्र का दौरा करते हैं, जब हम उस इलाके के दौरे पर जायेंगे तो वहां के हरिजन भाई हम से पूछेंगे कि लगभग 100 करोड़ का बजट सामने आया उस में अनुसूचित जाति, हरिजन भाईयों के लिये कितना बजट रखा है। हम उनको क्या बतलायेंगे, मेरी समझ में यह बात नहीं आती। हमारी दल की नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारे दल के नेता, श्री नारायण दत्त तिवारी, जो भारत सरकार में बैठे हैं जिनकी कृपा से इतनी बड़ी योजना बनी और इतने करोड़ का बजट मिला। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह बागेश्वर गये थे। मैंने उनको वहां पर हरिजनों की झोपड़ियां दिखाई थी, टमटा परिवारों के लोगों से मिलाया था। उस समय हमारे मुख्य मंत्री जी की आंखों में आंसू आ गये थे। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हमारे मुख्य मंत्री हैं, अगर उनके कार्यकाल में पर्वतीय क्षेत्र के हरिजनों का उद्धार नहीं हुआ तो मैं समझता हूं फिर कभी नहीं हो सकता है। मुझे यह दुख है कि इस 100 करोड़ के बजट में कहीं पर भी ऐसा संकेत नजर नहीं आ रहा है कि उनके हित के लिये, हरिजनों के लिये कुछ नहीं रखा गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिये हरिजन कल्याण कोष से 2-4 सौ रुपया दे देने से या एक-आध मशीन उनको दे देने से उनकी समस्या हल होने वाली नहीं है।

मान्यवर, जिला नैनीताल, कुमायूं, उत्तराखंड में हरिजनों की बुरी हालत है। उनको जमीन के पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनको भगा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पर्वतीय विकास मंत्री के हाथ में सारा मसला है इसलिए वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिहारी लाल---]

कृपया इसको देखें और जितने भी वहां पर हरिजन परिवार, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जमीन के पट्टे दे दिये जांय। मैं एक बात मंत्री जी को और बता देना चाहता हूं कि आप हर पर्वतीय जिले में कमिश्नर, डी.एम. या एस.पी. आदि जो अधिकारी हैं, उसमें अगर एक आदमी हर जिले में अनुसूचित जाति का न होगा तो वहां का विकास नहीं हो सकता है। न ही हरिजनों की पर्वतीय क्षेत्र में रक्षा हो सकती है।

मैं एक बात आपके सामने खुलकर कहना चाहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश में जहां पर कि हमारा शासन है, हरिजन कल्याण विभाग में, दो सेक्रेटरी ऐसे हैं जो कि हरिजन विरोधी हैं। अगले बजट में हम उनका नाम भी पेश करेंगे। ये अधिकारी हरिजनों के प्रति घृणा की नजर रखते हैं, वहां कोई भी बजट नहीं जा पाता है और अगर उसके लिये कोशिश की जाती है तो उसको फेल कर दिया जाता है। मान्यवर, यह ऐसा विषय है, जिसपर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इस तरह की जो मशीनरी है, उसको चैक किया जाना चाहिए।

अब मैं रोड्स के बारे में कहना चाहता हूं। टूरिस्ट्स की बात कही गई। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में अखिलाकांडा ब्लाक है, सनराइज वहां से बहुत अच्छा और सामने दिखाई देता है कोसानी जैसी जगह पर आज तक कोई भी टूरिस्ट के रहने की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे पर्वतीय क्षेत्रों के इन इलाकों में टूरिस्ट सेन्टर खोलने की व्यवस्था करें। मान्यवर, आप जानते हैं कि नैनीताल जिले में कई लेक हैं। किन्तु अभी आपके अधिकारियों ने मौके पर जाकर यह नहीं देखा कि वहां कितनी लेक हैं, उनका विकास हो सकता है, वहां पर टूरिस्ट सेन्टर बनाये जा सकते हैं और प्रदेश को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र के विकास के साथ-साथ प्रदेश का भी विकास होगा। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगाये जाने चाहिए जिससे वहां के लोग धन कमा सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मैं चाहूंगा कि कि अखिलकांडा, धारी ब्लाक, नथुवाखान, टनकपुर, सितारगंज, खटीमा में छोटे-छोटे उद्योग खोले जांय। मान्यवर, इन उद्योगों से वहां की बेरोजगारी भी काफी हद तक दूर हो जायेगी।

अब मैं रोड्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जिला नैनीताल तिवारी जी का क्षेत्र है। लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं। अल्मोड़ा 95 कि0 मी0, नैनीताल 68 कि0 मी0, पिथौरागढ़ 96 कि0 मी0, उत्तर काशी 77 कि0 मी0, चमोली 102 कि0 मी0, टेहरी गढ़वाल 88 कि0 मी0, पौड़ी गढ़वाल 101, देहरादून 102 कि0 मी0, पौड़ी-नैनीताल सम्पर्क मार्ग 102 और कुल 375 कि. मी. रह आता है। मैं नैनीताल का रहने वाला हूं। और अनुसूचित जाति का विधायक हूं। मेरे को कम से कम 100 कि. मी. देना चाहिये जबकि केवल नैनीताल के लिए 16 कि. मी. रखा गया है। तो अगर किसी का कोटा पूरा नहीं होता है तो इसे भी उसको दे दिया जाय। इतने बड़े बजट में केवल 16 कि. मी. मिला है, यह ध्यान देने वाली बात है। मेरा पिछड़ा हुआ खटीमा का इलाका है वहां पर कोई डिग्री कालेज नहीं है, जहां कोई अच्छा अधिकारी जाना पसंद नहीं करता। तो मैं चाहूंगा कि इस बजट में उसे वंचित न रखा जाय और वहां पर डिग्री कालेज देने की कृपा करें।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, हरिजन वर्ग के लिए इसी बजट में कहीं से धनराशि बढ़ायी जाय ताकि थोड़ा बहुत हरिजनों के आंसू पुंछ जांय। मैं फिर बताना चाहता हूं कि नैनीताल को इस बजट में किस तरह से वंचित किया गया है मेरी समझ में यह बात नहीं आती जिला परिषदों के लिये जो धन दिया गया है उसे बताना चाहता हूं। अल्मोड़ा जिला परिषद् को 5 लाख, पिथौरागढ़ को 7 लाख, चमोली को 14 लाख देहरादून को 2 लाख, गढ़वाल को 6 लाख, टेहरी गढ़वाल को 4 लाख, उत्तरकाशी को 2 लाख, इसमें नैनीताल को एक पैसा भी नहीं

दिया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि सारा बजट दें माननीय नारायण दत्त तिवारी, केन्द्रीय योजना मंत्री और उसमें नैनीताल को इस तरह वंचित कर दें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल––

यह कहां से पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तिका में दिया है जो आंकड़े आपने पढ़े मैं जानना चाहता हूं।

श्री बिहारी लाल––

मैं यहीं से पढ़ रहा हूं, जब आप नहीं थे सदन में। आप सदन में बैठते होते तो पता लगता क्योंकि आप महीने में बाहर ही चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। सितारगंज में शुगर फैक्ट्री के लिए डा. साहब ने कहा क्यों खुल रही है। तो सितारगंज में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं, उस इलाके में भी काम होना चाहिए, उसका विरोध करने की बात नहीं होनी चाहिए। हर क्षेत्र का विकास हो, आप भी दो फैक्ट्री लगा लें।

(व्यवधान)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल––

हमने कहां विरोध किया?

श्री बिहारी लाल––

आपने कहा कि सारा बजट जो है वह तराई में जा रहा है। तो मेरा कहना है कि तराई वाली कोई बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री बिहारी लाल––

मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में हरिजनों के लिए कुछ पैसा दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

(श्री जसवंत सिंह विष्ट के खड़े होने पर) आप बैठें विष्ट जी, मैंने देहलवी जी को बुलाया है।

श्री मोतीलाल देहलवी––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दि0 28 मार्च, 1981 को मैं यहां पर बराबर उपस्थित रहा हूं और जितने भाषण हुए मैंने उनको ध्यान से सुना।

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्तावक माननीय डाक्टर नौटियाल की बात को छोड़े देता हूं, लेकिन सत्ता पक्ष के जितने विधायकों ने यहां पर भाषण दिया है, किसी ने भी माननीय मंत्री जी के बजट से सन्तोष और सहमति व्यक्त नहीं की है और यह इस बात का प्रमाण है कि माननीय मंत्री जी के बजट से और उनके तौर-तरीकों से, उनके कार्यकलापों से सत्ता पक्ष के विधायकों को ही सन्तोष नहीं है। एक तरह से सत्ता पक्ष के विधायकों ने पर्वतीय विकास मंत्री के प्रति अपना अविश्वास व्यक्त कर दिया है। उनका उन पर विश्वास नहीं रहा। वह बात जाने दीजिए कि चूंकि सिर पर दिल्ली के अनुशासन का डंडा है। तो उसकी उन्हें बहुत घबड़ाहट है। तभी दिल्ली को प्रणाम करने के लिये जाते हैं और मुख्य मंत्री, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब की स्तुति करने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि डंडे से उनको डर है, डंडे से इन सबको ही डर है। लेकिन एक तरह से सत्ता पक्ष के विधायकों ने माननीय पर्वतीय विकास मंत्री के

[श्री मोती लाल देहलवी]

प्रति अविश्वास व्यक्त कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि नैतिकता का यह तकाजा है कि उनको आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वह इस्तीफा नहीं देना चाहते, तो डाक्टर अम्मार रिजवी साहब बैठे हुए हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी शायद अपने कक्ष में बैठे सुन रहे होंगे, इन लोगों को, उनको अब आगे मंत्री बनाये रखने पर पुनर्विचार करना चाहिए और यदि वह विचार नहीं करते तो पर्वतीय विकास मंत्री विकास नहीं, वहां का विनाश करके रख देंगे और उससे पर्वतीय अंचल को कोई लाभ होने वाला नहीं है।

पर्वतीय विकास मंत्री मेरे मित्र भी रहे हैं, हम और वह इमरजेंसी में एक साथ सवा साल तक जेल में रहे हैं। मैं जानता हूं कि स्वर्गीय चन्द्रभानु गुप्त के चरणों में बैठकर उन्होंने राजनीति की है, सीखी है और जेल से निकलते ही उनका साथ छोड़ दिया। खैर, मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता हूं, यह तो डाक्टर साहब और मुख्य मंत्री जी ज्यादा समझते होंगे। लेकिन मान्यवर, प्रगति की जो रूपरेखा मंत्री जी को अपने बजट में रखनी चाहिए, उसका भी प्राविधान उन्होंने नहीं किया है। अगर आपने अपने ही पर्वतीय विधायकों से परामर्श लिया होता, तो जाहिर है कि आज इतना बड़ा अरान्तोष और निराशा दोनों पक्षों के विधायकों ने यहां न व्यक्त की होती। लेकिन जैसा कि कई लोगों ने बताया, उनके सोचने की प्रवृत्ति वही इमरजेंसी वाली है। ऐसा है कि वह समझते हैं कि जो वह सोचते हैं वही सही है, और जो वह कहते हैं वही सही है। उन्हें किसी की सलाह और किसी के मशिवरे की जरूरत नहीं है। यद्यपि मैं अपने प्रदेश के पर्वतीय अंचल में दुर्भाग्यवश नहीं जा सका हूं लेकिन एक समिति के साथ में मुझे काश्मीर जाने का मौका मिला था। वहां पर मैंने अच्छी तरह अनुभव किया था कि पर्वतीय अंचल का जीवन कितना दुरूह, कितना कष्टकारक और कष्टमय होता है। इसलिये मैं अपने प्रदेश के पर्वतीय अंचल के लिए अच्छी तरह से अनुमान लगा सकता हूं कि वहां पर क्या स्थिति होगी।

यहां पर कहा जाता है कि हर चीज सस्ती हो गयी लेकिन माननीय शिवानन्द नौटियाल ने इसी सदन को सूचना दी कि उनके यहां अब भी एक स्थान ऐसा है कि जहां पर नमक 5 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इससे ज्यादा लज्जा और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि माननीय सदन में कहा जाय कि हर चीज सस्ती हो रही है लेकिन नमक जैसी चीज वहां पर 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। हम पर्वतीय अंचल का विकास कर सकते हैं अगर वहां पर जो प्राकृतिक संपदा है उसका दोहन करके सदुपयोग किया जाय। जिस हालत में आज हमारे पर्वतीय अंचल हैं, उस हालत में कभी नहीं रहे हैं। अभी यह भी होता है कि जिस अधिकारी को सजा देनी हो, जो बहुत बड़ा भ्रष्ट हो, बहुत बदनाम हो गया हो, मैदानी इलाके में, उसे सजा देने के लिये पर्वतीय अंचल में भेज दिया जाता है। हमारे विष्ट साहब को एक दिन इसी सदन में बहुत बड़ी शिकायत हो गयी थी और उन्होंने पूछा था कि क्या वजह है जो भ्रष्ट अफसर समझे जाते हैं, उनको हमारे यहां पर भेज दिया जाता है। जो अधिकारी मैदानी इलाके के वहां पर जाते हैं वे एक साल रहकर ही कोशिश करने लगते हैं कि वहां से उनका छुटकारा हो जाये। आज हमारे पर्वतीय अंचल अभिशाप बने हुए हैं, वहां पर मैदानी क्षेत्र के लोग रहना और काम करना नहीं चाहते हैं। वे वापस दिल्ली में भाग आते हैं और ट्रान्सफर्स के लिये सिफारिशें कराते हैं। मैं यह चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल का ऐसा अभिशाप दूर हो। आप बराबर 30 साल से दिल्ली के लोगों की बड़ी सराहना करते रहे हैं लेकिन ध्यान न देने से बहुत सा हमारा इलाका चला गया। उर्वशियम आपके यहां से चला गया। दिल्ली से बयान जारी हुआ कि वह इलाका झंझड़-खाबड़ था। उधर खतरा है। डाक्टर लोहिया ने उस समय उस मामले को उठाया

था। जरूरत थी इस बात की कि अगर खतरा था तो उस खतरे से बचाव का आप प्रबन्ध करते, वहां पर्याप्त साधन जुटाते, पर्याप्त सड़कें बनवाते तथा और तरह-तरह के सुधार करते। कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था। मान्यवर, कल यहां जितनी हाजिरी थी सदन में, उसे देख लीजिये और आज यहां की हाजिरी देख लीजिये, ऐसा लगता है कि जैसे गैर पर्वतीय वासियों को इस बजट से कोई दिलचस्पी है ही नहीं, एक भी व्यक्ति गैर पर्वतीय आज उधर से नहीं बोला है। यह है इनकी मोहब्बत का नमूना पर्वतीय अंचलों से। इन शब्दों के साथ, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय डाक्टर नौटियाल ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिये समय दिया। पर्वतीय विकास के लिये जो यह लगभग 85 करोड़ का बजट रखा गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। यह पर्वतीय लोगों के लिये जिनकी संख्या 38.22 लाख है, विकास के लिये रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र की 90 फीसदी जनता देहात में बस्ती है और उनमें 80 फीसदी लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से भी काफी नीचे स्तर पर अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। उनके उत्थान के लिये, उनके विकास के लिये, यह बजट प्रस्तुत किया गया है जिसका मैं समर्थन करता हूं।

पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये यह आवश्यक है कि जहां एक ओर वहां का उत्पादन बढ़ाया जाये, वहीं दूसरी ओर वहां के उत्पादित सामान के ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था की जाये ताकि सामान आसानी से दूसरी जगह पहुंच सके। वहां जो हार्टिकल्चर का काम शुरू किया गया है। उससे वहां की काफी गरीबी दूर हो सकती है। उद्यानों के बढ़ाने से उत्पादन में भी वृद्धि होगी। जरूरत उनके लिये मार्केट पैदा करने की है, ट्रान्सपोर्ट की सुविधा पैदा करने की है।

वहां पर उत्पादित माल के लिये पैकिंग का प्रबन्ध करना भी बहुत आवश्यक है। सहकारिता के आधार पर पैकिंग का प्रबन्ध करने से छोटे-छोटे लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा और माल दूसरी जगह आसानी से जा सकेगा। पैकिंग केस न होने के कारण फल वगैरह मैदानी इलाकों में नहीं आ पाते। फिर जो फल वहां बचे रहते हैं, डेलीसेस सेब जो बच रहता है, वह मैदानी इलाकों में न आने के कारण वहां पर दो आने और चार आने सेर में बिकता है। सरकार को चाहिये कि ऐसे फलों की प्रोसेसिंग आदि के लिये भी कोई प्लान्ट लगाना चाहिए। इसके अलावा बड़े-बड़े शहरों में बम्बई तथा कलकत्ता आदि शहरों में इन फलों के लिये कोल्ड स्टोरेज पड़ने पर, उनको निकाल कर बेंचा जा सके।

मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास के लिये धनराशि रखी गयी है जो 60 और 40 के रेशियो में है। इतनी कम धनराशि से ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो पाना सम्भव नहीं है। इस धनराशि को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे ग्रामीण लोगों को अधिक रोजगार मिल सकेगा।

[समय 3 बजे]

हमारे एक साथी ने अभी बताया कि नैनीताल जिले को बहुत कम बजट मिला है और उस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसी तरह से पर्वतीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव नारायण सिंह नेगी]

क्षेत्र में जो जिला परिषदें हैं, उनको क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये बहुत कम बजट मिला है जिस प्रकार से जिला परिषदों को बाढ़ और बरसात के कारण जो सड़कें आदि टूट जाती हैं उनको मरम्मत के लिये धन दिया जाता है, उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में भी इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे शिक्षित बेरोजगार लोग दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिये मैं समझता हूं कि आई. टी. आई. और पालीटेक्निक का ज्यादा प्रबन्ध वहां पर किया जाय जहां से वह टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर सकें और स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन देखा गया है जैसा नैनीताल और दूसरे स्थानों पर पालिटेक्निक स्कूल खोले गये हैं लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को उसमें स्थान नहीं मिला है जिससे उनके लिये वह हितकर नहीं है, मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आई. टी. आई. और पालिटेक्निक स्कूलों का जाल पर्वतीय क्षेत्र में बिछाया जाय और वहां के स्थानीय लोगों को उसमें स्थान दिया जाय।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के बागों में जब ओले गिर जाते हैं तो उनकी तीन साल की फसल बेकार हो जाती है, जैसे बीमा की योजना आपने मैदानी बागों के लिए शुरू की है, मैं समझता हूं कि उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों के बागानों के लिए भी बीमा योजना लागू कर दी जाय। सहकारिता के माध्यम से मार्केटिंग का प्रबन्ध किया जाय जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने आपके सामने यह सुझाव रखा था कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आलू कितनी पैदा होती है, लेकिन मार्केट के न प्रबन्ध होने के कारण वह अपने वहीं पर बर्बाद हो जाती है। अगर मार्केटिंग का प्रबन्ध हो और ट्रान्सपोर्ट का प्रबन्ध हो, तो मैं समझता हूं कि हम पर्वतीय क्षेत्र के 80 प्रतिशत गरीबी रेखा से जो लोग नीचे हैं, उनकी कुछ सहायता कर पायेंगे।

फल निदेशालय की ओर आपका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं। आजकल वहां पर जितने उद्यान लगे हैं, वे कायदे और नियम के अनुसार नहीं लगे हैं। जैसा बताया गया, हिमाचल प्रदेश के बागवानों को वहां के इंसपेक्टर वगैरह जांच करने वहां पर जाते हैं और वहां पर उन पेड़ों को लगवाने की कोशिश करते हैं जो वहां के लिये लाभदायक हैं। लेकिन हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी ऐसा प्रबन्ध नहीं हो सका है। जिस भी वैरायटी के पेड़ हो, उनको वह लगाते हैं और वह बहुत कामयाब नहीं होते हैं। इसलिए अगर बागवानों की ओर ध्यान दिया जाय तो मैं समझता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए हमारा निदेशक अलग से बनाया जाय जो वहां के बागवानों को अच्छी सलाह दे सके और उनको आगे बढ़ा सकें। जहां तक शिक्षा स्तर की बात है, पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी प्राइमरी या हाई स्कूल हैं, उनकी बिल्डिंग की हालत बड़ी दयनीय है और जो बजट मिला है, उससे पूरा नहीं हो पायेगा। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी साज-सज्जा की ओर भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक हाई स्कूल और इन्टर कालेज की बात है, उनमें भी साज-सज्जा और भवनों की बड़ी सख्त आवश्यकता है। यह अक्सर देखा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो भी हमारे अस्पताल खोले गये हैं, वहां मैदानी भाग से, यहां से डाक्टर जाते हैं और जब वहां जाते हैं, तो उसके बाद वह वहां से अपने ट्रान्सफर की कोशिश करते हैं। मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र के ही डाक्टरों को प्रोत्साहन दिया जाय। इसके लिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि जो विज्ञापन निकला है, वह लखनऊ से निकला है, पर्वतीय क्षेत्र में जो डाक्टर पड़े हुए हैं, वह इधर उधर घूम रहे हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं हुई। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं प्रार्थना करूंगा कि उसका समय कुछ और बढ़ाया जाय जिससे उन लोगों को भी इस बात की जानकारी हो जाय जिससे वे आवेदन पत्र दे सकें और पहाड़ में अपनी सेवाओं से लाभ पहुंचा सकें।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जो आबादी है वह ऊंची-ऊंची पहाड़ियों से ढलान की ओर बसी हुई है। जो लुढकान है उनका कटान शुरू हो जाता है, उनके बीच में नालियां बन जाती हैं जिससे गांवों को बहुत नुकसान होता है। लुढकान वाली योजना बन्द कर दी जाय। इसी प्रकार तलहटी में बाढ़ से बड़ा नुकसान होता है। वहां पर छोटी-छोटी नालियों के द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाय और उसके लिये काफी अनुदान दिया जाय। जहां तक पर्वतीय क्षेत्र में पीने के पानी का सवाल है वहां पर शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। बहुत से गांव ऐसे हैं कि तीन चार मील से पीने का पानी लाना पड़ता है। जल निगम और जल संस्थान जो हैं वहां योजना न बना कर यहां लखनऊ में बैठ कर योजना बना देते हैं। पाइप बिछा दिये जाते हैं लेकिन पानी छन जाता है। जल निगम तथा जल संस्थान अगर मिल कर काम करें तो वहां की जनता को स्वच्छ जल मिल सकेगा। इसके अलावा जो तराई भाबर के क्षेत्र हैं उनसे जो अनाज उत्पन्न होता है उसको मार्केट में लाने में बड़ी दिक्कत होती है और दलाल लोग इस कारण उसका सारा फायदा उठाते हैं। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि हर गांव से लिंक रोड मेन रोड तक बनाई जाय ताकि अपना उत्पादन किसान मार्केट तक ले जा सके और सही पैसा उसका वह पा सके। इन शब्दों के साथ मैं बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं इस विभाग के संबंध में जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये आपका आभारी हूं। हमारे यहां एक कहावत है जिसका अर्थ यह होता है कि मेरे इतने मामा हैं बेइन्तहा लेकिन सगा एक भी नहीं है। इस तरह से इस विभाग की दुर्दशा है। पर्वतीय विकास विभाग जब से खुला है यह नाम का ही विभाग रहा है लेकिन इस विभाग का अपना कोई नहीं रहा। सिर्फ बजट इसको जरूर मिल जाता है लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता है। नौटियाल जी इस विभाग के मंत्री रहे, उससे पहले शोबन सिंह जीना मंत्री रहे और गोविन्द सिंह मेहरा रहे। अब माननीय नेगी जी हैं लेकिन जो बातें मैं सुन रहा हूं उनको सुन कर बड़ा तरस आता है। सारी बौछार उन पर हो रही है। वह एक ऐसे घड़े की गन्दगी अपने सर पर ढो रहे हैं पता नहीं कब फूट जाय। एक भी विधायक ने मंत्री जी के इस बजट का स्वागत नहीं किया। असल में बात यह है कि पहाड़ से यदि दर्द हो, लगाव हो, जैसा हमारे माननीय दरेहलवी जी ने कहा कि वास्तव में जब हमें लगाव और दर्द होता है और नौटियाल जी ने भी इस बात का जिक्र किया था तो वे समझते हैं, लेकिन माननीय हमारे राजकुमार महोदय यहां पले, यहां बढ़े और यहीं शिक्षा पायी और यहीं मंत्री भी हैं तो इन्हें क्या मालूम कि पहाड़ क्या है और कैसी स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी पहाड़ में 80 प्रतिशत से ज्यादा परिवार नमक के साथ रोटी खाते हैं। इन 34 वर्षों में आज भी पहाड़ के 80 प्रतिशत से अधिक परिवार नमक के साथ रोटी खाते हैं और वह नमक भी 5 रु0 किलो है। इसके अलावा सारा पानी पहाड़ से आता है और पहाड़ की धरती प्यासी रहती है।

आपने जल निगम की तारीफ की और कहा कि पहाड़ को पानी देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं और मैंने पहले भी कहा था कि आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको दिखाता हूं जिन स्रोतों को आपके विभाग के इन्जीनियर यह कहते हैं कि सूख गये, अगर वे सूखे हैं तो भी आप देखेंगे और अगर नहीं सूखे हैं तब भी आप देख लेंगे। लेकिन कारण क्या है, धन मिल रहा है लूटने के लिये विभाग को। इनका कोई विभाग तो

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जसवंत सिंह बिष्ट--]

है नहीं, जिसके ऊपर अंकुश हो। मैंने कई बार कहा मंत्री जी से अंकुश होना चाहिये। जिस इन्जीनियर को आप यहां से भगाते हैं, उसे रानीखेत, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी भेजते हैं। इस प्रकार से आप एक भ्रष्ट इन्जीनियर वहां भेज देते हैं, जो इतना रुपया लूटकर आते हैं कि आप देख लीजिए मेरठ में कोटद्वार में और जगहों पर आलीशान बंगले बना लिये हैं। इस प्रकार से उनको आपने यहां से मार-मार कर भगा दिया और वहां से वे मालामाल होकर आये। माननीय मंत्री जी जब वहां जाते हैं तो इनकी तबियत खराब हो जाती है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं और कहता हूं कि यदि यह बात गलत सिद्ध हो तो आप जो सजा चाहें मुझे दें, मैं सहन करने के लिये तैयार हूं, लेकिन आप पहाड़ के लोगों को धोखा कब तक देंगे। पानी सबको प्यारा है। हमारे यहां नैथना पेयजल योजना बनी, जिसने 115 गांवों को पानी देना था लेकिन 22-23 गांवों को पानी मिल रहा है, वह भी बदस्तूर नहीं मिल रहा है। चीफ इंजीनियर और सुपरिण्टेण्डिंग इंजीनियर कहते हैं कि इसका पाइप बदला जाय क्योंकि इतने गांवों को पानी इन पाइप्स से नहीं दिया जा सकता है।

दूसरी बात पहाड़ के लोगों के पास नौकरी के अलावा कोई और जरिया नहीं है। अब तक इससे पहले जब अंग्रेजों की सरकार थी तो पहाड़ के लोगों को फौज में भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन आज आपकी कृपा से, चूंकि हमारी ईमानदार सरकार है, फौज में भी दो हजार रुपया भर्ती करने का लिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ईमानदार सरकार है। मैंने पहले कहा था आज भी कहता हूं कि हमारे पहाड़ों में एक पेड़ होता है जो ऊपर से चलता है, इसी तरह से आपके विभागों में भ्रष्टाचार का जोर ऊपर से चलता है। उसका नतीजा यह है कि आज पहाड़ के सारे नौजवान मैदानी हिस्सों में पड़े ठोकरें खा रहे हैं। एक मापदण्ड रखा गया है फौज में भर्ती होने का 5 फिट 5 इंच लम्बाई और 32 फिट कुछ इंच गोलाई। मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि आपको पहाड़ों से हमदर्दी है तो वहां की गरीबी कैसे दूर होगी और वहां के लोगों को कैसे आप रोजी रोटी दे सकते हैं, इस पर विचार करें। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इसके लिये सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं कि जैसा पहले मुख्य मंत्री ने घोषणा किया था कि हम पहाड़ में अलग से पुलिस कंपनी बना रहे हैं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो गया है वह अभी तक कम्पनी नहीं बना पाये हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उसमें जो आपने सीमा बांध रखी है जैसे लम्बाई 5 फीट 5 इंच है तो इसको घटाकर 5 फीट 3 इंच कर दें और सीने की नाप 32 इंच रखें, यह सुविधा पहाड़ के लोगों के लिये कर दें तो अच्छा होगा।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पर्यटन पहाड़ों के लिये उपयोगी है। वहां की गरीबी को दूर करने का उपाय है कि वहां पर्यटन का विकास करें। मान्यवर, मुझे जर्मन जाने का अवसर मिला है। वहां मैंने देखा है कि किस तरह पर्यटन का विकास उन लोगों ने किया है। ज्यादातर मुझे पहाड़ों में जाने का अवसर मिला है तो उन्होंने अपने यहां जो पहाड़ है उनको सुन्दर सजा रखा है, चरागाह उन्होंने बना रखे हैं और जगह-जगह पर प्राइवेट लोगों को पर्यटन गृह बनाने की इजाजत दे रखी है और गांवों में उन्होंने होटल बना रखे हैं। जबकि हमारे यहां उसके विपरीत है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पर्यटन के संबंध में आप इस समय बंगले यदि नहीं बना सकते हैं तो आप छोलदारी की व्यवस्था कर दें। मान्यवर, पिंडारी-ग्लेशियर सड़क पर छोलदारी की व्यवस्था करा दें और जो पर्यटक जायें उनको एक रुपया में उसमें रहने की व्यवस्था, साथ ही साथ वहां खाने की भी व्यवस्था करा दें और वहां घोड़े की भी व्यवस्था करें जिससे वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही साथ मान्यवर, वहां-जहां ग्लेशियर है उनका प्रचार करें क्योंकि बद्रीनाथ, मंसूरी, नैनीताल जाने के लिये प्रचार न भी करें तो भी वहां लोग जायेंगे।

मान्यवर, ढेकाला विदेशी लोग जाते हैं और भारतवासी कम जाते हैं क्योंकि वहां रहने की व्यवस्था जो है वह बड़ी मंहगी है क्योंकि बंगले जो हैं वह खर्चीले हैं, इसलिये वहां भी छोलदारी की व्यवस्था करें।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने पर्यटन पर पैसा कम रखा है और कहते हैं कि हम पर्यटन का विकास कैसे करेंगे। इसके अलावा मैं मंत्री जी की अक्लमंदी पर बधाई देता हूं कि गोपेश्वर में आप स्टेडियम बनाने जा रहे हैं जबकि वहां की 80 प्रतिशत जनता ऐसी है जिसको नमक रोटी खाने को नहीं मिलता है। इसलिये स्टेडियम को बनाने की बात न करें बल्कि वह पैसा दूसरी चीजों पर खर्च करें।

कोई वकील है, ठेकेदार है। मैं सीधे गांव से आया हूं मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हमारी घरवाली यहां आई तो नल देखा, सिनेमा तो देखा ही नहीं, बिजली बटन यहां देखी। हम घर में हल चलाते हैं हमारी घर वाली खेतों में काम करती है। सुबह से शाम तक पहाड़ की औरतें कोल्हू की बैल की तरह खटती हैं। पहाड़ पर औरतें 18–20 किलोमीटर से लकड़ी लाती हैं, और कभी-कभी तो रास्ते में बच्चे हो जाते हैं और अस्पताल न होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। डेढ़-डेढ़, दो-दो मील से पानी लाती हैं।

मान्यवर, आप कभी महिला वर्ष मना रहे हैं कभी विकलांग वर्ष मना रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल के लिए अस्पताल की व्यवस्था की जाय। पानी मान्यवर, दो-दो किलो मीटर दूर से वहां की औरतें लाती हैं। आप का विभाग कितना पानी दे रहा है आपका कोई इंजीनियर ईमानदार है और कुछ करना चाहता है तो उसको आप सीमेंट नहीं दे रहे हैं कैसे काम चलेगा। आप उनको सीमेंट दीजिये। दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि पहाड़ों पर रेल नहीं जाती है जिन्होंने पहाड़ नहीं देखा है वह तो यही जानते हैं कि वहां रेल जाती है, रिक्शा जाता है, बग्घी जाती है। किन्तु मान्यवर, आप तो जानते हैं कि पहाड़ पर ट्रक और बस चलती है इसके अलावा हम घोड़ों से सामान ले जा सकते हैं। मान्यवर, दूसरे नम्बर पर आता है उद्योग। आपमें बहुत से लोगों ने विदेश देखा है और पुस्तिका पढ़ी है किन्तु मैंने पुस्तिका नहीं पढ़ी, आपके सौभाग्य से मुझे जर्मनी जाने का मौका मिला। वहां मैंने अपनी आंखों से देखा जिस तरह से भारत वर्ष में 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। वहां जर्मन में भी पहले कृषि पर निर्भर थे। लेकिन आज बहुत कम व्यक्ति कृषि पर आश्रित हैं। बाकी सब उद्योग चलाते हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था कीजिये और लोगों को ट्रेनिंग दीजिये, पानी हमारे पास है बिजली पैदा कीजिये और लोगों को ट्रेनिंग दीजिये वह घरों में उद्योग चलायें। मान्यवर, पहाड़ पर एक जंगली बादाम होता है जो खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, और बड़ी ताकत उसमें होती है। गाचर मेले में वह बिकने आया था आपकी मोमफली तो 10 रुपये किलो बिक रही है और बादाम 8 रुपये में बिक रहा है। उसका प्रचार करें तो लोग खरीदें और गांव के बच्चे तोड़कर लायें और जगह जगह बिके। पहाड़ पर एक फल पैदा होता है जो खट्टा मीठा होता है। मान्यवर, वहां पर करौंद पैदा होता है, यहां पर उसको करौंदा कहते हैं, यह वहां पर जंगल में काफी मात्रा में पैदा होता है, अगर इस पर हार्टीकल्चर के जो विद्वान हैं अगर वह इसकी कलम कर दें तो इसकी पैदावार बढ़ सकती है। इसका अचार बहुत अच्छा होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। मान्यवर, इसी तरह से किलमोड़ा होता है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट---

मान्यवर, सुनिये, पहाड़ों का बराबर दोहन हुआ और आप बोलने के लिये समय भी नहीं देते हैं। माननीय मंत्री जी भी हमको नहीं सुनते हैं। तो मान्यवर, इन तमाम परिस्थितियों को देखते (इस समय 3 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करेंगे, जब तक हमारा अलग राज्य हमको नहीं मिलता मैं समझता हूं कि तब तक पहाड़ों का विकास नहीं होगा। आप हमको धोखा दे रहे हैं पर्वतीय विकास के नाम से। इन शब्दों के साथ डाक्टर शिवानन्द नौटियाल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम कुमार भार्गव---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, पहाड़ों के संबंध में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, कुछ ही बार मुझे वहां जाने का मौका मिला है। आज बजट पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं इसलिये कि कुछ लोगों ने, जब पहाड़ों की प्रगति की बात हो रही थी, तो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। माननीय दहेलवी जी बोल रहे थे कि हमारे माननीय मंत्री जी को किसी ने समर्थन नहीं दिया। माननीय दहेलवी जी ने जो बात कही थी उसका जवाब देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं, उन्होंने कहा कि किसी सदस्य ने चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, बजट का समर्थन नहीं किया इसलिये उनका नैतिक कर्तव्य है कि इस्तीफा दे देना चाहिये। माननीय दहेलवी जी अपनी बात कहने में सक्षम हैं अभी भी वह पुराने चश्मे से देखते हैं, उठा-पटक की राजनीति करते हैं। इधर से उधर आ गये लेकिन नजरिया नहीं बदला। इधर का प्रत्येक सदस्य अपने देश की प्रगति के प्रति अपना कर्तव्य समझता है। जिस तरह से घर की सजावट में ज्यादा से ज्यादा सजावट होती चली जाती है और मन नहीं भरता है उसी तरह से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये, बुलंदी पर खड़ा करने की इच्छा मन में रहती है, इसलिये सुझाव दिये जाते हैं। दहेलवी साहब की समझ में यह आ रहा है कि समर्थन नहीं मिला। यह भूल गये हैं, इनके मंत्रित्व के जमाने में अपने कुत्ते को मोटर में बैठाते थे, और जब हट गयी तो अब इंसान के प्रति प्रेम आ गया है। क्या कहा जाय दहेलवी जी को। इस बजट पर डाक्टर साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा। डाक्टर साहब वरिष्ठ सदस्य हैं। आज तक आप ही बतायें इतिहास में शायद ही इतना बड़ा बजट, देश के एक प्रदेश, हिमांचल प्रदेश के पूरे बजट के बराबर, हमको बजट दिया गया है पर्वतीय विकास के लिये। इसके लिये हमारी वर्तमान सरकार और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बधाई के पात्र हैं। हमारे मंत्री जी पहाड़ों के रहने वाले हैं, शायद ही उन्होंने कोई चीज छोड़ी हो, सिंचाई, पानी, टूरिस्ट अस्पताल, सड़कें सब चीजों पर बजट है। अगर इसी तरह से पहले प्रगति हुई होती तो पहाड़ों का विकास हुआ होता। इसकी वजह यही रही कि पहले उसे खाली राजनीति मुद्दा बनाते रहे। आज इसीलिये बहुत ज्यादा प्रगति का कार्य भी कम दिखायी पड़ रही है। वहां की मातायें हंसते हुये अपने बेटों को फौज में भेजती हैं। इस वक्त जब पड़ोसी पर विश्वास नहीं करता है, भारतीय संस्कृति का जीता जागता सबूत पहाड़ों पर मिलता है जहां खुले दिल के लोग, इंसान से इंसान में प्यार करने वाले लोग वहां रहते हैं। उनको आम जरूरतों की चीजें मुहैय्या नहीं हैं, जैसा कि बिष्ट जी ने कहा, पानी की व्यवस्था, उद्योग और अस्पतालों की व्यवस्था तथा नमक के साथ रोटी खाने की बातें कहीं, यह सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी है पूरा करने की और पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के उत्थान और पिछड़े हुए इलाकों के विकास के लिए मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि वहां पर वहां के रा-मैटिरियल्स से संबंधित उद्योग लगाये जाएं, और इससे संबंधित जो योजना वहां लागू करने की घोषणा माननीय मंत्री जी ने दी है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि इन उद्योगों के लिए वहां के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएट और बड़ी-बड़ी डिग्रियां लिये घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल सके और एक बात जानकारी में यह आयी कि वहां के एक विश्वविद्यालय को मान्यता नहीं दी जा रही है, लगभग 3 साल

से तो इसके लिए जरूर मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने बजट प्रस्ताव में इस बात की अवश्य घोषणा करें। यह बहुत ही गंभीर बात है। मा0 मंत्री जी ने वहां पर उद्योग लगाने की बात कही, विकास के लिए कहा, बड़ी खुशी हुई, वहां पर तो इसके लिए प्रकृति का भी सहयोग है, तमाम किस्म के फल और फूल वहां होते हैं, फिर भी वह इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। एक छोटा सा कस्बा लखनऊ का ले लीजिये मलिहाबाद, इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा हुआ है। इसीलिए आज इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वहां के लोगों की हर दृष्टि से प्रगति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, पिछले वर्ष के बजट में हमने पहले ही कहा था कि यह बजट एक धोखा है और आज भी कह रहा हूं कि यह धोखे का बजट है और पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। पिछले बजट में माननीय मंत्री जी ने 3 घोषणाएं की थीं। एक तो यह कि वे हिल कैडर पर्वतीय क्षेत्र में लागू करेंगे। दूसरे यह कि वे बेसिक एजूकेशन में 25-1 का रेशियो अध्यापकों में लायेंगे और तीसरे यह कि जल निगम और जल-संस्थान को एक करके पर्वतीय क्षेत्र में फैली हुई विषमता को दूर करेंगे। तो माननीय मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इन तीनों में से अब तक कौन सी अपनी योजना चलायी। इसके अलावा मान्यवर, आज हमारे यहां विद्यालयों का हाल देखिये। मुझे अभी अभी अपने क्षेत्र में जाने का मौका मिला। मैं शिक्षा की बात कहूंगा मैं सुआरी में गया, जो बहुत बड़ा गांव है, वहां एक हाई स्कूल है। और न तो वहां साइन्स का अध्यापक है, न वहां गणित और एग्रीकल्चर का अध्यापक है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज कल बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं और इस तरह के प्रबन्ध से पर्वतीय क्षेत्र के विकास के नाम पर हमारे बच्चों का मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरे स्थान पर गया, वहां के अस्पताल की हालत देखी कि सफ्दर हाल में एक महीने से न तो वहां डाक्टर है और न ही दवाइयां। वहां के लिए मैंने पहले भी कई बार शिकायतें की, और बराबर शिकायत करता रहा हूं, इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरे स्थान पर गया खोला गांव में, जहां पर 200 फैमिलियों की आबादी है, लेकिन वहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरे स्थान पर गया खोला गांव में, जहां पर 200 फैमिलियों की आबादी है, लेकिन वहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां के लोग किसी दूसरे गांव में जाने के लिए आज बाध्य हो गये हैं। तो माननीय मंत्री जी इस ओर भी कृपया ध्यान दें जो इंसान की पहली जरूरत की चीजें हैं, जिनके अभाव में आदमी जिंदा नहीं रह सकता और आगे के विकास की बातें कर रहे हैं।

दूसरे हमारा गांव रीठाखाल है, वहां पर एक अस्पताल खोला गया है, जहां मुझे देखने को मिला कि बड़े गंदे से कमरे हैं, उसमें न कुर्सी है और न मेज की व्यवस्था है, और डाक्टर भी अभी वहां पोस्ट नहीं हुए हैं और न ही फार्मेसिस्ट हैं वहां। मैंने वहां के कम्पांउडर से पूछा कि यहां कौन कौन सी दवाएं हैं तो उसने बताया कि 5 पेंसलीन के इन्जेक्शन हैं, 7 सल्फाडाइजिन की गोलियां और 7 अन्य गोलियां। तो मान्यवर, सारी दवाएं वहां की कहां गयीं जबकि पिछले साल का आपका बजट 86 करोड़ का था। यह हाल है वहां के विकास कार्यों का, और जनता के उत्थान का।

मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी का पर्वतीय क्षेत्र का दौरा होता है सारे अधिकारी मंत्री जी के पीछे भागने की होड़ लगाये हैं, उनको काम से कोई मतलब नहीं है, केवल मंत्री जी के शुभचिन्तक बनना चाहते हैं। 40-40 गाड़ियां पूरे मण्डल की मंत्री जी के पीछे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी]

भाग रहीं हैं। मंत्री जी किसी से बात करने के लिये तैयार नहीं, उन्हें अधिकारियों से ही फुर्सत नहीं है।

मैं बड़े अदब के साथ माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप क्षेत्र में गये। अपने क्षेत्र में जा कर क्या किसी अस्पताल को, किसी स्कूल को या क्या आपने किसी पेय जल योजना को देखने की कोशिश की? पेय जल की स्कीम बन गयी है, पैसा उस पर खर्च हो चुका है लेकिन गांव को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है मान्यवर, सारी स्कीमें कागजों में बन चुकी हैं। आज हम चाहते हैं कि कोई लाइबिलिटी को समझें और कृपा करके उन अधिकारियों पर जिन्होंने गलत स्कीमें बना कर जनता के साथ धोखा किया है, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करें और उन्हें दंडित करें। एक बड़ा अजीब माहौल है मान्यवर, हमारे पर्वतीय विकास क्षेत्र में कि आज कोई भी अधिकारी हम विरोधी पक्ष के एम0 एल0 एज0 की बात सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे डर है कि यह बात मंत्री जी के पास तक न पहुंच जाय कि वह विरोधी दल के एम0 एल0 ए0 से बात कर रहा था।

मैंने पिछले बजट के समय में पर्वतीय विकास के मामलों के संबंध में मंत्री जी को सहयोग देने के लिये कहा था और पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक में भी हमने यह बात कही थी और आज भी कहते हैं कि आप विकास करिये, हम आपके साथ हैं।

मान्यवर, 11 अस्पताल इस साल मंत्री जी ने खोले हैं। दो चुनाव क्षेत्रों में और तीन अपने क्षेत्र में। अब मंत्री जी के कांस्टीटुएन्सी में 8 अस्पताल हो गये हैं। क्या बंटवारा किया है इस तरह के तरीके से। 84 किलो मीटर की सड़क इस साल उन्होंने दिया है। जिसमें से 20 किलो मीटर सड़क हमारे क्षेत्र में दी है और 64 किलो मीटर सड़क स्वयं अपने क्षेत्र में ले गये हैं। मेरे यहां जो पिछली सरकार की चार सड़कें स्वीकृत थीं, उनको बंद करने के आपने आदेश दे दिये। इस मामले को मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा, पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक में भी उठाया माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध किया कि आप उन सड़कों को बनाने के आदेश दे दें कि ये सड़कें पुनः चालू कर दी जाय, लेकिन आज तक उन सड़कों पर निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ। एक इंच भी सड़क हमारे पर्वतीय क्षेत्र की आगे नहीं बढ़ी है।

अभी एक नई पेय जल योजना बनी है, पिछले मंत्री जी के काल में एक स्कूल नया खुला है जो जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। मैंने यहां बहुत लड़-झगड़ कर स्कूल यहां शासन से लिये दो स्कूलों के लिये मंत्री जी ने डंडी मार रखी है।

मान्यवर, जब स्वयं मंत्री जी कुछ नहीं कर पाये तो उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये पहले की बनी हुई सड़कों का उद्घाटन करना शुरू कर दिया। जहां उद्घाटन करने जाते हैं वहां बड़ा आदमकद पत्थर अपने नाम का लगवा देते हैं।

एक बड़े दुख की बात मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि यह एक बड़ी गलत परम्परा रख रहे हैं कि माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा, जी ने एक सड़क बनवाई थी, उसका उन्होंने उद्घाटन किया था उसमें शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ था। उस शिलान्यास के पत्थर को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। मान्यवर, इसकी इनक्वायरी होनी चाहिये कि ऐसा गलत काम कौन कर रहा है या कौन करा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में बड़ा शांत वातावरण था लेकिन अभी हम बता रहे हैं इस माननीय सदन में और दफा 301 में भी हमने निवेदन किया था कि पहाड़ों पर भी डर व्याप्त हो गया और आज कोटद्वार का बावर इलाका जहां मंत्री स्वयं रहते हैं, वहां इतना भय व्याप्त है कि वहां रात को कोई सोता नहीं है और कई घर लूटे गये, कई लोगों की जाने चली गयी.। शासन व्यवस्था इतनी कमजोर हो गयी है कि आम आदमी पहाड़ों में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सचमुच अगर विकास की बात करते

हैं, अगर उनको पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना है तो ठंढे दिल से सोचें, सब लोगों का सहयोग लें और मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि कृपया नोट कर लें।

विद्यालय अगर खोलने हैं, इण्टरमीडिएट कालेज नहीं चाहिए। अगर आप साइंस नहीं देते हैं। हम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। हो सकता है एक विशेष क्षेत्र में साइंटिस्ट, डाक्टर निकल सकें, इसलिये मेरा सुझाव है कि जितने भी इण्टर मीडिएट कालेज हैं उनमें अनिवार्य रूप से साइंस कर दें। प्रान्तीयकरण विद्यालयों का होता है। उनके अध्यापक आज मान्यवर दुःखी हैं। प्रान्तीयकरण के समय जो स्केल मिलता था, अगर अस्थाई थे तो स्थाई नहीं किया गया। आज बड़ी निराशा है। मैं चाहूंगा कि इसकी तुरन्त व्यवस्था की जाये। मैं चाहता हूं कि जो व्यवस्था पहले प्रान्तीयकरण के समय थी वह बाद में भी रखी जाये और इसी तरह से जो हास्पिटल्स हैं, उनके संबंध में मेरा सुझाव है कि हास्पिटल खोलते ही पहले बिल्डिंग बना दें, पूरे इक्विपमेंट दे दें, डाक्टर को पोस्ट कर दें, तभी चल सकता है वरना जनता के साथ खिलवाड़ होगा। जनता सोचती है कि अस्पताल है, डाक्टर लेने जा सकते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे बे-मौत मारे जाते हैं।

मंहगाई के इस युग में मुख्यालय पौड़ी में आज एक आक्ट्राय शुरू हुआ है। एक ट्रक के सामान पर साढ़े तीन सौ चुंगी दी जायेगी। इसके अलावा मान्यवर, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिए बड़ा स्कोप है। फारेस्ट इण्डस्ट्रीज हमारे यहां लगे। स्पोर्ट्स गुड्स के लिये जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है, सामान का सारा कच्चा माल हमारे यहां से जाता है। चमखड़ी एक पेड़ होता है वह जाता है। मंत्री जी, पौड़ी मण्डल का मुख्यालय है। जब तक मुख्यालय का डेवलपमेन्ट नहीं होगा तब तक आपका यह डेवलपमेन्ट नामुमकिन है। आपने आफिसर्स होस्टल एक देहरादून में बनाने का प्राविधान किया है और एक गोपेश्वर में। लेकिन आपने पौड़ी में आफिसर्स होस्टल खोलने की सोची भी नहीं। यह एक बड़ा मजाक हम लोगों के साथ है। पौड़ी जिले का नहीं मण्डल का मुख्यालय है और जितने भी अधिकारी वहां पर हैं वह वहां पर इसीलिये नहीं टिकते कि रहने के लिए, दफ्तर के लिये, कोई व्यवस्था नहीं है। एक मांग थी बहुत पहले से मुख्यालय की कि वहां एक मिनी सेक्रेटेरियट बना दिया जाये लेकिन इस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। मुझे बड़ा दुःख है कि इस ओर आपकी सुदृष्टि नहीं हुई। मैं निवेदन करूंगा कि पौड़ी मण्डल के विकास को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से आप इस ओर ध्यान दें। अभी तक उस मण्डल के मुख्यालय में टूरिस्ट रेस्ट हाउसेज नहीं है। एक बड़ी अनोखी बात है। जितने भी आगे प्रपोज्ड किये गये हैं वह पौड़ी में नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस दिशा में सोचें और यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है। सभी विधायकों ने कहा है कि आप जब भी कोई विकास कार्य प्रपोज करते हैं तो उससे पहले सभी विधायकों की राय ले लें तो उचित होगा, भले ही आप राय न मानें लेकिन यह प्रजातांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है कि आज विकास के मामलों में विधायकों को नहीं पूछा जाता है। एक बात और मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 4 सड़कें हैं उन सड़कों को बन्द कर दिया गया था। उन सड़कों के बारे में यह चाहूंगा कि मंत्री जी यह घोषणा कर दें कि वे सड़कें पूर्वतः चलेंगी।

श्री अध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हो चुका है। अब काफी समय हो गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी––

एक बात मान्यवर, और कहकर खत्म करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री इस समय यहां पर हैं नहीं, मैंने जब अस्पतालों के बारे में उनसे कहा था तो उन्होंने जवाब दिया

[श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी]—

कि पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी इलाके से डाक्टर जाना नहीं चाहते इसके लिए आप व्यवस्था करें। मंत्री जी जैसी कि मुझे जानकारी है वहां पर 60 स्थान चिकित्सकों के लिये खाली हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी वहां पर नहीं है। वहां पर लेडी डाक्टर नहीं है। वहां पर डाक्टरों के 11, सिस्टर के 10, स्टाफ नर्सेज के 12 और इसी तरह से अन्य कई और स्थान वहां पर रिक्त हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी आ गये। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की इन समस्याओं को ध्यान में रखें कि वहां के अस्पताल कैसे चलाये जायें या मैदानी क्षेत्र के डाक्टर पर्वतीय क्षेत्र में क्यों नहीं जाते हैं। आपने हिल कैडर की बात कही है, उनको हम लेने के लिए तैयार हैं लेकिन लोग जो भर्ती किये जायें वह केवल हिल्स के किये जायें, यह मेरा सुझाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नौटियाल जी का समर्थन करता हूं।

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमें पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं पर्वतीय विकास के बजट पर जो माननीय मंत्री जी ने रखा है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। दरअसल में मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारे साथी, माननीय विधायक, इस पक्ष के तथा उस पक्ष के माननीय सदस्य और वक्ता लोगों ने एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाया है। वह कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र को काफी बजट दिया जा रहा है। यह भी निश्चित है कि मंत्री जी, मुख्य मंत्री और उनके वरिष्ट सहयोगी बहुत ही योग्य हैं। यह भी लोगों का विचार है कि हमारे ऊपर के अधिकारी भी काफी योग्य हैं। फिर यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह जो बजट दिया जाता है यह कहां चला जाता है। इसकी प्रगति कहां चली जाती है। मेरी समझ में एक बात यह आ रही है कि वाकई जो आदेश होते हैं उनका समुचित पालन शायद नहीं हो पाता। तो मैं इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस को ज्यादा केयरफुली देखें कि ज्यादा से ज्यादा आदेशों का पालन हो।

मान्यवर, हमारे सूबे में जंगल कम हैं। दरअसल किसी देश के पर्यावरण को दुरुस्त रखने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए, 30 से 33 प्रतिशत तक जंगल होने चाहिए। मौजूदा समय में लगभग 15 से 17 फीसदी जंगल हमारे यहां हैं। इसका कारण यह है कि जंगलों की अंधाधुन्ध कटाई। मैं अपना सुझाव देता हूं कि आगे जंगलों का कटान सरकार ज्यादा से ज्यादा रोकने का प्रयास करे जिससे पर्यावरण आगे ठीक ठाक रहे। मान्यवर, जंगलों के रहने से काफी फायदे भी हैं। सबसे पहला यह है कि बाढ़ की समस्या कतई नहीं होगी। पेड़ों की वजह से पहाड़ों पर कटान कम होगा। सिल्टिंग कम होगी, नदियों की गहराई कम होगी, बाढ़ कम आयेगी। और दूसरी चीज यह कि पर्यावरण बिल्कुल ठीक-ठाक रहेगा। बरसात समय से होगी। साथ ही साथ जंगलों से इम्प्लाइमेन्ट के चान्सेज बहुत हैं। जंगलों से संबंधित उद्योग पहाड़ों पर लगाये जा सकेंगे।

पहाड़ों के बारे में मेरा यह ख्याल है कि जनरल सर्वे करा लिया जाय कि किस बैल्ट पर, किस हाइट पर, किस किस्म के पेड़ों का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस सिलसिले में एक हाई लेबल कमेटी द्वारा पूरे पहाड़ की सर्वे करा ली जाय। और उस रिपोर्ट के मुताबिक उस का डेवलेपमेन्ट कराया जाय।

मान्यवर, मेरी समझ में यह बात आती है कि पहाड़ों पर जंगल से संबंधित उद्योग, पशु-पालन, ये मुख्य उद्योग चल सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया कि पहाड़ों में जो जड़ी बूटियां होती हैं उनसे आयुर्वेदिक उद्योग चलाये जा सकते हैं। इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर चर्चा समाप्त हो गई। अब कटौती के प्रस्तावक बोलेंगे।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं समझता हूं कि आप के कुशल निर्देशन के आधार पर शनि का दिन भी अच्छा गुजरा है। मुझे तो ऐसा लगता था कि कभी-कभी शनि की दृष्टि बक्र हो जाती है लेकिन आज लगता है कि यह उल्टा हो गया। इस माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने, मान्यवर, अपने मुख से जो बातें कहीं हैं और यहां पर सुनी है, वह इस बात की साक्षी है कि सब ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में पर्वतीय विकास की जो बात है उसकी पूर्णतया सफलता की बात स्वीकार की है। मैं दोनों तरफ से माननीय सदस्यों का इस बात के लिये हृदय से स्वागत करता हूं और मान्यवर, यह तो यहां एक परम्परा रही है कि इतनी भारी मेजोरिटी, बहुसंख्या होने के बाद भले ही चाहे आज इस बजट को आप पास करा लें लेकिन, मान्यवर, यह शनि की दृष्टि बक्र ही रहेगी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के लिए, मान्यवर, आपकी दृष्टि सम नहीं बनी है। मैंने पहले भी निवेदन किया था और पुनः दोहराना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी भी उपस्थित हो गये हैं इसलिये भी कहना चाहता हूं कि यह जो बजट पर्वतीय क्षेत्र के लिये बना है इसको आप फिर से दोबारा देख लें। मैं जानता हूं कि हमारी लाख चेष्टा करने के बाद भी यह बजट पास हो जायेगा लेकिन पर्वतीय जनता के सामने न तो मुख्य मंत्री जी, न प्रधान मंत्री जी, न वित्त मंत्री जी और न ही पर्वतीय राज्य मंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं। मेरा बिलकुल सही और स्पष्ट कहना है कि जब मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आधा हम लोग देते हैं और आधा केन्द्र से मिलता है तो जब 350 करोड़ रुपया हमको केन्द्र से मिल गया तो 350 करोड़ रुपया हमको इस प्रदेश की ओर से मिलना चाहिए। इस दृष्टि से 700 करोड़ रुपया हो गया।

श्री ब्रह्म दत्त--

इतने का क्या करोगे?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

देखिये साहब, शनि बोलने लगे। क्या करेंगे इतने पैसे का ? पहाड़ वाले इतने रुपये का क्या करेंगे? यही आपका मंत्रि-मंडल चाहता है। हम तो जीना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि क्या करोगे। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले जून के महीने में जो पर्वतीय क्षेत्र के लिये और इस प्रदेश के लिये प्लानिंग कमीशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें 15 प्रतिशत वेस्टेज देने की बात कही गयी थी। मान्यवर, उसके आधार पर हमको बजट मिलना चाहिये। इस हिसाब से 930 करोड़ प्रदेश का हिस्सा और 930 करोड़ केन्द्र का बनता है। मान्यवर, ये तो हमारे यहां भी डाका डाल गये। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि 4.3 प्रतिशत पापुलेशन हिल्स की है। उस हिसाब से भी 279 करोड़ रुपये होता है और उसमें 350 करोड़ रुपया जोड़ लिया जाय तो वह 629 करोड़ रुपया होता है और जब कि आपने केवल 570 करोड़ रुपया दिया है। मान्यवर, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप बजट देने में किसी तरह की कमी न करें, बजट न काटें। वरना पहाड़ की जनता भड़क जायेगी और मैं माननीय बलदेव सिंह आर्य की बात दुहराना चाहता हूं कि वह सारा का सारा सीमान्त का क्षेत्र भभक रहा है। अगर उसको मालूम हो जाय कि हमारी उपेक्षा हो रही है तो देश और प्रदेश की जनता को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिये मैं आपको पहले ही से आगाह कर देना चाहता हूं।

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—]

यहां पर कुछ मित्रों ने एक बात कही। माननीय बहुगुणा जी का नाम लिया गया। माननीय धवन जी ने कहा मैं उसको पिष्ट-पेषण नहीं करना चाहूंगा लेकिन सम्मानित सदन को सत्यता से अवगत कराना चाहता हूं कि सन् 1974 में जब माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा यहां पर मुख्य मंत्री थे जिन्होंने पहली बार पर्वतीय अंचलों के लिये अलग से बजट बनाया था और पहली बार पहाड़ों के बारे में अलग से सोचा जाने लगा था। 1962 में यहां पर आक्रमण हुआ, 1960 में सीमान्त में चीन ने आक्रमण किया, बदरीनाथ तक वे आ गये थे लेकिन किसी ने पहाड़ के लिये अलग से बजट देने की बात नहीं की। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वही प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री उपलब्ध हुये जिन्होंने पहली बार पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कुछ सोचा और उसके लिये अलग से बजट बनाया। इसके अलावा जब वे वित्त मंत्री थे तो उन्होंने दिल्ली में प्लानिंग कमीशन के अन्तर्गत एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें यहां के प्लानिंग सेक्रेटरी को भी बुलाया गया था और पहाड़ के एरिये के हिसाब से जो कि प्रदेश का 17.4 प्रतिशत है, हमारा बजट स्वीकार करवाया था। जब कि प्रदेश का अंशदान 1078.8 लाख और इतना ही केन्द्र का अर्थात 2157 करोड़ 6 लाख का बजट उन्होंने स्वीकार करवाया था।

इसके अलावा मान्यवर, उन्होंने प्रशासनिक इकाइयों को कम करने की पूरी सिफारिश की थी और कहा था कि पहाड़ों का भला तब हो सकता है जब कि वहां की प्रशासनिक इकाइयों को छोटा कर दिया जाय जैसे कमिश्नरी को जिला और जिले को तहसील बना दिया जाय और इसी तरह से ब्लॉक को और छोटा कर दिया जाय। सफलता असफलता अपनी जगह पर है। जहां तक प्रयास करने का प्रश्न है हम यही तो कह रहे हैं कि सरकार प्रयास करे अगर प्रयास ही नहीं किया जायेगा तो कैसे बात बनेगी जैसा आर्य जी ने कहा जमीन में तो चीज आये मैं उन्हीं की बात दोहराता हूं आप की सड़कें मंजूर हैं 8 सौ कि0 मी0 लेकिन हमें एक कि0 मी0 तो बनी हुई दिखाइये। आप कहते हैं कि हमने इतनी पेयजल की योजनायें दी तो एक योजना में पानी चलते हुए दिखाईये। हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि पर्वतीय जनता अच्छी तरह से जानती है कि क्या हो रहा है।

मान्यवर, माननीय धवन जी ने कहा कि आजकल गुंडों का राज्य हो गया है उन्होंने स्वयं स्वीकार किया क्योंकि इनका एक गुंडा जब माननीय मुख्य मंत्री जी कोटद्वार गये थे तो 302 धारा वाला व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी होने के लिए वारंट है वह उन की अगवानी मोटर साइकिल में कर रहा था। एक मकान का उद्घाटन जो 7 साल पहले बना था मुख्य मंत्री जी कर रहे थे, ठीक है करना चाहिये हमें कोई आपत्ति नहीं। तो वहां कोटद्वार के इंस्पेक्टर ने कहा जिसको पकड़ने के लिये हमारे पास वारंट है तो जब वह माननीय मुख्य मंत्री जी की अगवानी कर रहा है तो हम उसको कैसे पकड़ें क्योंकि उसको माननीय मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। मैं बताना चाहता हूं कि जब से माननीय मंत्री जी ने वहां शराब की दुकानें खुलवा दी हैं, सुरा की दुकानें खुलवा दी हैं, चमोली जिले में तो ऐसे तत्व पैदा हो गये हैं कि कभी आपको सूचना मिलेगी कि शिवानन्द नौटियाल जै-राम जी को हो गये। तो हमें तो यह भी खतरा है क्योंकि हमारा वहां जीना मुश्किल हो गया है। जब कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में कभी ऐसी वारदातें नहीं होती थीं, जहां यहां से लोग सुरक्षा के लिये जाते थे वहां दिनदहाड़े डकैतियां हो रही हैं, लूट हो रही है (व्यवधान) वह आपके साथी हैं धवन साहब, जितने इस प्रकार के लोग हैं सारे सत्ता के साथ हैं इस बात को कौन नहीं जानता है मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता हूं केवल हिंट के रूप में कहना चाहता हूं।

मान्यवर, बिहारी लाल जी ने एक बात कही कि हमको इतना बजट मिला है तो उस विषय में पहले मैंने कहा कि 20 करोड़ रुपये के बजट में से आपको 1 करोड़

10 लाख मिला है जो आप कहते हैं हरिजनों को दे दिया। तो वह 20 करोड़ रुपये कहां हैं, यह सरकार कहां ले गयी, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं इन्होंने कहा है कि हमारी एक योजना के अंतर्गत हरिजनों के लिये 100 करोड़ का प्राविधान केन्द्र ने किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि पर्वतीय जिलों के हरिजनों के लिये वह रुपया कहां है। मैं पर्वतीय मंत्री जी से भी जानना चाहता हूं वह बतायें। माननीय नेगी जी ने कहा कि 80 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं जिसमें 90 परसेंट लोग गांवों में रहने वाले लोग हैं। मैं जानना चाहता हूं माननीय नेगी जी से जिन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया है इसमें कहां पर पर्वतीय अंचल के लोगों के लिये बजट नजर आ रहा है? सब को आज यह जुकाम लगने लगा है कि आज से 5 साल पहले इतना बजट नहीं था। आपने यह भी देखा है कि चीजों के दाम कितना गुना बढ़ गये। मैंने पी0 डब्लू0 डी0 के एक इंजीनियर से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो सीमेन्ट के पुल आज से 5 साल पहले बनने वाले थे। उसके दाम अब 20 गुना ज्यादा हो गये हैं उन्होंने यही कहा कि साहब 20 टाइम्स इसके दाम बढ़ गये हैं और बजट तो हमेशा प्रगतिशील होता है। कौन कहता है कि बजट नीचे घटता है? बजट तो हमेशा बढ़ता ही रहता है और आप कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ है तो यह कौन सी नई बात है या खोजपूर्ण बात है। यह तो बढ़ेगा ही। अगला काम क्या है यह बताइये। आपके पास उसके लिए कोई कथन नहीं है (व्यवधान) उसको भी आप इसी बजट में मिला रहे हैं। वहां मनेरी और टिहरी बांध बन रहा है, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह भी उसी बजट से बन रहा है। हमको टिहरी और मनेरी बांध नहीं चाहिए, हमको पीने का पानी चाहिये। हम डूबना नहीं चाहते हैं। प्रदेश को पानी देने के लिए हम प्यासे रहते हैं तो प्रदेश का भी कर्त्तव्य है कि वह हमें पानी दे। मनेरी और टिहरी का पानी गढ़वाल के काम नहीं आयगा, यहां शारदा तक पानी आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा, हम दोना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं। हम इस अधिकार की बात करते हैं तो कोई गलत बात नहीं करते हैं। मैंने तो सबेरे ही कहा है, पहले ही कहा है कि 1 करोड़ 25 लाख रुपये लाचारी की हालत में खजाने में हर साल दे रहे हैं और इस तरह से पांच साल में यह रुपया सवा छः करोड़ हुआ और आप हमको योजना में 570 करोड़ ही दे रहे हैं। जितना हम दे रहे हैं उतना तो आप हम पर कम से कम खर्च करें। इस तरह की बात यदि माननीय सदस्य करेंगे तो पहाड़ बौखला जाएगा और वहां जो अलगाव की भावना पैदा हो रही है, वह ज्यादा जोर पकड़ेगी। हम जिन्दा ही रहना चाहते हैं और उसके लिए यदि हम कोई बात कहते हैं या करते हैं तो माननीय स्दस्यों को हमारा साथ देना चाहिए, ऐसी हम उनसे अपेक्षा करते हैं। माननीय नेगी जी ने उद्योग के साथ साथ हार्टीकल्चर की बात कही। सबने उस पर विशेष ध्यान दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं हार्टीकल्चर विभाग को कि उसने हार्टीकल्चर में लगातार पांच वर्ष तक पहाड़ों को पुरुस्कार दिलाए हैं। पांच पुरुस्कार बराबर हमको सेव के अलावा में मिले हैं। पर मार्केटिंग में हमारा सेव हिमांचल के नाम से बिकता है, तो इनके मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। आप उस पर 5 लाख रुपया दे रहे हैं, फिर भी बड़ा हंगामा। फिर से एक दफ्तर और बनाना चाहते हैं। पहले एक दफ्तर का काम तो संभल नहीं रहा है और ऊपर से सारे रुपये को उस दफ्तर पर लगाकर हमारी इकोनामी को कमजोर कर रहे हैं, इसका हमें सख्त अफसोस है। इस तरह से कृषि विभाग में सेव से उसकी पेटी की कीमत चौगुनी है और सेव दो आने किलो है। मार्केटिंग की स्थिति को यदि आपने नहीं सुधारा तो कैसे होगा? माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि जिला परिषद् का कम पैसा दिया। यह तो मैं सबेरे ही कह चुका हूं। हमारे यहां नगरपालिकाओं और नोटिफाईड एरियाज को जितना धन देना चाहिए, उतना उन्हें कतई नहीं मिला है। जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था तो मैंने देहरादून के लिए अलग से रुपया देकर सड़कों का वहां प्राविधान कराया था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने किया। इसलिए कह

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--]

रहा हूं कि करना चाहिए ताकि लोग वहां आयें। स्कूल, पेयजल और पी. डब्लू. डी. की बात कही गयी। इसमें कोई संदेह नहीं कि पी. डब्लू. डी. का हमारे पहाड़ों पर बड़ा योगदान है, लेकिन सड़कों के लिये इंजीनियर नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? वहां बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं हैं, जिससे काम ही नहीं चल रहा है, तो निर्माण कैसे होगा? सारे के सारे बजट का एक-चौथाई 84 करोड़ रुपया है, तो यह और कम होगा मैंने तो जोड़ा नहीं। इस समय तो 25 करोड़ रुपया दे दिया जिसमें से 1 1/2 करोड़ रुपया तो बुलडोजर के लिए और 1 1/2 करोड़ रुपया से ट्रक खरीदेंगे। तो इस 25 करोड़ रुपये में से ही सब कुछ आना है जो कि पी. डब्लू. डी. को दिया गया है। हमारे साथ एक और दुर्घटना हो गयी। पहले 2-3 हैड होते थे। एक 299, 499, और 699 जिसका मतलब यह होता था कि अगर पहाड़ों में किसी कारण से रुपया खर्च नहीं हो पाता था तो वह रुपया पहाड़ में ही रह जाता था और अगले साल दूसरे मद में या उसी में खर्च हो जाता था। पर इस शासन ने उसको खत्म कर दिया। शिक्षा विभाग में 50,000 रुपया सरेन्डर कर दिया। पिछले साल एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा? तो पहाड़ी इलाके में सरेन्डर वाली बात चलने वाली नहीं है। हम लोग सरेन्डर करने वाली नहीं हैं। आप भले ही सरेन्डर करें लेकिन हम नहीं करेंगे। इसलिये हम पूरे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी वहां की जनता जागरूक है और माननीय इंदिरा जी को चुनाव का बुखार है। जब वे चुनाव में चलती हैं तो 5 1/2 लाख रुपये साफ करने का बिल हो जाता है। मेरी प्रार्थना है कि इस तरह से हमारे रुपये का आप दुरुपयोग न कीजिए। पहाड़ के रुपये से आप चुनाव न करायें। वहां की जनता बहुत गरीब है, जो 2 टाइम रोटी खाकर जिन्दा रहना चाहती है। हमारे भाई बिहारी लाल जी ने सितारगंज की बात कही। मैं सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर और जितने भी नैनीताल में पूर आते हैं उन सब में आप मिलें लगवायें, हमें विरोध नहीं है। विरोध तो केवल इस बात से है कि आप वहां के रहने वाले लोगों को सुविधायें नहीं देते हैं। अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा जायेगा तो कोई काम ठीक नहीं हो सकता है।

स्कूलों का जहां तक संबंध है कहा गया कि वे खोल दिए गये, टीचर्स रख दिए गये। उनके रजिस्टर में मान्यवर, सब अध्यापकों की नियुक्ति है पर पहाड़ के एक विद्यालय में भी कोई अध्यापक नहीं है और न ये उनकी नियुक्ति ही करते हैं। हिल कैडर की बात कही जाती है लेकिन एक लड़के की भी नियुक्ति नहीं की है। तो यह स्वप्न है जिसे अधिक दिन तक नहीं दिखाया जा सकता है। स्कूलों में अध्यापक नहीं थे इम्तिहान 26 मार्च से आरम्भ हो गये। फिर कहते हैं कि लड़के नहीं थे। जब मास्टर ही नहीं थे तो लड़के कहां से होंगे जब स्कूल ही मार्च में खुल रहे हैं? यहां से मार्च के महीने में आदेश जाते हैं नये स्कूलों के खोलने के तो कैसे वहां पर नये लड़के मिल जायेंगे? इस प्रकार की अव्यवहारिकता और अनाचार पर्वतीय अंचल में हो रहा है। यह बजट ऐसा है जो पर्वतीय अंचल के लिए दुर्भाग्य का सूचक है और मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा यही है कि इस बजट को आपकी आज्ञा लेकर एक बार वापस ले लें और इस पर पुनः विचार करके, जो रुपया हमको मिलना चाहिये वह रुपया दिलवा कर, इसे फिर से प्रस्तुत करें, उस समय हम इसका समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव को चाहता हूं कि वह पूर्ववत् रहे।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

मान्यवर, सर्व प्रथम मैं माननीय विद्यासागर नौटियाल जी ने जो कुछ मूल रूप से प्रश्न उठाये हैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने कहा था कि 1980-81 में 76 करोड़ का प्राविधान था। सत्य यह था कि मूल आय-व्ययक जब पेश किया था तब वह 76 करोड़ कुछ का था, उसके बाद प्रथम अनुपूरक पेश किया गया जो 17 करोड़ 5 लाख 8 हजार का था। उसके बाद सूखा सहायता की मद में कुछ धन दिया

आया और यह सब मिला कर लगभग 93 करोड़ के ऊपर था। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और आश्वस्त करता हूं कि इसमें से कोई सेविंग नहीं होगी, सारी रकम खर्च कर ली जायेगी।

दूसरा प्रश्न माननीय नौटियाल जी ने पर्वतीय क्षेत्र के लिये प्रथम बजट शीर्षक 299, 499, 699 समाप्त किये जाने का प्रश्न उठाया। वह अब भी मौजूद है। बजट में नान प्लान भी पहले अलग से दिखाया जाता था और उक्त की समाप्ति के आदेश 31-8-79 को हुए जब कि सम्भवतः आप लोगों (विरोध पक्ष) की ही सरकार थी। हम इसको पुनः चालू करने पर विचार कर रहे हैं और एकाउन्टेंट जनरल से इस पर राय ली जा रही है।

आपने यह प्रश्न उठाया कि इस वर्ष 84 करोड़ का बजट है। गिनती में आपने ठीक कहा। स्थिति यह है कि एक माह का आप लेखानुदान पहले ही पास कर चुके हैं। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान विभाग से भी 3 करोड़ के लगभग की धन-राशि इसमें शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त आई0 आर0 डी0 राष्टीय ग्रामीण रोजगार आदि का प्राविधान भी इसमें सम्मिलित किया जाना है। इस सारे रुपये को मिलाकर यह बजट करीब एक अरब रुपये का हो जाता है।

आपके हृदय में पर्वतीय विकास के लिये व्यथा है, मैं उसे अच्छी तरह से समझता हूं और मैं निष्ठा और विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इधर से, और उधर से माननीय सदस्यों द्वारा जो भी रचनात्मक सुझाव दिये गये हैं उस पर अमल किया जायेगा।

पर्वतीय विकास परिषद् की मीटिंग बुलाकर उसमें भी आप सुझाव रख सकते हैं। गत वर्ष अक्टूबर में बजट पास हुआ था . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य--

पी0 डब्लू0 डी0 की जो कमेटी बनी है उसमें आपने ठेकेदारों को रखा है, हम लोगों को उसमें कहां रखा है?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

उसमें आपके एक श्री कृष्णानन्द जोशी हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एक उसमें श्री शेर सिंह दान हैं, यह भी भूतपूर्व सदस्य हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी अगर ठेकेदारों को सदस्य बना देंगे, तो हम लोगों का क्या होगा? क्या माननीय मन्त्री जी उनको वहां से हटा देंगे और उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रखने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

क्या जो विधायक नहीं रहे, वह कोई काम न करें ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, ठेकेदारों को अगर उसमें रख दिया जाता है, तो उससे तो अच्छा कार्य नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

जो पहले 78-83 योजना बन रही थी, उसमें 380 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्राविधान किया गया था, जिसमें 200 करोड़ रुपया सेन्ट्रल असिस्टेंस इंगित की गयी थी। इस समय हमारी योजना 80-85 में 570 करोड़ की है, जो 10 करोड़ ज्यादा हिमांचल प्रदेश से है और अगर प्रति व्यक्ति भी, जो मैंने पहले बताया था. . . .

(व्यवधान)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

प्रति व्यक्ति उसमें आप क्यों मिला रहे हैं? मैं अपनी सूचना के लिये चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

डाक्टर नौटियाल जी, वह बैठ नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं जब वह बैठ जायं तब आप बोलिये।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

माननीय जसवन्त सिंह जी ने पर्यटन के संबंध में काफी कुछ कहा और उनकी सूचना के लिये मैं बताना चाहूंगा कि पर्यटन में सारे प्रान्त का जितना आउटले है, उसका लगभग आधा सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र के लिये है और वह इसलिये है कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। किसी हद तक वह आपकी चिन्ता ठीक है, उसमें सिर्फ यह है कि उसका प्रस्ताव गढ़वाल मंडल विकास निगम से आना था। चूंकि 1 करोड़ रुपये से अधिक वह योजना थी, पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट ब्यूरो के थ्रू पास होना चाहिए। तीस तारीख को मीटिंग है, चेष्टा यह की जा रही है कि जल्द से जल्द उसको कराया जाय। तीसरा यह भी प्रश्न उठा और कहीं-कहीं लोगों के दिल में खटका भी है कि सितारगंज में चीनी मिल क्यों होनी चाहिए। अब जहां पर गन्ना है, वहां पर तो चीनी की मिल लगेगी ही। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग बसे हैं, उनके मन में ठेस न लगे कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक कारपोरेशन के चीफ जो मिस्टर जोशी हैं, उनसे मैंने कहा कि गढ़वाल मंडल का परीक्षण किया जाय। उनके बारे में बराबर भारत सरकार से बात कर रहे हैं। इस तरह की जो यूनिट्स हैं, जहां पर एयर कंडीशन्स के माध्यम से काम करना पड़ता है, जिस तरह से स्वीटजरलैंड में है, ...

(व्यवधान)

माननीय रियासत हुसैन साहब ने कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन पर हम पूरी तौर से विचार करेंगे और तद्नुसार कार्यवाही करने की भी चेष्टा करेंगे। यह प्रश्न उठाया गया कि कुछ स्थानों पर अस्पताल ज्यादा दे दिये गये हैं। स्थिति यह है कि असंतुलन जहां पर है, कुछ विकास खंडों में 2300, 2400 की आबादी पर एक अस्पताल है और कुछ में 11,000 की आबादी पर एक अस्पताल है उस असंतुलन को दूर करने के लिये कुछ स्थानों पर अधिक अस्पताल दे दिये गये हैं, इसमें कोई विशेष पक्षपात नहीं किया गया है। इसके अलावा यही रीति स्कूलों के मामले में बरती गयी है। जैसा मैंने कहा था पिछले वर्ष अक्टूबर में बजट पास हुआ था। मैं कुछ अस्वस्थ भी था। पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक हुई और समितियां बना दी गयी हैं जो इन सब बातों को एग्जामिन करेंगी और समितियों के द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर उनके निरूपण में सहायता मिलेगी। यह भी कहा गया कि बगैर भवन के अस्पताल तथा स्कूल क्यों खोल दिये जाते हैं? इसमें यह चेष्टा

संख्या 50–पर्वतीय विकास विभाग–अनुदान संख्या 87–पर्वतीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 117–पर्वतीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम

की है कि स्पेशल रिपेयर्स के लिये जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट स्कूल्स की इमारतों के लिये अधिक धन दे दिया गया ताकि उनके भवन बन जायें और यह तकलीफ कुछ हद तक दूर हो जाय। वैसे इस वर्ष बजट आउटले पिछले वर्ष की बजट से इस सम्बन्ध में अधिक रखा गया है लेकिन जब हम स्पेशल रिपेयर्स में अधिक रुपया खर्च कर देंगे तो स्कूल अधिक नहीं खोल सकते। श्री विद्या सागर नौटियाल जी ने माडल स्कूल की बात कही। 38 माडल स्कूल उनके यहां खोलने के आदेश चले गये हैं। चमोली में जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिये कह दिया गया है। इसके अलावा नरेन्द्र सिंह भंडारी के द्वारा कही गयी 5 सड़कों को चालू करने के लिये कह दिया गया है। उन पर काम शुरू हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि शिवानन्द नौटियाल जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

क्या शिवानन्द नौटियाल जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल––

मैंने बहुत से सवाल उठाये थे जिनका कोई निराकरण नहीं किया गया। लिहाजा वह स्वयं सिद्ध बात है कि उन्होंने मेरी बातों को स्वीकार कर लिया। ऐसी स्थिति में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–पर्वतीय विकास विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–पर्वतीय विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,99,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87–पर्वतीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87–पर्वतीय विकास विभाग -पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,69,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 117–पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 117 पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,24,01,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 में, जैसा मैंने पहले कहा था, माननीय श्री रियासत हुसैन तथा श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा दी गयी सूचना जो दिनांक 27-3-81 को उरई जिला जालौन के अन्तर्गत थाना चुर्खी के थानाध्यक्ष, एक सब-इन्सपेक्टर तथा एक सिपाही को डकैतों द्वारा मौत के घाट उतार देने के संबंध में है स्वीकृत की गयी और शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं। इस पर, जैसा पहले ही निश्चित हो चुका है, 30 मार्च को वक्तव्य होगा।

मिर्जापुर के रिहन्द बांध में नाव डूब जाने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष---

मद संख्या 10 स्थगित हो गया है, जैसा आपको सूचित किया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, वहां की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है, काफी लोग नाव दुर्घटना में मारे गये। 36 लाशें पायी गयीं, वहां लोगों ने लाशों को गंगा में डाल दिया, जहां वे सड़ रही हैं, पूरे शहर का पानी गंदा हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि वक्तव्य न दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

इसीलिये इस पर वक्तव्य जल्द से जल्द मांगा गया था। स्थगित तो कर दिया गया है, लेकिन मैंने आदेश दे दिया है कि 31 मार्च को वक्तव्य होगा। केवल एक दिन का ही समय बीच में है।

आगरा में सेना के खतरनाक एवं दूरगामी शस्त्रों का जखीरा पकड़े जाने के संबंध में 13 मार्च, 1981 को दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)---

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं संशोधन के लिये कुछ कहना चाहता हूं, जो उस दिन वक्तव्य दिया था उसमें क्लेरीकिल मिस्टेक टाइपिंग की हो गयी थी, उसमें 24-2-81 को.....

श्री विद्यासागर नौटियाल---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय मंत्री जी जो पढ़ रहे हैं, उसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी को मिल गयी है?

श्री अध्यक्ष---

माननीय नौटियाल जी, वह चर्चा के लिये वक्तव्य है, चर्चा के पहले अपने वक्तव्य का संशोधन दे रहे हैं, दे सकते हैं। उन्होंने मुझको भी सूचित किया था, स्वीकार कर रहे हैं, अपनी गलती को।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

24-2-81 के बजाय 28-2-81 है इसको मान लें और उसमें जो वजन 340 किलोग्राम बताया गया था उसमें मिलिटरी में प्रयोग होने वाले खाली खोखले में 900 ग्राम और निकला है।

13 मार्च, 1981 को दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आगरा में जो घटना घटी उस पर वक्तव्य दिया गया। लेकिन उस दिन इधर और उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्यों में इतनी उत्सुकता थी इस बात को जानने की जिज्ञासा थी और अनेकों तथ्यों को जानने के लिये। उस दिन यह आरोप लगाया गया था कि सरकार जानबूझ कर तथ्यों को छिपाना चाहती है जिससे षडयन्त्र का पर्दाफाश न होने पाये। जो दोषी है जिनके द्वारा यह षडयन्त्र किया गया है वह लोग बच जाय। इस संबंध में मैं उस दिन स्पष्टीकरण मांगा था आज मैं पुनः आदरणीय सदन के सामने सारी बात लाना चाहता हूं। 24 तारीख को एक विस्फोट हो गया, कुछ जानें चली गयीं, तलाशी ली गई जिससे ऐसे गम्भीर जालसाजी का षडयन्त्र सामने आया जो राष्ट्रव्यापी है। सेना के कारतूस, सेना की गेली, बम बरामद हुये जिससे राष्ट्र-व्यापी गिरोह पकड़ा गया। यह चन्डीगढ़, दिल्ली, बंगलौर, मद्रास में फैला हुआ है और इसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और राज नेताओं का हाथ है। जिसके कारण यह सफलतापूर्वक गिरोह काम कर रहा था। यह भी पता चला कि सेना की जो छावनी बबीना में है वहां से सामने ग्वालियर जाता था और आगरा में ट्रांसपोर्ट के जरिये ट्रान्जिट होता था। वहां पर एक भवन की तलाशी ली गई जिस्से कई सनसनी भेद जानकारी मिली है उस भवन में भूमिगत कमरे हैं। बैंक मिला है जो 12 फिट लम्बा और 8 फिट चौड़ा है। यह पता नहीं चल पाया कि यह किस प्रयोजन के लिये बना था। वहां पर खून की छीटें और कई दाग पाये गये हैं। यह तथ्य जांच में आई कि न जाने कितने लोग मारे गये थे। मधुबन नामक एक मजदूर वहां काम करता था जो बंधुआ मजदूर की तरह से काम करता था उसके बाहर एक घेरा बना था उसके बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। गुलाब सिंह नामक एक व्यक्ति मिला जो पूरी तरह मर नहीं पाया था उसको बेहोशी की हालत में बोरे में भरने की कोशिश कर रहे थे और वह कह रहा था मैं मरा नहीं हूं मैं जिन्दा हूं, मुझे मत मारो। उसने पुलिस के सामने सब तथ्यों का रहस्योद्धाटन किया है। पता नहीं किस-किस से वह सम्बन्धित है। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि बिक्री कर वाले जांच कर रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी फर्म है आगरा में जो जायेंगे देखेंगे कि कितनी वह दुकान चलती है लेकिन बिक्री कर 5 सौ रुपया पड़ता है। इनकमटैक्स वाले, बिजली वाले टेलीफोन वाले सभी उसकी जांच कर रहे हैं। एक षडयन्त्र हुआ ऐसे षडयन्त्र होते हैं, लेकिन इस षडयन्त्र में चिन्ता की बात यह है कि जो लोग पकड़े गये उन लोगों को बचाने के लिये सत्तारूढ़ दल के जिम्मेदार लोग शासन पर उनको बचाने के लिये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप मैं अपनी निजी जानकारी से नहीं कह रहा हूं बल्कि समाचार पत्रों में यह बात उजागर हो चुकी है। 3 मार्च को जिलाधिकारी श्री मुखर्जी ने यह जानकारी दी की काण्ड पर हर स्तर से दबाव डाला जा रहा है। 4-1-81 के अमर उजाला और स्वदेश में यह प्रकाशित हुआ है। वहां के जिलाधिकारी इस बात को कहते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जिलाधिकारी कोई बात कहे जो गलत हो तो उसका कंट्राडिक्शन सरकार की तरफ से क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। वहां के जिलाधिकारी ने यह बात कही तो उस पर कौन सी आगे जांच की गयी। जो लोग पकड़े गये हैं वह सत्तारूढ़ दल के एम0 पी0 के संबंधी हैं। आगरा बर्तन भंडार के मालिक सरदार सिंह की पुत्री आगरा के संसद सदस्य निहाल सिंह के भाई को ब्याही हुयी है। मान्यवर, वह उनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार होना कोई खास बात नहीं है, खास बात यह है कि लोग आये, लोगों को बुलाया गया और उन्होंने जिलाधिकारी पर दबाव डाला और जिलाधिकारी ने इसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

उजागर किया। मान्यवर, मैंने मांग की थी और आज फिर मांग करता हूं। इस केस में मैजिस्ट्रेट की जांच बैठा दी गयी है। लोकल मैजिस्ट्रेट इस स्थिति में क्या जांच कर सकता है? संपूर्ण देश में, चंडीगढ़, ग्वालियर, बंगलौर में इसका जाल फैला हुआ है। बड़े-बड़े सेना के अफसर आये हुये हैं। तो क्या मैजिस्ट्रेट जांच करके सही तथ्यों को सामने ला सकता है। यह बात सुनने में आयी है, कि उन्होंने जांच किया और जांच में इस बात को उजागर किया, समाचार पत्रों में भी छपा है कि बम मिले, राकेट मिले हैं, अब उसको दबाने की चेष्टा की जा रही है। आगरा के पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों को यह बताया है। समाचार पत्रों में आया कि बबीना छावनी से मिलिटरी का काफी सामान चोरी होकर तीन हाथों में बदल कर ग्वालियर में पहुंचता था। इससे संबंधित आगरा में एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। "अमर उजाला" में यह सब बातें छपने के बाद भी वहां पर कोई गंभीर कार्यवाही नहीं हुयी है। देवी दयाल स्टील कम्पनी और पालें स्टील बनाने की जो फर्म्स हैं इनकी जाली मुहरें भी वहां पर मिली हैं। यानी पूरा लंबा गिरोह फैला हुआ है। इसीलिये मैं साफ-साफ कह देना चाहता हूं, सरकार की ओर से रोज-रोज घोषणायें होती हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, दबा देंगे लेकिन इस घोषणा से जनता में, प्रशासन में भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है यह विश्वास नहीं पैदा होगा। यह विश्वास जब पैदा होगा जब सरकार के द्वारा प्रभावी कदम उठाये जायं। मैं इसी प्रसंग में एक घटना बता देना चाहता हूं। अभी मंशा राजपूत की एक घटना घटी, ढाई साल समय बीतने का बहाना लेकर एक आदमी को रि-इंस्टेट कर दिया गया। तो इस तरह भ्रष्टाचार सरकार के लोग करते चले जायंगे और आपकी सरकार में जो कार्य कुशल, कार्य निष्ठा, ईमानदार कर्मचारी हैं उनका गला घुटता चला जायगा तो सर्विसेज पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मुझे जानकारी मिली है, सत्ता पक्ष में बैठे हुये मंत्री जानते हैं, एक नियोजन विभाग का अधिकारी था, बड़ा कर्तव्य निष्ठ था, नियोजन विभाग में उसने अच्छा काम किया है 3 बार उसको हार्ट का अटैक होता, वह प्रार्थना करता है कि....

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

एक सदस्य---

आप इसी विषय पर बोलें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आगरा से संबंधित विषय पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य दूसरे विषय पर बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

उसने कहा कि हमको बदल दिया जाय। उसको छुट्टी दी गयी। वह एक अप्रैल से लागू होगी। परन्तु सरकार उसको लिये जा रही थी ट्रेन में वह मर गया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, माननीय सदस्य आगरा परेशान न हों, वह मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं कि वह जो कुछ कहेंगे ठीक कहेंगे। वह परेशान न हों। मैं चाहता हूं क्या इसी तरह काम किया जायगा, यदि इसी तरह काम किया जायगा तो जनता में आस्था उत्पन्न नहीं होगी, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। इस मामले में मेरा साफ आरोप है, सरकार जानबूझ कर इस मामले को दबा रही है, सत्तारूढ़ दल के प्रतिष्ठित राजनेता इस मामले को दबा रहे हैं। तो आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? कल दिल्ली से और आगरे से बहुत लोग आये थे। विधायकों में घूम-घूम कर कन्वेसिंग कर रहे थे कि इस मामले को न बढ़ाया जाय।

यह कौन लोग थे, इसको मैं बताऊंगा, पूरे तौर पर पर्दाफास करूंगा। इस तरह से भ्रष्टाचार और अराजकता के मामलों को जानबूझ कर दबाने के लिए जो भी प्रयत्नशील हो, मान्यवर, चाहे वह शासन से संबंधित हो, या कोई भी हो, उसे दण्डित किया जाना चाहिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय अध्यक्ष जी, जिस विषय पर आपने कृपापूर्वक चर्चा का समय दिया निश्चय ही वह मामला बहुत ही अपने आप में गम्भीर है और हमारी भी यही इच्छा थी कि इस पर चर्चा हो जानी चाहिए, ताकि सही रूप में सभी तथ्य सामने आ सकें। इसमें दो राय नहीं है कि 24 फरवरी को आगरा में बम विस्फोट हुआ एक आदमी के चिथड़े उड़ गये और एक जिन्दा आदमी को बोरे में बंद किया गया जो चिल्ला रहा था कि मुझे अस्पताल ले जाया जाय इसके 5 मिनट बाद ही वहां की स्थानीय पुलिस पहुंच गयी और 10 मिनट बाद आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सी0 ओ0, एस0 पी0 (सिटी), ए0 डी0 एम0 और डी0 एम0 वगैरह सभी घटना स्थल पर मौजूद थे। और उनके मालिकान जो वहां मौजूद थे, उनको हिरासत में ले लिया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और मालिकों की उसके बाद भी गिरफ्तारियां हुईं, व अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां हुईं। माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कुछ आरोप सत्ता पक्ष पर लगाये और कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, कुछ तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सबूत फौरी कार्यवाही का परिणाम और क्या हो सकता है कि मालिकान को फौरन पकड़ा गया और उन्हें मीसा के अन्तर्गत बंद कर दिया गया। सर्वश्री सरदार सिंह, नरेन्द्र सिंह और शेर सिंह आज भी मीसा के अन्तर्गत बन्द हैं। इससे बड़ा सख्त कदम शासन की ओर से और क्या हो सकता है। और यही नहीं श्रीमन् धारा 302, 304 और 307 और लगभग एक दर्जन अन्य दफाएं उन अभियुक्तों पर लगायी गयी और मान्यवर, यही नहीं मिलेट्री के अधिकारियों ने, सेल्स-टैक्स और इन्कम टैक्स के अधिकारियों ने भी छापे मारे। बहुत सी चीजें बरामद हुयी। बिजली के तार बड़ी मात्रा में बरामद हुये और टेलीफोन के तार बरामद हुये।

मान्यवर, जितना भी सम्भव हो सकता था, वह प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी। श्रीमन्, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई के संसद सदस्य उनके रिश्तेदार हैं इस ओर मेरी निश्चित जानकारी है, कि उनका कोई भी सीधा सम्बन्ध अभियुक्तों से नहीं है। और मान्यवर, यही नहीं मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि संसद सदस्य श्री निहाल सिंह के बारे में कहा गया कि वह इस मामले में दबाव डाल रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 24 फरवरी को यह काण्ड हुआ और पहली मार्च को माननीय सदस्य, श्री निहाल सिंह जी ने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को लिखा और एक पत्र श्री ज्ञानी जैल सिंह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार को लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस काण्ड में जो भी अभियुक्त दोषी पाये जाएं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इसके उत्तर में 7 मार्च को माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा श्री निहाल सिंह जी के पास उत्तर आ गया। तो मान्यवर, इससे बड़े सबूत और क्या हो सकते हैं?

श्रीमन्, राजनैतिक लांछन लगाना बड़ी आसान बात है। मेरी बात हो सकता है कि माननीय गुप्ता जी गलत समझें लेकिन श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से उन्हें कहूंगा कि वे पता लगा लें कि जनता पार्टी के शासन काल में आगरा में श्री लाल कृष्ण अडवानी गये थे तो उनके यहां ठहरे थे या नहीं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, यह प्रत्यक्ष आरोप है, उनका उनसे कोई संबंध नहीं है यह कई बार कह चुका हूं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल---

श्रीमन्, कांच के महल में रहने वाले दूसरों पर ईंटें नहीं उछाला करते। अपनी पार्टी के नेताओं से पता लगा लें, उसके बाद किसी सांसद के ऊपर कीचड़ उछालें। जमानत के लिये अभियुक्त जब कलेक्टरी और दीवानी जा रहे थे तो जनता पार्टी के आज के मौजूदा सांसद ने और भूतपूर्व सांसद उनके साथ थे। मौजूद सांसद और भूतपूर्व सांसद ने उनकी जमानत के लिये भी तोड़ कोशिश की। पहले वास्तविकता पता लगा लें, श्रीमन्।

मैं इसके साथ ही साथ माननीय गृह राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह बड़ा अहम प्रश्न हो गया है कि आज जो मसला उठा है उसमें हमारे आगरा के जिलाधिकारी कम दोषी नहीं हैं। उन्होंने 4 मार्च को बयान दिया जो जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने अपना गैर जिम्मेदाराना बयान देकर और उसके बाद गली मोहल्ले के छोटे-मोटे लोगों से बयान दिलवा दिया।

कई सदस्य---

उसने सही तथ्य प्रकाश में ला दिये तो यह गैर जिम्मेदाराना बात हो गयी आपके लिये?

श्री अध्यक्ष---

कृपया शान्त रहें और उनको सुनें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल---

जिलाधीश बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। आगरा के जिलाधीश रिटायर्ड मिलेटिरी मैन हैं। केन्द्र के गृह राज्य मंत्री, श्री योगेन्द्र सिंह मकवाना ने स्टेटमेंट दिया कि कोई भी महत्वपूर्ण घटना पर बयान न दिये जायं जब तक कि जांच की रिपोर्ट न आ जाय। लेकिन जिलाधिकारी, आगरा ने बिना परीक्षण के, परीक्षण की रिपोर्ट आने के पहले ही बयान दिया कि उसमें जीवित बम थे और एन्टी रैन्क वगैरह चीजें बरामद हुई हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

कृपया शान्त रहें और पहले उनको सुन तो लें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल---

उन्होंने बयान दिया और भी अस्त्र-शस्त्र मिले। तो जो कि मिलेटरी के रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके मुंह से ऐसा बयान शोभा नहीं देता। श्रीमन्, उसके बाद उन्होंने बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि उन पर दबाव पड़ रहा है, किसी राजनीतिक नेता का नाम उन्होंने नहीं बताया, यह कहा कि कुछ लोगों द्वारा उन पर प्रभाव डाला जा रहा है।

तो मैं श्रीमन्, माननीय गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि शासन की यदि छवि उज्ज्वल करनी है तो आज आप जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण लीजिये कि वे कौन से लोग हैं जो उन पर दबाव डाल रहे थे, इस बात को वे बतायें। अगर नहीं थे, तो उनको इसके लिये सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी चाहिए।

श्रीमन्, जितने भी प्रकार से हो सकता है, हर एजेन्सी से उनके खिलाफ जांच हो रही है, वे मीसा के अंदर बंद हैं, पुलिस ने अपनी चार्जशीट भेज दी, सेल्स टैक्स अपना काम कर रहा है। इसमें दो राय नहीं कि यह बहुत जघन्य कार्य हुआ। जो अभि-

युक्त पकड़े गये उन्हें चार हजार बोरी सीमेन्ट विगत 6 महीने के अन्दर आगरा पूर्ति विभाग से दिया गया। एक बड़ी अजीब बात लगती है कि चार हजार बोरी सीमेन्ट आगरा पूर्ति विभाग के ए0 डी0 एम0 ने सप्लाई किया और बिना किसी जस्टीफिकेशन के अपने डिसीजन पर दे दिया।

यही नहीं श्रीमन्, बिजली का बहुत सा तार, टेलीफोन का तार और जैसा माननीय विधायक ने बताया है नकली पारले देवीदयाल की मोहरें और तमाम चीजें पकड़ी गयीं, सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स नाम मात्र को देते थे और लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इससे संबंधित हों, ऐसे राष्ट्र द्रोहियों के साथ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये और उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाये और उत्तर प्रदेश की जनता को दिखा दिया जाये कि इस समय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में शासन ऐसे लोगों को कुचलने के लिये कटिबद्ध है। उनको किसी तरह से बख्शा नहीं जायेगा।

*श्री रियासत हुसैन---

जिस गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, माननीय डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल जी ने दो-तीन बातें कहीं, मैं पहले उनका एक मिनट में जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि कोई चिट्ठी, यह चार्ज लगाया कि वहां के किसी सांसद से इसका संबंध है तो उन्होंने जैल सिंह को लिखी थी, उसका एक्नालेजमेंट भी आ गया। बड़ी अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी ध्यान दें मुरादाबाद में 4 चांद वाली मस्जिद के संबंध में दो बार प्रधान मंत्री की चिट्ठी आ गयी मुख्य मंत्री के पास कि इस मामले में देखिये कि क्यों नहीं अब तक उस मस्जिद का मामला हल हुआ लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ तो जैल सिंह की चिट्ठी की हैसियत क्या है...

(व्यवधान)

दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि लाल कृष्ण अडवानी जी वहां ठहरे थे जो श्रीमन् जून, 78 के बाद आपकी सरकार थी, आपकी इन्टेलीजेन्स थी, आप क्या कर रहे थे, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आप की सी0 आई0 डी0 क्या कर रही थी? अगर वह जगह इतनी खतरनाक थी तो विस्फोट के पहले उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि उस डी0 एम0 का, मुझे मालूम नहीं था कि वह मिलिटरी मैन है। मिलिटरी सर्विस में हर आदमी नेशनलिस्ट, हर आदमी डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल होता है और उसके संस्कार में यह है कि वह किसी भी राजनीतिक दबाव में न आकर कार्य करे। सत्य को सामने रख दिया। वह काबिले बधायी है।

श्रीमन्, मैं इस मामले की तरफ आता हूं। मेरी समझ में यह नहीं आता है, मैं समझता हूं कि ऐसा काण्ड है यह जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी है और ऐसी चीज है जिसकी वजह से यह हमारे प्रदेश के परव्यू में नहीं आता। और उसकी इन्क्वायरी, जैसा कि अभी बताया गया, डाक्टर कौशल ने बताया, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, बिजली वाले, टेलीफोन वाले भी कर रहे हैं, आपकी पुलिस भी कर रही है और कुछ इंक्वायरी के लिये मिलिटरी के लोग भी आये थे तो निश्चित ही इन सारी इंक्वायरी में आप के प्रदेश के बाहर बहुत सी चीजें चली जाती हैं तो क्यों नहीं सी0 बी0 आई0 के हवाले इस को कर देते। उसमें सारी बातें सुलझ जायेंगी और सब चीजें सामने आ जायेंगी। आप एक मजिस्टीरियल इन्क्वायरी क्यों करा रहे हैं। आपका कहना कि उसमें डी0 एम0 ने वहां के एक गलत काम किया था, सही बात को कह दिया प्रेस वालों से तो क्या यह जुर्म किया, पाप किया कि सच बात कह बात को कह दिया प्रेस वालों से तो क्या यह जुर्म किया, पाप किया कि सच बात कह दी? क्योंकि सच बात आप को कड़वी लगती है। आपसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन--]

बर्दाश्त हुई नहीं सच बात तो आप उसकी इन्क्वायरी दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब से करवा रहे हैं। उसने सच क्यों कह दिया और वह कितना दोषी है उसकी आप मैजेस्टीरियल इन्क्वायरी करवा रहे हैं। इससे स्पष्ट यह नतीजा निकलता है कि जो काण्ड हुआ जैसा काण्ड हुआ कि बम मिला, दुनिया की चीजें जो सामने आ रही हैं उसकी जानकारी आपके लोकल एल0 आई0 यू0, लोकल पुलिस और इन्टलीजेन्स की निगाहों से छिपी रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यह साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि उन्होंने तथ्यों को छिपाया तो आप पहले उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। उनको वहां से निकालकर बाहर कीजिए। यह बात सही है कि उसके अन्दर कुछ पोलिटिकल लोगों का हाथ है, संरक्षण है। आप जानते हैं कि ऐसा आदमी बहुत चतुर होता है, होशियार होता है, जिसकी चलती है वही कश्ती पर बैठता है। आज तो जिम्मेदार इस मा0 सदन के, देश और प्रदेश की जनता के आप हैं। आपने जब जिम्मेदारी संभाली 9 जून को तो उसके बाद 24 फरवरी को यह काण्ड, विस्फोट हुआ तो आपकी सरकार क्या करती रही, आपके इन्टेलीजेन्स वाले क्या कर रहे थे? इसका जवाब तो आपको देना चाहिए और आप इसलिये इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि जो जून 80 के बाद में आए हैं उनकी, वे राजनीतिक तत्व उसके पीछे हैं, उसकी मदद में हैं, उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सी0 बी0 आई0 किसी का रिश्तेदार नहीं है। न जनता पार्टी का, न हमारा, न आपका। सी0 बी0 आई0 सबसे बड़ी ताकत है आप उसके सुपुर्द कर दीजिए, मामला सब सामने आ जायेगा। आप अपने ऊपर बोझ मत लीजिए। आपने जो कहा कि रिश्तेदारी नहीं है तो आप नाक सीधे मत पकड़िये। यूं पकड़िये (हाथ के इशारे से दिखाया गया)। नाक तो हाथ में आ ही जायेगी चाहे जैसे पकड़ा जाय।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, आगरा के मोती कटरा में जो दिनांक 24-2-81 को बम विस्फोट हुआ था, उस सम्बन्ध में मुझे भी कुछ ज्ञात हुआ है और वह मैं इस माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, जिनकी कोठी में यह तहखाना है और जिसके अन्दर यह हुआ है, वह अगर आपको या जिनको बम या कारतूसों के बारे में जानकारी होगी, उन्हें ज्ञात होगा, वह फौज के पुराने बम के खोल और कारतूसों के पुराने खोल हैं। उसको नीलामी के द्वारा खरीदने का काम यह करते रहे हैं। आपको मालूम होगा कि यह पुराने कारतूस जो मिसफायर कर जाते हैं अगर उन्हें थूक लगाकर चालू कर दें तो चालू हो जाता है इसलिए हो सकता है कि फायर हो गया हो लेकिन यह कहना मान्यवर कि यह बहुत बड़ी घटना है, अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र है, कोई बहुत बड़ा गिरोह है, फौज का हाथ भी रहा है और जो मिलकर इस काम को कर रहे हैं, वह यकीन में आने की बात नहीं है। यह बात तो मैं मानने को तैयार हूं कि इसमें जो लोग हैं वह बहुत बड़े गिरोहबन्द आदमी हैं, चोर हैं डाकू हैं, बदमाश हैं। लेकिन यह कहना कि हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, हमारी फौज उन को संरक्षण दे रही है, या पूरी तरह से जांच नहीं हो रही है, गलत है। इस को संक्षेप में आप के सामने रख दूं। ज्यों ही घटना घटित हुई कुछ मिनटों के अन्दर हमारी पुलिस पहुंच गयी। पुलिस पहुंचने के थोड़ी देर बाद मिलिटरी वहां पहुंच गयी। घेरा डाला। और मान्यवर, जो अभियुक्त है वह बहुत बड़ा चोर है, यह भी मान लिया कि बहुत बड़ा डकैत है। लेकिन वहां के ईमानदार एस0 एच0 ओ0 ने कोई रिश्वत नहीं ली और उस की जमानत नहीं की। जिस गुलाब मजदूर की माननीय राजेन्द्र जी गुप्त ने बात की, कि वह अपना दम तोड़ रहा था, उस को थैले के अन्दर बंद कर दिया था, आगरा की पुलिस ने तुरन्त ही जा कर, मान्यवर, उस पर कब्जा किया, उस को बचा लिया और उसके बयान निजाई यानी डाइंग डिक्लेरेशन लिये। क्या यह सबूत नहीं है कि पुलिस कितनी कार्यकुशलता से, प्रशासन कितनी कार्य कुशलता से काम कर रहा है। उस के बाद

उस के ऊपर कितनी धारायें लगायी गयीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि कितनी धारायें लगाई गईं और बाद में धारा 382 कर दी गई थी, जब मजदूर मर गया। आप ने यह कहा कि मजदूर चिल्ला रहा था। "बाबू जी मत मारिये चिल्ला रहा था। सेठ जी मुझे मत मारिये" कह रहा था। लफ्ज जो सेठ जी कहा था। वहां सी0 जे0 एम0 की अदालत है उस ने जमानत नहीं ली। वहां के जिला जज ने, शायद वह अब हाई कोर्ट चले गये हैं, जमानत नहीं ली। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वह अभियुक्त बंद है। अब बताइये कहां पर इस में सेना इनवाल्व है, कोई बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह इस में कहां शामिल है, कितनी अच्छी तरीके से वहां पर काम चल रहा है, मैजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी चल रही है, कोई परेशानी, कोई भय व्याप्त नहीं है। बिला वजह सदन को गुमराह करना यह भी अच्छी बात नहीं है।

*श्री बदन सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आप ने इस अहम मसले पर चर्चा के लिये आज्ञा दे दी इस के लिये मैं आप को बधाई देता हूं। लेकिन सरकारी पक्ष की तरफ से जो यह कहा जा रहा है कि भिन्न-भिन्न विभाग और आय कर विभाग सचेत है। मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह सब विभाग सोते रहे, निष्क्रिय रहे। जब तक रक्त रंजित घटना नहीं हुई तब तक यह गुप्तचर विभाग कहां गया था, बिक्री विभाग कहां गया था, आयकर कहां गया था। किसी को कोई पता नहीं। इतनी बड़ी घटना हुई कि जिस वक्त यह बम का विस्फोट हुआ, जिस गोदाम में यह विस्फोट हुआ, उस का अग्रिम भाग ही उड़ गया था। तो यह शासन की विभिन्न एजेंसियां सोती रहीं। यह जिलाधिकारी, आगरा की तरफ से स्पष्ट बयान है 4 तारीख को, मैं उस में पढ़े देता हूं..

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

गुप्ता जी ने पढ़ दिया...

श्री अध्यक्ष—

इस को पढ़ा है उन्होंने..

श्री बदन सिंह—

आप ने कहा कि..

श्री अध्यक्ष—

यह पढ़ दिया गया है..

श्री बदन सिंह—

जब से यह घटना हुई तब से इस घटना को बराबर दबाया जा रहा है। जो रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी था उस पर दबाव डाला गया, एक धनी पार्टी ने उस को पचास हजार रुपये देने का प्रलोभन दिया लेकिन उस छोटी तनख्वाह पाने वाले सब इंस्पेक्टर ने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं घटना की एफ0 आई0 आर0 302 में दर्ज करूंगा। और उस थानेदार को जो इनाम दिया गया वह भी मैं आपको बता देता हूं कि उसे पिथौरा थाने में ट्रांसफर कर दिया गया जहां कि पीने के लिये भी पानी नहीं मिलता है। इतना ही नहीं आज यह कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का षडयंत्र नहीं चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि विभिन्न कमरों में 84 बोरे गोला बारूद की सामग्री प्राप्त हुई और वह अभी बंद पड़ी हुई है। 3 मार्च को कालिरहा ग्राम में एक आगरबाग में ताजगंज थाने के अन्तर्गत 4 किलोमीटर दूर मिलीटरी फायरिंग रेंज के निकट स्थित 2 बम व 6 पलीते बरामद हुये। जब उनका पानी में परीक्षण किया गया तो जोर का धमाका हुआ और चारों तरफ आवाज हुई। इसी 19 व 20

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बदन सिंह—]

मार्च की रात्रि के 10 बजे खैराती टोला के पक्के नाले की झाड़ियों से एक बोरी भरे विस्फोटक सामग्री पायी गई। उसे मैं स्वयं देखकर आया हूं। इनमें 6 बम के खोके जिन पर काले रंग में एम0 एम0 आई0 एल0 एल0 0545 लिखा हुआ था। 25 अलम्यूनियम की पंख नुमा फिरकें, जिनके सुराख कटे हुये थे तथा एक चूड़ी कटी साकट नुमा वस्तु तथा 8 प्लेट अलम्यूनियम की मिली। मैं यह सामग्री 20 तारीख को ताजगंज थाने में देखकर आया हूं। अब मैं यह बताता हूं कि किस तरह से इस सामग्री की सूचना पुलिस को दी गई। जब तीन आदमी उसको किसी झाड़ी में छिपा रहे थे तो कुछ बच्चों से वहां जाकर देखा कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने लोकदल के कार्यकर्ताओं को सूचना दी। पुलिस ने वास्तविकता को छिपाया और सूचना देने वालों का नाम रिपोर्ट में दर्ज नहीं करवाया। मान्यवर, यह बहुत बड़ा काण्ड हुआ है जिसका कि रक्षा मंत्रालय से संबंध है। जो रक्षा मंत्रालय का दल वहां पर आया तो उसने भी स्वीकार किया है कि वह सेना में प्रयोग होने वाली सामग्री प्राप्त हुई है। जो कि आगरे में फायरिंग रेंज में प्रयुक्त होने वाली मिलिटरी की सामग्री है जो कि वहां से चुराकर लायी जाती है।

एक बात यह कही गई कि जिलाधिकारी आगरे ने सेना के अधिकारी के आने से पहले रिपोर्ट दे दी। उनका जिलाधिकारी पर विश्वास नहीं है। जो मजिस्टीरियल जांच की गई उसके विषय में एस0 डी0 एम0 आगरा द्वारा करायी गई है लेकिन वह भी तो जिलाधिकारी के अधीन काम करने वाले हैं। तो मान्यवर, यह ऐसा मामला है जो रक्षा मंत्रालय के विभिन्न प्रकार के गोलाबारूद से संबंध रखता है इसलिये मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि आप इसकी जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा करायें। एक साथ ही मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, 3 अपराधी जो फर्म के मालिक थे उनको मीसा के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया और सजा दी गई। वे हैं सरदार सिंह, सुरेन्द्र सिंह, और शेर सिंह। उनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में बंद किया गया लेकिन इस अपराध के आरोप में बंद नहीं किया गया और उनको अस्पताल में रखा गया है। अभी तक इस केस को दबाने के लिये शासन पार्टी के एक माननीय सांसद बराबर दबाव डाल रहे हैं। आज आगरा की जनता में भय व्याप्त है न जाने कितनी ऐसी सामग्री विभिन्न इलाकों में धनी लोगों के गोदामों में और उनके कारखानों में छिपी पड़ी है। तो मैं यही कहूंगा कि यह शासन बिलकुल असफल रहा है यह बात जनता में साफ हो गयी है। प्रदेश और देश के लोग जानने के लिये आतुर हैं कि यह सामग्री आगरा पीतल भंडार के पास कहां से पहुंच गयी और किन सूत्रों से पहुंच गयी।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, काफी बहस इस पर हो चुकी है, मैं दो तीन मिनट ही लूंगा। हमारे डा0 कौशल जी ने एक बात कही जो अभियुक्त है उसके यहां जनता पार्टी के नेता खाने के लिये पहुंचे थे। आपने यह भी कहा कि कोई ए0 डी0 एम0 सिविल ने 4 हजार बोरी का चपला किया जिसके लिये ए0 डी0 एम0 के लेवल के अधिकारी जांच कर रहे हैं। तो दोनों ए0 डी0एम0 हैं। फिर डी0 एम0 के बारे में भी आपने थोड़ा सा लांछन लगाया। एक माननीय सदस्य ने तो साफ कर दिया कि वह खाली खोखों का व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार अभियुक्त की तरफ से सफाई भी आ रही है। दूसरे सदस्य कहते हैं कि उनका जनता पार्टी के लोगों से संबंध है। तो सभी विपक्षी सदस्य सरकार से मांग करते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां हैं ए0 डी0 एम0 4 हजार बोरी दे रहे हैं और डी0 एम0 ने भी गलत बयानी की और अभियुक्त भी जो हैं जनता पार्टी से संबंध रखते हैं तो इसमें कौन सी शर्म आपको लग रही है, कौन सी हिचक हो रही है कि उसकी सी0 बी0 आई0 से जांच करा लें। आप कहिये कि सी0 बी0 आई0 से जांच करायेंगे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हमें भी मौका मिलेगा जवाब देने का..?

श्री अध्यक्ष--

बहुत बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

स्पष्टीकरण के तौर पर एक मिनट चाहता हूं। मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने इस मामले को इतना घटा देने की कोशिश की जैसे केवल चोरी का मामला हो और वहां नीलामी हुआ करती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं क्या यह सही नहीं है कि मिलिट्री के कारतूस जो हैं वह दबा कर बेचे जाने चाहिए क्या यह सही नहीं है कि उस जखीरे में जो कारतूस मिले हैं वह बिना दबाये हुए हैं। तो इससे जाहिर होता है कि मिलिट्री के लोग इसमें इनवाल्व हैं।

दूसरी बात कौशल साहब ने कही उन्होंने डी0 एम0 पर आरोप लगाया। तो डी0 एम0 ने कौन सी गलत बात की तो उन्होंने आरोप लगाये हैं उसकी इनक्वायरी कीजिये, जो उनके आरोप हैं उनके पीछे कौन से लोग हैं जिन्होंने दबाव डाला। तो वह बतायेंगे जिससे बात साफ हो जायेगी। इसमें डी0 एम0 का क्या अपराध है। वह एक एक्स मिलिट्रीमैन हैं उन्होंने अपने अनुभव की बात कही है जो जानबूझ कर कही है। वह खोल के अंदर जिंदा थे क्योंकि वह अनुभव सिद्ध आदमी हैं। मैंने जिलाधिकारी का हवाला दिया और एक सांसद पर आरोप लगाया लेकिन माननीय सदस्य ने हमारे नेता सांसद अडवानी जी पर आरोप लगाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह बतायें कि कौन तारीख थी और कौन सा मौका था। मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर वाक स्वतंत्रता का लाभ उठा कर कोई बात कहें तो उसकी हम निन्दा करते हैं। अन्यथा वह तारीख और मौका बतायें उसकी पूरी जानकारी दें। मैं अंत में मांग करता हूं कि इस सारे मामले की जांच सी0 बी0 आई0 से करायें। (व्यवधान) यह सी0 बी0 आई0 को लेकर चर्चा हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय सदस्य बैठें, अब चर्चा समाप्त होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन की इस घटना के बारे में जो चिन्ता है, उस चिन्ता में शासन ने जिस गम्भीरतापूर्वक इस विषय को लिया है और उसके साथ-साथ उसमें जो कार्यवाहियां की हैं, उसकी ओर मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने प्रारम्भ से ही शंका प्रकट कर दी और पता नहीं क्यों वह बार-बार शंकालु मन बना रहे हैं और शंकालु मन जब कभी किसी भी चीज को देखता है, तो उसके मन की जो पूर्व भावना है, उसके अनुरूप ही वह हर चीज को देखता है, देखने लगता है। हमारे यहां की देहात की अवधी भाषा की एक कहावत है--दाई जाने अपन नाई, यानी जो जैसा होता है, उसी प्रकार की वह दूसरों के बारे में शंका करने लगता है। (व्यवधान) मैं एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूं, मुझे पहली बार लगा कि आगरा का असर माननीय रियासत साहब तक पहुंचा है। यहां तक पहुंचा है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं कि जिनसे हमारी समझ में आने लगा कि वह विषय से विषयान्तर कर दिये हैं और वह आगरा के असर में हैं। मान्यवर, वह बोल रहे थे आगरा बम-विस्फोट पर और बोलने लगे मुरादाबाद के बारे में। तो मैं माननीय धर्मपाल जी से कहूंगा कि वह उसका अवश्य कोई जोरदार इलाज करें..(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धरमपाल--

मंत्री जी स्पष्ट बताएं कि राज्य गृह मंत्री ने अपराधियों की सिफारिश में कोई फोन किया था या नहीं?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं इसमें भी कहना चाहता हूं। जहांतक स्थिति दो-तीन चीजों के बारे में है, राजेन्द्र कुमार गुप्त ने चर्चा की और उनकी यह चर्चा करने के बारे में लगा कि उनपर राज नेताओं का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने उद्धरण एक समाचार-पत्र का प्रस्तुत किया है और उन्होंने उस अधिकारी को ऐसा कहते हुए उद्धृत किया है। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपकी पीठ से ही निर्णय हो चुका है कि समाचार पत्रों में जब कभी कोई सूचना निकलती है तो उसको यहां उसका पूर्ण रूपेण साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। मैंने शासन की ओर से आपकी भावना को समझते हुए जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है, वह इस बात को बतावें कि यह कहां तक सही है...

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

उल्टे चोर कोतवाल को डांट रहा है। क्या वह स्पष्ट डिक्लेरेशन करेंगे कि सी0 बी0 आई0 से इसकी वह जांच करायेंगे, वरना...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आज मैं रियासत साहब की बात सुनते हुए, अपनी पूर्व बात को ध्यान में रखते हुए, वह कुछ भी कहते हैं तो उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसलिये इस बारे में सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट भी...

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

हम लोग आपसे यह बात सुनने के लिये यहां नहीं बैठे हैं, यह सब आप लोकपति जी को सुनायें। आप सी0 बी0 आई0 की जांच की घोषणा नहीं करते हैं तो हम सदन का त्याग करते हैं।

(रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्यागकर चले गये)

श्री हुकुम सिंह--

आप सी0 बी0 आई0 इन्क्वायरी नहीं कराना चाहते तो इसको सुनने से क्या फायदा।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

सिद्दीकी साहब की आज चर्चा यहां कैसे आ गई। राजेन्द्र कुमार गुप्त अगर उनकी चर्चा करें तब तो उनकी अन्तर्भावना मैं समझता हूं, लेकिन शासन की नीयत उस वक्त साफ थी और आज भी साफ है और जो विभागीय जांच हो रही है, उसमें कोई बात आती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में शासन को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप गलत समझे। एक कर्मचारी को छुट्टी न देकर उसको मरवा डाला। मैं यह आरोप लगा रहा था।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

शासन के द्वारा जानकारी करने पर भी अभी तक कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं कि पत्ता रूढ पार्टी का...

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूं कि क्या वे सी0 बी0 आई0 की जांच बैठा रहे हैं? यदि नहीं बैठा रहे हैं तो उनकी बात नहीं सुनेंगे और सदन का त्याग करते हैं।

(श्री मोती लाल देहलवी अपने दल के सदस्यों सहित नारे लगाते हुए सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यदि माननीय मंत्री जी सी0 बी0 आई0 की जांच कराने को तैयार नहीं हैं तो हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ नारे लगाते हुए सदन त्याग कर चले गये)

(श्री विद्यासागर नौटियाल भी सदन त्यागकर चले गये)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि किस प्रकार से अपने मन की दुर्भावनाओं को प्रकट करने के लिये माननीय सदन के कीमती समय का दुरुपयोग करते हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिये माननीय सदस्यों ने कुछ इस प्रकार के तथ्यों की ओर आकर्षित किया है जो कि लोकतंत्र की परम्पराओं के विरुद्ध है और चाहे वे विरोध पक्ष के हों उनको शोभा नहीं देती है। यह बात सत्य से परे है कि सत्ता रूढ़ पार्टी का कोई भी नेता चाहे वह विधायक हो या चाहे वह संसद सदस्य हो या और कोई दूसरा व्यक्ति हो उन्होंने किसी प्रकार से इस इन्क्वायरी पर कोई दबाव डाला हो। उत्तर प्रदेश का शासन श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में चल रहा है और माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की भावनाओं का आदर करते हुए सदैव ऐसे कृत्यों पर कठोर कदम उठा रहा है जैसे कि 3 मार्च को 3 अभियुक्तों को एन0 एस0 ए0 में बंद कर दिया गया है।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल ने 2-3 चीजें कहीं। आपने कहा कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाय। मैंने पहले ही कहा है कि स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। दुबारा भी हम रिमाइन्डर भेज देंगे। एक बात यह कही गयी कि वहां पर ए0 डी0 एम0 ने किसी अभियुक्त को 4000 बोरों के सीमेंट के परमिट दिए हैं। उसकी भी जानकारी करायी जायेगी और अगर यह बात किसी सीमा तक साबित होगी तो उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी अगर यह पाया गया कि उसने जायज काम नहीं किया है।

बदन सिंह जी ने हर काम के लिये अपना सारा समय अपने लोक दल के लोगों का नाम लेने में ही दुरुपयोग किया है और कहा कि लोक दल के ही लोगों ने सूचना दी। यदि उन्होंने सूचना दी होती तो उनके नाम लिखे होते कि लोक दल के लोगों ने सूचना दी थी ताकि वे अपने नेताओं को कहते कि हमने उनके नाम लिखवा दिए हैं।

माननीय नेता विरोध दल ने सफाई देने की बात कही. वे इस समय सदन में नहीं हैं। सफाई उस पक्ष की ओर से आयी। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा कि कुछ लोग दिल्ली से आये। हो सकता है कि उधर से आये हों। इसलिये सफाई दी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी का दृढ़ संकल्प है कि कोई कोताही नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और 30 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 36 मिनट पर सोमवार, 30 मार्च, 1981 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
28 मार्च, 1981।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सदस्य पुस्तिका